<u>हिमाचल प्रदेश विधान सभा</u>

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त, 2018 को अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल, अध्यक्ष की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा, कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

28/08/2018/1100/RG/YK/1

प्रश्न सं.507

अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार कश्यप जी ने श्री बलबीर सिंह वर्मा को प्राधिकृत किया है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति उप-योजना का पैसा हर चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्यों के लिए बहुत सी स्कीमों में जाता है और इस उप-योजना की कोई भी स्कीम चाहे पानी की हो, स्कूल की बिल्डिंग या सड़क हो, उसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा जाने के कारण कोई भी स्कीम कम्पलीट नहीं हो पाती ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति उप-योजना की स्कीमें हैं, इनको विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत भी लाएं। विधायक एक-दो स्कीमें हर चुनाव क्षेत्र में, स्कूल, सड़क एवं पानी के लिए ऐसे प्राथमिकता में लाएं जिससे कोई-न-कोई स्कीम तो कम्पलीट हो सके। नहीं तो, अनुसूचित जाति उप-योजना की अधिकतर स्कीमें अधूरी ही रहती हैं और विभाग अपनी इच्छा से ही इस पैसे को इधर-उधर करते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदया से यही आग्रह है।

अध्यक्ष : प्राधिकृत माननीय शहरी विकास मंत्री।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जितना फण्ड एस.सी.एस.पी. में आता है, यह सही है कि यह अलग-अलग विभागों में अलग-अलग स्कीम में दिया जाता है। इसमें बस स्टैण्ड, आई.पी.एच. की किसी स्कीम, स्कूल की बिल्डिंग इत्यादि में इसका अपना शेयर हो सकता है। तो अलग-अलग जगह पर यह पैसा दिया जाता है जहां यह सैंक्शन होती है। लेकिन इसमें भी जैसे हमारी विधायक प्राथमिकता है, उसी के अनुरूप विधान सभा क्षेत्रों से ही कार्य की मांग आती है और विभाग उन्हीं पर कार्य करता है। कुछ ऑन गोइंग स्कीम्ज हैं, जैसे पूर्व विधायक ने कोई स्कीम दी होगी या वर्तमान विधायक ने जो स्कीम ऐड ऑन की होती है, उसके अनुरूप बजट के अनुसार उसी पर कार्य होता है। क्योंकि वैसे विभाग स्कीम्ज में, जैसे एक सड़क अगर हमने एस.सी.एस.पी. कम्पोनेंट से बनानी शुरू की, तो

उसको अगले साल विधायक प्राथमिकता में डालकर बहुत सारे विधायक तो लोक निर्माण विभाग में सीधे तौर पर ले आते हैं या एस.सी. कम्पोनेंट द्वारा सड़क बन जाती है या वह

28/08/2018/1100/RG/YK/2

कोई स्कीम बनाता है, तो फिर वह विभाग को ही ट्रांसफर हो जाती है, उसके अधीन आ जाती है। माननीय सदस्य ने अलग-अलग स्कीमों में थोड़ा-थोड़ा पैसा देने की बात कही है, जितना बजट होता है क्योंकि

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

28/08/2018/1105/MS/YK/1

प्रश्न संख्याः 507 क्रमागत---
श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी-----

अगर आप देखें तो स्टेट में वर्ष 2018-19 में 3901 वर्क्स चल रहे हैं। यह फिगर वर्ष 2018-19 की है। जो स्टेट में इतने ज्यादा काम चल रहे हैं ये अलग-अलग विभागों के हैं और विभागों की बजट एलोकेट करने की अपनी जिम्मेवारी रहती है। अनुसूचित जाति उप-योजना के पास जितना पैसा है उसको हम देते हैं। जहां तक आपने पच्छाद का प्रश्न किया है, इसमें टोटल 83 वर्क्स सैंक्शंड हैं जिनमें से 57 पर काम शुरू हुआ है तथा 14 पूरे भी हो गए हैं। इसके अलावा 53 कार्य प्रगति पर हैं तथा 26 कार्य ऐसे हैं जिनमें जैसे कहीं पर फॉरैस्ट की क्लीयरैंस नहीं आई या कहीं जमीन का झगड़ा है या कन्सर्न्ड डिपार्टमैंट से अनुसूचित जाति उप योजना के ऐस्टीमेट्स नहीं आए, तो ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से 26 कार्य अभी लम्बित हैं। इसी तरह से अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों से अलग-अलग विधायकों के काम है। इसमें थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है लेकिन बजट के अनुसार हम इसमें पैसा देते हैं।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति उप-योजना में बहुत सी सड़कें सभी विधान सभा क्षेत्रों में डाली गई हैं और जब हम विभाग से बात करते हैं तो बहुत सी सड़कों में दिक्कत यह आ रही है कि हमारा 10 परसेंट पैसा उन सड़कों में होना चाहिए लेकिन 10 परसेंट पैसा न होने के कारण उन सड़कों को एन0डी0एस0 के लिए नहीं भेजा जाता और उनकी डी0पी0आर्ज0 नहीं बनाई जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन स्कीमों में 10 परसेंट पैसा नहीं दिया गया है उन स्कीमों की डी0पी0आर्ज0 बनाने के लिए, एन0डी0एस0 लेने के लिए क्या आप विभाग को आदेश देंगी?

दूसरा मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि हमारी बहुत सी सड़कें और स्कीमें ऐसी हैं जो भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं बन पा रही हैं। इस विषय को हमने एक-दो बार पहले भी रखा था कि जो स्कीमें हमने डाली हैं उनको फॉरैस्ट लैंड के कारण या लैंड न मिलने के कारण नहीं बनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा

28/08/2018/1105/MS/YK/2

कि उन स्कीमों को प्रायोरिटी पर चेंज करे ताकि वे स्कीमें बन सकें। तो क्या माननीय मंत्री जी उन स्कीमों को चेंज करने के भी आदेश विभाग को देंगी?

अध्यक्षः वैसे तो यह पच्छाद विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। यदि माननीय मंत्री जी आपके पास उत्तर है तो दे दीजिए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, जिला स्तर पर बनी कमेटियों में स्कीमें कम्पलीट होती हैं और कुछ जिलों में इन कमेटियों की मीटिंग भी हो गई है। वहां पर यदि चेंज करना है या अन्य कुछ करना है तो विधायक इसमें स्पेसिफिक बता दें कि किन-किन स्कीमों को चेंज करना है। जब जिला स्तर पर कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें स्कीमों की पूरी समीक्षा होती है और वहां पर आप सभी विधायक सदस्य हैं। हरेक विधायक उस कमेटी की मीटिंग में जाए और वहां अपनी बात रखे कि क्या चेंज करवाना है। उसके अनुसार विभाग उन स्कीमों पर विचार करेगा। वैसे हमने ई-समीक्षा भी शुरू की है ताकि स्कीमें कम्पलीट हो सकें। अभी विभाग ने जो ई-समीक्षा शुरू की है आप उसमें देखें। जो 10 परसेंट ओवरऑल

बजट की बात कही है, इस पर संबंधित मंत्री या सरकार विचार करेगी कि इस पर क्या हो सकता है।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, पीछे जनवरी में जब मुख्य मंत्री जी ने विधायकों के साथ प्लानिंग की बैठक की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति उप-योजना की जितनी भी स्कीम्ज होंगी उन्हें विधायक प्राथमिकता में जोड़ा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई हुई है क्योंकि अभी तक हमारे से ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं मांगी गई है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी यदि आपके पास उत्तर है तो दे दीजिए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी अवगत करवाया कि ये अपनी बात जिला स्तर पर बनी कमेटी में रखें। विधायक प्राथमिकता अलग है।

28/08/2018/1105/MS/YK/3

अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत जो ऑन-गोईंग स्कीमें हैं उनको हटाना भी उचित नहीं रहेगा, चाहे वे आपके विधान सभा क्षेत्र की स्कीमें हों। जो ऑन-गोईंग वर्क्स हैं जिनमें विभाग का कुछ पैसा लगा हुआ है वे चलते रहेंगे।_विधायक जिला स्तर पर बनी हुई कमेटियों में अपनी बात रखें, फिर उसमें विचार कर सकते हैं।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा----

28.08.2018/1110/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 507ः-----**जारी**------

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)ः अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी कोई 40 सड़कें हैं जिनका काम एस0सी0 सब प्लान में हो रहा है। थोड़ा-थोड़ा पैसा हर

सड़क को दिया जाता है। मेरा माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिन सड़कों का काम 90 प्रतिशत हो गया है, 80 प्रतिशत हो गया है और 70 प्रतिशत हो गया है क्या उन सड़कों को प्राथमिकता दे कर पूरा करने के आप आदेश देंगे ताकि कुछ न कुछ रिजल्ट ग्राउंड में नज़र आए?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि कमेटियों की मीटिंग्ज का मतलब ही यह होता है कि अगर आप अपनी एक स्कीम में, क्योंकि पैसा तो उतना ही है, चाहे आप उसे 10 स्कीमों में बांट लें, आप यहां पर 40 सड़कें कह रहे हैं लेकिन यहां पर कुछ विधान सभा क्षेत्रों में 70-70, 80-80 एस0सी0 कम्पोनेंट में स्कीमें चल रही हैं। इसमें पैसा तो उतना ही रहेगा लेकिन उसके आप विभाग को अपनी प्राथमिकता दें और जो स्कीम आप कम्पलीट करवाना चाहेंगे उस पर जरूर विचार करेंगे।

28.08.2018/1110/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 677

श्री बलवीर सिंह (चिन्तपुरनी)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि JICA के माध्यम से यह जो 5.50 करोड़ रूपए का प्रावधान होगा यह किस मद में खर्च होगा तथा कब तक मन्जूर हो करके काम शुरू किया जाएगा?

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि यह किस मद में खर्च होगा इसमें Japan International Cooperation Agency से हमने सेकिण्ड फेज़ में 5.50 करोड़ रूपए का प्राजैक्ट तैयार करके भेजा है। इस

प्रोजैक्ट की स्वीकृति भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से मिल चुकी है। इसमें 1 हजार 9 करोड़ रूपए सम्भवतः इसी साल हमें JICA का सेकिण्ड फेज़ मिलेगा। जैसे ही स्वीकृति मिलती है, हम 5.50 करोड़ में से 25 दुकानों का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ रूपया खर्च होगा। हम किसान भवन का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें कार्यालय व चौकीदार का कमरा भी है उसमें 50 लाख रूपया खर्च होगा। नीलामी मंच में 1 करोड़ रूपया खर्च करने जा रहे हैं। बाउंडरी वॉल और रिटेनिंग वॉल पर 60 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। पब्लिक टॉयलैट पर 10 हजार रूपया खर्च करने जा रहे हैं। इसमें एक कल्वर्ट भी लगने वाला है उसमें 15 हजार रूपए खर्च होंगे। वहां पर एक यार्ड बनने जा रहा है उस पर 80 लाख रूपया खर्च होगा। बोरवैल टैंक बनाने जा रहे हैं उसमें हम 80 लाख रूपया खर्च करने जा रहे हैं। वहां पर एक ड्रेन ज़ोन बनना है उसमें लगभग 80 लाख रूपया खर्च करने वाले हैं। यह टोटल 5.50 करोड़ रूपया बनता है।

28.08.2018/1110/जेके/एजी/3

प्रश्न संख्याः 678

श्री पवन कुमार **काजलः** माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यह ठीक है कि कांगड़ा शहर में सत्र न्यायालय नहीं है। लेकिन वहां पर जो लोअर कोर्ट है उस बारे में मेरा मकसद यह है कि उस लोअर कोर्ट ने वहां पर कुछ साइलैंट ज़ोन एरिया बताया है। माता बज्रेश्वरी में जो श्रद्धालु आते हैं वे कई बार जयकारा लगाते हुए आते हैं और कई ढोल बजाते हुए आते हैं। इनको पहले थाने जाना पड़ता है और कोर्ट से आदेश आते हैं कि यह साइलैंट ज़ोन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जबसे आपकी यह अच्छे वाली सरकार

आई है उसके बाद ही वहां से लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। इसका भविष्य में आप कोई प्रावधान करें। इस कोर्ट को शहर से बाहर करें या जो साइलैंट ज़ोन है उसको रिमूव करें?

माननीय मंत्री जी एस0एस0 की बारी में.....

28.08.2018/1115/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 678 क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, अच्छी सरकार तो अच्छी है। अच्छे काम कर रही है। वे काम केवल मात्र इस (सत्तापक्ष) तरफ के लिए नहीं हैं बल्कि पूरे प्रदेश के 68 के 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में काम कर रही है।

जहां तक माननीय सदस्य जी का कहना है कि कोर्ट शहर के बीच में है उसको शहर के बीच से उठा करके दूसरी जगह ले जाना है। मैं माननीय सदस्य जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि कोर्ट परिसर का भवन बना हुआ है। अब जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाने का कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार और विभाग के ध्यान में नहीं है और इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्षः पवन जी, प्रश्न का उत्तर हो गया।

श्री पवन कुमार काजलः सर, यह ठीक है कि कोर्ट की बिल्डिंग नई बनी है। परन्तु मेरा कहने का मकसद यह है कि जो श्रद्धालू आते हैं वे बृजेश्वरी मंदिर को जाते हैं उनको तंग न किया जाए, उनको पहले थाने न जाना पड़े। इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं?

अध्यक्षः मंत्री जी, यह ज्यूडिशरी का मैटर है आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय सदस्य जी, वैसे तो मैंने उत्तर दे दिया है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एक्चुअली होना यह चाहिए था कि जब वह भवन बन रहा था अगर उस वक्त इस कार्य कर दिया गया होता और इस बात को मध्यनज़र रखा होता

कि ज्यूडिशियल कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाने के बजाय कहीं बाहर बनता तो उस वक्त यह सम्भव हो सकता था। अब जब वर्तमान में सारा स्ट्रक्चर बन चुका है, कोर्ट चला हुआ है तो इस वक्त उसको हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाना सम्भव नहीं है।

28.08.2018/1115/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 679

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र आनी के अंदर तीन वर्षों में 1961 लकड़ी के पोल बदले गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे आनी चुनाव क्षेत्र में ऐसे कितने लकड़ी के पोल हैं जोकि अभी बदले जाने शेष हैं? चूंकि मेरा आनी विधान सभा क्षेत्र स्नो बाउंड एरिया है इसलिए कब तक ये पोल बदले जायेंगे?

मुझे प्रश्न के "ख" भाग में उत्तर प्राप्त हुआ है कि आनी विधान सभा क्षेत्र में 2011 में 66 के0वी0 का सब-स्टेशन 13 करोड़ रुपये की लागत लगाया गया है। इसके अलावा मेरा निरमंड ब्लॉक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत 26 पंचायतें आती हैं जिनमें लॉ वॉल्टेज की समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर 22 के0वी0 या 66 के0वी0 का सब-स्टेशन लगाने का विचार रखती है?

इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र आनी में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा जो नए ट्रांसफार्मर्ज़ लगाए जाने हैं वे कब तक लगाने की कृपा करेंगे?

मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ ऐसे घर भी हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने घर हैं और कब तक वहां पर बिजली दी जायेगी?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है उसमें लॉ वॉल्टेज की समस्या और लकड़ी के पोल बदलने के बारे में ज़िक्र किया है। जहां तक पोल की बात है हमने कहा कि तीन वर्षों में 1961 लकड़ी के खम्भे बदले गए हैं। इस वर्ष भी कुल 2100 पोल शिफ्ट करने की इनकी रिक्वायरमैंट है।

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2018/1120/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 679 जारी----

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी----

मार्च, 2019 तक आपके 500 पोल बदलने का हमने टारगेट रखा है। जो आपने वोल्टेज की बात की, वोल्टेज हेतु भी हम 8 नये ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। 10.30 किलोमीटर लम्बी एच.टी. लाइन बिछाई जानी है। 58 किलोमीटर लम्बी एल.टी. लाइन बिछा रहे हैं जिससे आपकी वोल्टेज की समस्या कम हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगा कि आपके निरमंड क्षेत्र के अंदर कम वोल्टेज की समस्या के सुधार हेतु 66/22 के0वी0 के एक सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि आपके चुनाव क्षेत्र के अंदर एक नहीं, दो सब स्टेशन्ज़ का निर्माण हो रहा है। एक तो पहले ही लग चुका है और दूसरा दिसम्बर, 2020 तक हम पूरा करेंगे। हालांकि यह पावर इवैकुएशन के लिए है परन्तु इससे आपकी जो वोल्टेज की समस्या को भी सुचारू रूप से खत्म करने का प्रयास करेंगें। दिसम्बर, 2020 तक का हमने इसका टारगेट रखा हुआ है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने अन्त में यह पूछा था कि कुछ घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। अगर आपके पास उसका उत्तर है तो कृपया दे दीजिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मूल प्रश्न लो-वोल्टेज़ का था लेकिन जो इन्होंने अभी प्रश्न पूछा, जहां ऐसे घर

28.08.2018/1120/केएस/डीसी/2

हैं, जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, आप उसकी लिस्ट हमें दे दें, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगें।

श्री हीरा लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नगान में जो सब स्टेशन का निर्माण हुआ है उससे करसोग का जो 33 के0वी0 का सब स्टेशन है, वह भी उससे जुड़ा है परन्तु अभी तक करसोग में वह 33 के0वी0 सब स्टेशन शुरू नहीं हुआ है। वह इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि नगान में एक ट्रांसफार्मर का निर्माण होना था । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह ट्रांसफार्मर लग चुका है? यदि नहीं, तो वह कब तक लग जाएगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो ट्रांसफार्मर की बात की, 66/33 के0वी0 की बात की, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि इसको हम जुलाई, 2019 तक कम्पलीट कर देंगें और जो वोल्टेज़ की समस्या है, उसका हम समाधान करेंगें।

28.08.2018/1120/केएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 680

श्री नरेन्द्र बरागटा (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्लास नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं के लिए इस वक्त वहां कितनी अकमोडेशन है तथा ये क्योंकि विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत दिया गया है, इसमें जो नये कमरे बनने हैं, वे कब तक बन कर तैयार हो जाएंगें?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालिका) पीपलीवाला पांवटा साहिब में 14 कमरों की रिक्वायरमैंट है जिसमें से विद्यालय के पास अभी 9 कमरे हैं और 5 कमरों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मु0 61,79,000/-रु0 की दे दी गई है और व्यय की स्वीकृति 1,00,000/- रु0 की दी जा चुकी है। प्राक्कलन क्योंकि अधिशासी अभियंता मण्डल पांवटा साहिब से अभी प्राप्त हुआ है इसलिए ये स्वीकृतियां भी अभी दी गई हैं। बजट की उपलब्धता पर इन 5 कमरों का निर्माण कर दिया जाएगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.8.2018/1125/av/dc/1

<u>प्रश्न संख्या : 681</u>

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, पेंशन के लिए आयु 80 से 70 साल डिक्रीज की गई है, मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों को जो पेंशन की सुविधा मिल रही है इससे बच्चा-बच्चा खुश है। इस नीति के बनने के बाद 40359 लोगों ने अप्लाई किया जिसमें से 17981 लोगों को आज दिन तक पेंशन मिल चुकी है। इसमें बिलासपुर जिला में 4147 लोगों को पेंशन लगी है और आवेदन करने वालों की संख्या (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो मंत्री जी का लिखित उत्तर है, आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं। खासकर मैं चम्बा वालों को बधाई देना चाहता हूं। (---व्यवधान---) मंत्री जी अपना उत्तर दे देंगे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं, आप चिन्ता मत कीजिए। चम्बा जिला से 933 लोगों ने अप्लाई किया जिसमें से 923 लोगों को पेंशन उपलब्ध हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, (--

-व्यवधान---) लम्बित मामलों के बारे में तो मंत्री जी बता देंगे। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो लम्बित मामलों की संख्या 22378 हैं।

अध्यक्ष : ध्वाला जी, आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें पेंशन लगाने का क्राइटीरिया क्या है? क्या यह बजट के अनुसार दी जाती है या वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है। दूसरा, पेंशन के जितने भी केसिज होते हैं वे जनरल हाउस में पास किए जाते हैं मगर जनरल हाउस की मीटिंग में गणापूर्ति का अभाव रहता है जिसके कारण प्रार्थी 6-6 महीने तक वहां के चक्र काटता रहता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है कि जो भी पेंशन का मामला आए उस प्रस्ताव को पंचायत पास करें?

28.8.2018/1125/av/dc/2

शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पेंशन लगने से बच्चा-बच्चा खुश है तो मैं इसमें थोड़ा चेंज लाना चाहती हूं। यह पेंशन की स्कीम 70 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति को है तो इससे प्रदेश का हर बूढ़ा-बूढ़ा खुश है। (---व्यवधान---) मैंने इसमें एड किया है कि बच्चों के साथ बूढ़े भी खुश हैं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि इस पेंशन को लगाने हेतु क्राइटीरिया क्या रखा है तो मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रदेश में अब तक जितनी भी पेंशन लगी हैं उसमें 69 वर्ष तक जो पेंशन के हकदार होते हैं उसके लिए 35 हजार रुपये का इनकम क्राइटीरिया रखा गया है। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट में प्रदेश के हर बुजुर्ग के सम्मान के लिए एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हेतु पेंशन के लिए इनकम का कोई क्राइटीरिया नहीं रखा गया है। इस सरकार ने हर बुजुर्ग को सम्मान और पेंशन की बात सुनिश्चित की है। आज सभी सदस्य बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रश्न कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार के मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती

हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी स्कीम शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2018/1130/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 681 .. क्रमागत्
माननीय शहरी विकास मंत्री .... जारी

इतना बड़ा दरियादिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें रखा है, इन स्कीमों को शुरू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और अभी तक हर विधान सभा क्षेत्र से 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कुल 40359 व्यक्तियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें से 17981 लोगों को पेंशन की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा जैसे-जैसे इनके कागज़ात चैक किए जा रहे हैं, सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए प्रयासरत है। इस स्कीम के तहत हर व्यक्ति को 1300/- रुपये पेंशन मिल रही है। इस पेंशन मिलने से हर बुजुर्ग खुश होगा। जहां तक इसके लिए बज़ट की बात है, मुझे याद है कि जब पिछली बार यह विभाग मेरे पास था, मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया था। इसमें ऑनलाइन फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व के आधार पर पेंशन दी जा रही है। जैसे-जैसे बजट का प्रावधान होगा, आगे नई पेंशन लगती जाएगी। इसमें कोई पिक-एंड-चूज और सीनियोरिटी की बात नहीं है। मेरे पास जब पिछली बार यह विभाग था, उस समय से आज तक इसी मापदण्ड के आधार पर यह पेंशन दी जा रही है। इसके लिए बजट की उपलब्धता तो रहती ही है। लेकिन ये पेंशन के मामले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम संवेदनशीलता के साथ इसको आगे बढ़ाते जाएंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर नहीं आया।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी, इसमें जनरल हाउस की जरूरत ही नहीं है।

शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सीनियोरिटी के हिसाब से ही पेंशन लगती है। इनको कोई भी ऑनलाइन चैक कर सकते हैं।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उन फॉमों को तब एक्सैप्ट करता है जब

28.08.2018/1130/TCV/HK-1

उनको जनरल हाउस की मीटिंग में पास करके भेजेंगे। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि ग्राम पंचायत ही उनको पास कर दें?

अध्यक्षः वैसे इसमें जनरल हाउस का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी आप बताएं।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, इसमें जो हमारी एस0सी0 कम्पोनेंट की कमेटी बनी है, जब ये सारे केसिज वहां पुटअप होते हैं, फिर बजट की उपलब्धता पर इनको स्वीकृत कर लिया जाता है। पंचायतों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। पंचायत के लोग केवल एन0ओ0सीज0 दे सकते हैं, विभाग तक कागजात पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनको स्वीकृत करना विभाग का काम है और विभाग में जब कमेटी की मीटिंग होती है तो वह इनको स्वीकृति देती है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये यह जानना चाहता हूं कि इस स्कीम में उम्र कम की गई है। यह योजना कांग्रेस सरकार के समय में 80 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों के लिए थी और आपने इसको 70 साल किया है। मैं यह पूछना चाहता था कि जो पेंशन 70 साल से हैं जिसमें 22000 के करीब केसिज़ पैंडिंग पड़े हैं, इनको आप फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व बेसिज़ पर बता रहे हैं। लेकिन श्री ध्वाला जी और हमारा सवाल यह है कि कई जगह आनॅलाइन नहीं है, लोगों ने फॉर्म सबमिट करवा दिए हैं और 70 साल में इनकम का भी कोई मापदण्ड नहीं है । पंचायत प्रधानों ने फॉर्म जमा करवा दिए हैं। अब

उनमें से 17000 को पेंशन लग गई है और 22000 उस पेंशन से वंचित रह गये हैं। आपने किन मापदण्ड़ों व नियमों के तहत उन 17000 को पेंशन दी? क्या इसके लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि किसको पेंशन देनी है और किस आधार पर देनी है? या फिर जो भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर की उम्र का होगा, जिस दिन वह पेंशन के लिए अप्लाई करेगा, क्या उसको एक महीने के अन्दर पेंशन लगा दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्री श्रीमती एन0एस... द्वारा जारी ।

28-08-2018/1135/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 681 -----क्रमागत

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और इनको यह बात पूरी तरह से समझ नहीं आई है। मैं इनको बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी बुजुर्गों को एक समान दृष्टि से रखते हुए पैंशन देने का फैसला लिया है। यहां पर इनकम की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इनकम के बिना ही सबको समान किया गया है, 70 वर्ष से ऊपर गरीब या अमीर कोई भी पैंशन के पेपर्ज़ भर सकता है लेकिन उसके कागज़ पूरे होने चाहिए। 70 वर्ष की आयु से अधिक प्रार्थी अपना प्रार्थना-पत्र सीधे कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो ऑन-लाईन सिस्टम के बारे में कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जिले के कार्यालयों में ये सारे पेपर्ज़ आते हैं, ये सारे पेपर्ज़ तहसीलों से आते हैं या फिर पंचायत प्रधान भी जमा करवा सकते हैं और सीधे तौर पर व्यक्ति तहसील कल्याण अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी प्रश्न का जबाव आ गया है। आप प्लीज़ बैठ जायें।

शहरी विकास मंत्रीः जब तहसील कल्याण अधिकारी को प्रार्थना-पत्र आयेंगे तो सारे मोनीटरिंग कमेटी की एक ही मीटिंग में आयेंगे, सारे प्रार्थना-पत्र वहां पर रखे जायेंगे। फर्स्ट

कम-फर्स्ट सर्व की बात भी यहां पर हुई है। आप सरकार का धन्यवाद करें कि प्रदेश के बुजुर्ग पैंशन ले रहे हैं और शेष बचे हुए बुजुर्गों को भी सम्मानपूर्वक पैंशन दे दी जाएगी।

अध्यक्षः ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य प्लीज़ बैठ जाईये। ...(व्यवधान)... एक मिनट बैठ जाईये। माननीय मंत्री महोदया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आमदनी का मापदंड हटा दिया है। एक मिनट सुनिए। मंत्री जी आप क्या कुछ और बोलना चाहती हैं। आप केवल इसी बात को बतायें कि 70 साल की उम्र के बाद कितनी पैंशन लगेगी और इसके लिए क्या कागज़ देने पड़ेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि प्रार्थी स्वयं भी अपना प्रार्थना-पत्र दे सकता है। पंचायतें भी भेज सकती हैं। ...(व्यवधान)... आपकी सरकार (विपक्ष) ने तो इस पर विचार ही नहीं किया।

28-08-2018/1135/NS/HK/2

अध्यक्षः आप इनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

शहरी विकास मंत्रीः आपकी सरकार ने तो इन बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं किया। इसकी बज़ट एलोकेशन सोफ्टवेयर बेस्ड है और सलैक्शन भी सोफ्टवेयर बेस्ड है। ...(व्यवधान)... अपने कागज़ कोई भी प्रार्थी पहुंचा सकता है। बज़ट एलोकेशन सबजैक्ट टू टारगेट है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाईये। ...(व्यवधान)...

शहरी विकास मंत्रीः आपकी सरकार (विपक्ष) का रिकॉर्ड देखें तो पिछली बार कुछ नहीं हुआ है।

अध्यक्षः माननीय महेन्द्र सिंह जी, आप अपना स्पष्टीकरण दें। ...(व्यवधान)... प्लीज़ प्रश्न का जबाव आ गया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम सीधी बात पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति 70 साल का हो गया और ऑन-लाईन उसने अप्लाई कर दिया तो क्या उसको उसी दिन पैंशन लग जायेगी या कितने समय के अंदर उसको पैंशन लगेगी?

अध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंह जी, आप उत्तर दें। ...(व्यवधान)... आप एक मिनट बैठिये। आप बैठिये तो सही। उत्तर आ गया है और अब अगले प्रश्न पर जाना है। माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आप बैठ जाईये। ...(व्यवधान)... माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री, महेन्द्र सिंह जी आप बोलिये।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.08.2018/1140/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 681... जारी

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी विधायकों के दिल में एक शंका पैदा हुई है। जैसे आदरणीय रमेश चंद ध्वाला जी ने पूछा कि क्या 70 साल या इससे ज्यादा आयु के वृद्ध लोगों के पैंशन फॉर्म जनरल हाउस से पास होकर आगामी कार्रवाई के लिए जाएंगे? मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके फार्म जनरल हाउस में नहीं जाएंगे। वे इसके लिए डायरैक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे आदरणीय अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि क्या जिस दिन ये फॉर्म ऑन-लाइन प्राप्त होंगे, उसी दिन पैंशन लग जाएगी? आदरणीय अग्निहोत्री जी आप सरकार के बीच में रहे हैं, आपको सरकार के सिस्टम का पूरा पता है। हर काम को करने के लिए समय लगता है। पेपर्ज़ में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है या कोई कॉरैक्शन तो नहीं है। इसलिए उन फॉर्म्ज की छानबीन की जाती है। उसके बाद जो आवेदन-पत्र सही पाए जाएंगे उसके मुताबिक पैंशन लग जाएगी। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वृद्ध पैंशन के केसिज में सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।

28.08.2018/1140/RKS/YK-2

<u>प्रश्न संख्याः 682</u>

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय नैना देवीजी के घ्वांडल में 50 बिस्तरीय अस्पताल अधिसूचित हुआ था। पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि

नैना देवीजी के इस 50 बिस्तरीय अस्पताल को तुरंत सरकार चलाएगी। यहां पर यह भी पूछा गया था कि इस अस्पताल को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत करवाया था कि नैना देवी टैम्पल ट्रस्ट ने इसके लिए 5 करोड़ रुपये का रेजोल्यूशन दिया है। जो श्रद्धालु माता नैना देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर आतें हैं और वहां पर यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर आ जाती है। टैम्पल ट्रस्ट द्वारा 5 करोड़ रुपये का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया और यह रेजोल्यूशन सचिव, भाषा एवं संस्कृति के पास भी पहुंच गया है। लेकिन अब पी.डब्ल्यू.डी., डिविजन नं0-2, जिला बिलासपुर ने 40% धनराशि जोकि मु0 4,03,86,000/- रुपये बनती है, की मांग रखी है और यह कहा जा रहा है कि अगर यह पैसा नहीं मिलेगा तो इस अस्पताल के भवन निर्माण का काम शुरू नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग के पास 1.21 करोड़ रुपये की धनराशि जमा करवाई जा चुकी है। भवन निर्माण हेतु अंडर फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत भी क्लीयरैंस मिल चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उक्त अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ताकि वहां पर जो सैंक्शंड स्ट्रेंथ है वे अपना काम सुचारू रूप से कर सके। जो 4.03 करोड़ रुपये की मांग रखी है या 40% की शर्त है, उस शर्त को हटाने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है और जो 5 करोड़ रुपये का रेजोल्यूशन मां नैना देवी टैम्पल ट्रस्ट ने दिया था उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने श्री नैना देवीजी के घ्वांडल में 50 बिस्तरीय अस्पताल कि अद्यतन स्थिति के बारे में प्रश्न किया है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

28.08.2018/1145/बी.एस/वाई.के./-1

प्रश्न संख्या : 682 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी...

इस अस्पताल के निर्माण के लिए जो औपचारिकताएं सरकार को करनी है सरकार उस पर कार्य कर रही है। यह अस्पताल जब अपग्रेडिड किया गया उससे पहले इसका स्तर सी.एच.सी. का था। उसकी जो प्रशासनिक स्वीकृति थी, वह पहले उसी स्तर की थी परंतु जब इसको 50 विस्तरों का कर दिया तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 10,09,65,900/- रुपये बनती है। यह जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली है यह 14.05.2018 को मिली है। इसके साथ-साथ लगभग 1,21,31,335/- रुपये की व्यवस्था भी कर दी गई है। माननीय सदस्य जी ने यह पूछना चाहा है कि 40 प्रतिशत की जो शर्त है इसमें किसी भी डीविजन में डैंडर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 40 प्रतिशत धनराशि वहां पर जमा करवानी पड़ती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। और इसके साथ-साथ धन की व्यवस्था भी इस कार्य के लिए कर दी है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एश्योर करना चाहता हूं कि श्री नैना देवी जी एक धार्मिक स्थल है इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम धन की उपलब्धता और मंदिर में जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां पर शीघ्रातिशीघ्र धन की व्यवस्था करवाएगी। दूसरा माननीय सदस्य ने कहा कि टैंपल ट्रस्ट नैना देवी जी की तरफ से एक प्रस्ताव मुझे दिया था । वे लगभग 5 करोड़ रुपया इस अस्पताल के लिए देना चाहते हैं। मैंने इस सारे मामले जो मंदिर से संबंधित विभाग को भेजा है और जैसे ही वह विभाग निर्देशित करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे । दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय ठाकुर जय राम जी के माध्यम से कि नैना देवी के ऐतिहासिक स्थान को देखते हुए और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस अस्पताल को अच्छे-से-अच्छा बनाया जाए। सरकार इस अस्पताल के निर्माण के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देगी। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त करता हूं।

28.08.2018/1145/बी.एस/वाई.के./-2

अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य ने पूछना है तो पूछ लीजिए, वैसे इसमें आश्वासन आ गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुल 1,21,31,335/- रुपये सरकार द्वारा दिए गए हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह पैसा पिछले तीन-चार वर्षों से लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा है। वह पैसा कम्युनिटी हैल्थ सैंटर का पैसा था और कुछ पैसा करीब 34 लाख रुपये और दिया गया है लेकिन यह सारा पैसा अस्पताल के लिए बहुत कम है। माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन है कि सबसे बड़ी दिक्कत फोरैस्ट कन्जर्वेशन एक्ट की होती है, फोरैस्ट क्लीयरेंस हो चुकी है। डिग्री कालेज के लिए सड़क बनाने का पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि मंदिर ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि इंकम टैक्स वाले ले जा रहे हैं। कृपया जल्दी इस कार्य को शुरू करें क्योंकि मंदिर ट्रस्ट अगर पैसा देना चाहता है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, सरकार का पैसा इसमें नहीं लगेगा। मंदिर ट्रस्ट वाले तो यह भी कह रहे हैं कि अगर अस्पताल में उपकरणों के लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि विभागीय सचिव के पास केस लम्बित पड़ा है यदि जल्दी से स्वीकृति मिल जाती है तो टैंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिया है। वैसे इसका इतिहास पुराना है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने प्रश्न पूछने हैं । संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि इस अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार कटिबद्ध है और श्री जय राम ठाकुर जी के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत धनराशि की जो आप बात कर रहे हैं उसको सरकार उपलब्ध करवाएगी, यह आश्वासन मैं आपको देता हूं।

श्री डी.टी.द्वारा जारी...

28.08.2018/1150/DT/ AG -1

<u>प्रश्न संख्याः 683</u>

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि 22 मार्च, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी नाचन विधान सभा क्षेत्र के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर चच्योट आई0टी0आई0 में दो नए ट्रेड सैंटर चलाने की घोषण की थी। उसके बाद नाचन विधान सभा क्षेत्र की जनता और कार्यक्रर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री से मिले । सभी कार्यक्रताओं की ओर से एक आग्रह किया गया था की चच्योट आई0टी0आई0 में दो नहीं तीन ट्रेड चालाए जाने की स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आई0टी0आई0 चच्योट में तीन ट्रेड चलाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी।

28.08.2018/1150/DT/ AG -2

<u>प्रश्न संख्याः 684</u>

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय सर्कुलर रोड़ को चौड़ा करने का सोचा गया। मेरे केवल दो प्रश्न हैं इसमें 18.84 करोड़ रूपये सर्कुलर रोड़ की वाईडनिंग के लिए खर्च हुए है यह पैसे ADP के तहत आए हैं या अमृत योजना के तहत आए है, शायद इसमें क्लेरीकल मिसटेक रही हो। मैने इस प्रश्न में यह भी पुछा था कि कितने पेड़ कटे हैं और कितने पेड़ ऐसे कटे जिसमें एन. जी. टी. से आदेश सरकार ने लिये हैं। जहां -जहां यह रोड़ चौड़ा हो रहा है, मैं समझता हूँ रोड चौड़ा करने का जो काम है यह गाड़ीयों को पार्क करने के लिए हो रहा है इससे ट्रैफिक का हल नही हुआ है। कोर्ट को हर साल इसमें इन्टरविन करना पड़ता है। माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला शहर से विधायक है और शिक्षा मंत्री भी है इन्हें पता है कि हर साल कोर्ट को, स्पैशली शिमला में, ट्रेफिक के मामले में इन्टरविन करना पड़ता है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नही उठाएं जा रहे। सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, इसके बावजूद भी ट्रैफिक की इतनी समस्या है कि जहां भी लोग चौड़ी सड़क

देखते हैं वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते है। इससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। आजकल लोग चालान से भी नहीं डरते और पुलिस को कहते हैं कि आप चालान कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक की समस्या के कारण हमारा पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। मेरा सरकार से केवल एक सुझाव है कि की अगर सरकार चाहे तो पार्किंग की आज्ञा प्राईवेट लैण्ड पर स्टील स्ट्रक्चरज़ के ऊपर दे सकती हैं। अब शिमला स्मार्ट सीटी बनने जा रही है तो हम स्टील स्ट्रक्चरज़ के ऊपर फ्लाई ओवरज़ भी बना सकते हैं। ये कुछ सुझाव मैने रखें हैं और मैं चाहूंगा की सरकार इस पर ध्यान दे। क्योंकि हर वर्ष हमारे शिमला शहर की या कहें कि हिमाचल की छवि अन्य राज्यों में ठीक नहीं जा रही है।

श्री एन जी द्वारा जारी....

28/8/2018/1155/ए0जी0/एन0जी0-1

प्रश्न संख्याः 684.... जारी....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य जी ने जानना चाहा है कि इस सड़क के लिए 18 करोड़ 84 लाख रू0 किन-किन मदों से आया है? मैं बताना चाहुंगा कि इस सड़क के लिए 27-03-2018 को 8 करोड 89 लाख 21 हजार रू0 की एडमिनीस्ट्रेशन एप्रूवल और एस्टीमेट सैंक्शन वर्तमान सरकार ने दे दी है । इस सड़क के लिए सी.आर.एफ. से भी 9 करोड 99 लाख रूपये आया है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सड़क में 70 प्वाईंटस है और यह सब विभिन्न विभागों के हैं । इन 70 प्वाईंटस को क्लीयर करने के लिए हमने कई जगह सड़क को चौड़ा करना है, कई जगह सड़क की रीसरफेसिंग करने का कार्य होना है और हमने लोक निर्माण विभाग को यह सारा कार्य सौंपा है। लोक निर्माण विभाग ने इन 70 प्वाईंटस में से 28 प्वाईंटस क्लीयर कर दिए हैं ।

14 प्वाईंटस पर कार्य चल रहा है। शेष 28 प्वाईंटस, जोकि विभिन्न् विभागों के हैं, लोक निर्माण विभाग उन सभी विभागों से निवेदन कर रहा है कि इन प्वाईंटस में जो ज़मीन के विवाद हैं उन मामलों का समाधान करने के लिए विभाग अपने स्तर पर शीघ्र प्रयास करे। लोक निर्माण विभाग भी अपने स्तर पर इन 28 प्वाईंटस को क्लीयर करने के लिए कार्य कर रहा है । जो 28 प्वाईंटस कलीयर हो चुके हैं और जिन 14 प्वाईंटस पर कार्य चल रहा है उनके लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशी उपलब्ध है । शेष बचे 28 प्वाईंटस में भी जैसे-जैसे जमीन उपलब्ध होती जाएगी, वैसे-वैसे वर्तमान सरकार इस पर कार्य करेगी, माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है । मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय सदस्य से, क्योंकि आप वहां के चुने हुए प्रतिनिधि है, अतः आप भी अपने प्रभाव का प्रयोग करके इस सड़क के सभी प्वाईंटस को क्लीयर करने में सरकार और विभाग की मदद करें ।

28/8/2018/1155/ए0जी0/एन0जी0-2

प्रश्न संख्याः 685

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पुछना चाहुंगा कि ये जो सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक है, ये वाकई में बैंक का काम करता है या ये कुछ लोगों के पैसे कमाने का धन्धा है । जो सूचना माननीय सदन में रखी गई है उसके अनुसार पिछले 3 साल में लगभग 174 करोड़ रूपये का लोन इस बैंक ने लोगों को दिया है और उसमें से 64 करोड़ रूपये बैंक का एन.पी.ए. है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहुंगा और आश्वासन भी चाहुंगा कि जिन लोगों ने लोन लिया है और जो डिफाल्टर हैं, उन लोगों के पास भारी मात्रा में चल-अचल ऐसेट, बड़ी-बड़ी गाडियां हैं, उन्होंने 3-3 कुत्ते पाल रखे हैं और 4-4 करोड़ की कोठियां बनाई हुई हैं । वो लोग जानबूझ कर बैंक का लोन नहीं देते । क्या माननीय मन्त्री जी उन लोगों से रिकवरी का कोई आश्वासन देते हैं और

जिन्होंने लोन देते समय नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है, क्या सरकार उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई करना चाहती है ?

उद्योग मन्त्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने एन.पी.ए. के बारे में चिंता जाहिर की है। इस से पहले भी इस विषय को माननीय सदन में माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने भी रखा है। जिन लोगों ने बैंक से पैसा लिया और पैसा वापिस नहीं किया और बैंक का इतना ज्यादा एन.पी.ए. हो गया, जिसके कारण बैंक की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा है।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

28/08/2018/1200/RG/DC/1

प्रश्न सं. 685--क्रमागत

उद्योग मंत्री-----जारी

आपका नाम मैंने बिना बोले ही ले लिया। जो यहां पर बोला गया है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, ये जितनी भी बातें इसमें आई हैं, इनके ऊपर जांच शुरू करवा दी है और जो लोग दोषी हैं, उनको इसके लिए दण्ड मिलेगा।

प्रश्नकाल समाप्त

28/08/2018/1200/RG/DC/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभी पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल और माप), वर्ग-II(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-2/2016 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-II(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-बी.(2)-5/2016 दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.05.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28/08/2018/1200/RG/DC/3

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं

28/08/2018/1200/RG/DC/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। सर्वप्रथम श्रीमती आशा कुमारी, सभापति लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19) के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

Smt. Asha Kumari : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy each of the Reports of the Committee on Public Accounts:-

i. समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है;
ii. समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पर आधारित तथा **वित्त विभाग(आधिक्य)** से सम्बन्धित है; और
iii. समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 पर आधारित तथा **वित्त विभाग(आधिक्य)** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2018-19) के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

28/08/2018/1200/RG/DC/5

i. समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 70वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित** से सम्बन्धित है;और
ii. समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 4.2,4.3, 4.4 व 4.5 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल, सदस्य, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

डॉ.(कर्नल)धनी राम शांडिल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2018-19) का दसवां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को राहत प्रदान करने की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

28/08/2018/1200/RG/DC/6

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

Shri Rakesh Pathania : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy of the Reports of the Public Administration Committee:-

i. समिति का **तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सैनिक कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :

(i) समिति का **8वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं

विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्राथमिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

28/08/2018/1200/RG/DC/7

(ii) समिति का **5वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति **(वर्ष 2018-19)**, का **7वां कार्रवाई प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर

आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

एम.एस. द्वारा अगली मद शुरू

28/08/2018/1205/MS/YK/1

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)कार्य-सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी करता हूं।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने तृतीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है"।

तो प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने तृतीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है"?

(प्रस्ताव स्वीकार)

28/08/2018/1205/MS/YK/2

नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा

अध्यक्षः अब नियम-63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा होगी।

अब श्री मुकेश अग्निहोत्री जी नियम 63 के अंतर्गत चर्चा उठाएंगे किन्तु इस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। चर्चा के उपरान्त माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। श्री हर्षवर्धन चौहान जी का नाम भी इसमें शामिल हैं और वे भी इसमें भाग ले सकते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा नीति में जो संशोधन किए गए हैं वे संशोधन चुपचाप और गुपचुप किए गए हैं। मैंने उस मसले को विधान सभा के भीतर उठाने के लिए आपसे आग्रह किया था। आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा नीति हमेशा से इस प्रदेश का कन्सर्न का विषय रहा है। पावर सैक्टर हमारी आय का साधन भी है और लम्बे समय से पावर सैक्टर में फ्री पावर और रॉयल्टी के लिए संघर्ष भी हुए हैं। पूर्व की सरकारें चाहे वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, चाहे शांता कुमार जी की सरकार थी या धूमल जी की सरकार थी, वे हमेशा फ्री पावर और रॉयल्टी के मुद्दे पर संर्घषरत्त और आंदोलित रहीं। लेकिन यह पहली जय राम जी की सरकार आई है

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जिसने छः महीने में ही इस प्रदेश में जो भी सरकारें पावर सैक्टर के लिए आज दिन तक केस तैयार करती रहीं, उसको धराशाही करके रख दिया। उसको इन्होंने पूरी तरह डिमोलिश कर दिया और मैं तो यह कहूंगा कि पावर लॉबी के आगे इस सरकार ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। हिमाचल के रिसोर्सिज को सेलआउट करने की पूरी रणनीति इन्होंने तैयार कर दी है। इन्होंने तो अखबार में बयान देकर साफ कर दिया है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? -(व्यवधान)-लेकिन मैं वह तान छेड़ना नहीं चाहता जो मेरी बहन छेड़ना चाहती है। पावर माफिया के आगे पूरी तरह आपने समर्पण दिखा दिया है। एक समय था जब रॉयल्टी के लिए संघर्ष हुआ, यात्रायें हुईं और यह मनवाया गया कि वर्ष 1990 के बाद के जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

28.08.2018/1210/जेके/एच0के0/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः------जारी--------

उन पर 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी, फ्री पावर मिलेगी। यह मांग होती रही कि 1990 से पहले के जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनमें भी फ्री पावर मिले। भाखड़ा बगैरह के केसिज़ पर लड़ाई होती रही। अब आप पावर पॉलिसी में चेंज़िज लाए हैं। बाहर तो इन्होंने कहीं आउट नहीं किया है। आनन-फानन में, औनें-पौंने तरीके से फैसला केबिनैट में कर दिया। कुछ बातें छन-छन के बाहर आई हैं। पहली दफा किसी सरकार ने फ्री पावर को 12 साल के लिए डिफ़र कर दिया। अगर आपने फ्री पावर को ही डिफ़र कर दिया तो इसके बाद पावर सैक्टर में आपके पास क्या बचा है? जो इन्कम का साधन आपके पास होता था आप उसी को डिफ़र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कैम का रूप धारण कर लेगा। आप लोग सत्ता में बैठे हैं, कुर्सियों में बैठे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग ही हमेशा रहेंगे। आपने फ्री पावर को 12 साल तक छोड़ने का फैसला किया है, हकीकत तो मंत्री जी यहां पर बयां करेंगे कि क्या-क्या किया है? जो प्रोजैक्ट होंगे, 10 मैगावॉट तक की बिजली हमारा बिजली बोर्ड खरीदेगा। सवाल यह है कि उनकी मंहगी बिजली हमारा बिजली बोर्ड क्यों खरीदे? बिजली बोर्ड को ऐसी क्या आफ़त आ पड़ी है कि प्राइवेट इन्वैस्टर की बिजली मंहगे रेट से ले कर वह उसको फिर आगे बेचेगा? आपने यहां पर बोर्ड का भट्टा बिठाने का पूरा बन्दोबस्त कर दिया है। जो सरकार को फायदे मिलने हैं वे कन्स्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट से मिलते थे और अब आपने यह कर दिया कि कमिशन के टाइम से फायदा मिलेगा। एन0ओ0सीज़0 सारी गवर्नमैंट प्रक्योर करके देगी। फ्यूचर प्रोजैक्ट्स के लिए आप करते तो समझ आता। आपने जो ऑन गोविंग प्रोजैक्ट्स हैं, अलॉटिड प्रोजैक्ट्स हैं, उन सब पर यह नीति लागू कर दी। अलॉटिड प्रोजैक्ट्स से करोड़ों, लाखों और अरबों में जो आय प्रदेश को होनी है, आपने पूर्व सरकारों द्वारा जो प्रोजैक्ट्स अलॉटिड थे,

उन पर भी वह नीति लागू कर दी। मंत्री जी को सदन में यह बताना पड़ेगा कि आखिर जो

28.08.2018/1210/जेके/एच0के0/2

आपने प्रोजैक्ट्स की रॉयल्टी डिफ़र की है इससे हिमाचल को टोटल कितना नुकसान हुआ? यह आंकड़ा इस माननीय सदन में रखा जाए कि इससे कितने अरब/खरब रूपयों का नुकसान होगा। पहले ही जो अपफ्रंट प्रीमियम 20 लाख रूपए का था वह इनके लिए एक लाख रूपए कर दिया गया था । लीज़ मनी घटाई गई थी और अब तो यह हो गया है कि हिमाचल प्रदेश को, सरकार को और बिजली बोर्ड को कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ पूंजीपति ही इससे पलेंगे। जो बड़े-बड़े पावर सैक्टर के लोग हैं वे केवल 10-15 लोग होंगे उनको फायदा देने के लिए आपने इतनी सालों की मेहनत पर पूरा पानी फेर कर रख दिया है। आपने यह भी कहा कि 25 मैगावॉट तक इन्वाइरन्मैंट क्लीयरैंस की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पहले 5 मैगावॉट तक था उसको आपने 25 मैगावॉट तक आगे करवा दिया। इसका मतलब आपने हिमाचल के पर्यावरण का licence for the destruction of environment जारी कर दिया। आपकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी सड़क बननी होती है उसके लिए भी इन्वाइरन्मैंट क्लीयरैंस लेनी पड़ती है जबकि यहां पर 25 मैगावॉट, 20 मैगावॉट तक के प्रोजैक्ट्स के लिए आप इनवाइरन्मैंट क्लीयरैंसिज में ऐसी रिलैक्सेशन देंगे और यह कहेंगे कि केन्द्र यह चाहता है, केन्द्र ने मांग की है लेकिन केन्द्र तो बहुत कुछ चाहता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

28.08.2018/1215/SS-HK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागतः

लेकिन हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा नीति की एक सैंक्टिटी है। बोर्ड को बिजली महंगी मिलेगी और वह सस्ती बेचेगा। पहले ही आप 300 या 400 करोड़ रूपये की सबसिडी दे रहे हैं जोकि कंज्यूमर्ज़ को पास ऑन करते हैं। आप इतनी महंगी बिजली लोगों से खरीदेंगे। मंत्री जी, आप यह हाउस में बताने की कृपा करें कि आप किन लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। आखिर वे कौन लोग हैं जिनको ऑब्लाइज किया जा रहा है? कौन-सा दबाव आपके ऊपर रात के अंधेरे में छः महीनों में आ गया कि आपको पूरे पावर सैक्टर का स्वरूप ही चेंज करना पड़ गया। यहां पर शांता जी के टाइम में 1990 के बाद के जो प्रोजैक्टस थे उनमें फ्री पावर मिली। चमेरा की बात हुई। पहले तीन परसैंट की बात हुई। फिर बाद में उसको बढ़ाकर 12 परसैंट तक लेकर गए। फिर यह मांग भी आई कि 1990 से पहले के प्रोजैक्टस पर भी फ्री पावर की बात मनवाई जाए। आप अभी भी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि पानी पर हम रॉयल्टी मांगेंगे। आपको कौन मानेगा? क्योंकि आप अपनी 12 परसैंट की फ्री पावर डैफर कर रहे हैं। यह भी क्या गारंटी है कि जिन प्रोजैक्टों में आपको फ्री पावर मिल रही है वह मिले। वे कहेंगे कि आपने तो अपनी नीति बदल दी तो आपको किस बात के पैसे दिए जाएं। 1990 के बाद के जिन प्रोजैक्टों में आपको पैसा मिल रहा है वह पैसा आपको कैसे मिलेगा? पहले की बात तो आप छोड़िये। आपका पानी की रॉयल्टी का क्लेम भी खत्म हो जायेगा। यह मसला हिमाचल प्रदेश में आज का नहीं है। आपको याद होगा कि माननीय ध्वाला जी और आपके कुछ साथियों ने 2001 के आस-पास प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ इश्युज़ खड़े किये थे। उनमें इन्होंने उस समय कहा था कि 35 प्रोजैक्टस कैबिनेट ने एक ही दिन में क्लीयर कर दिए। उसमें स्पैसिफिक मैंशन था कि आप इतने पावर प्रोजैक्टस को एक ही दिन में कैसे दे सकते हैं। अब तो आपने एक दिन क्या हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने बिजली के सैक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इतना बड़ा इश्यु था, आप इसको हाउस में लाते और ऊर्जा नीति पर कैबिनेट एप्रूवल से पहले इस माननीय सदन में डिस्कशन करते। क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि इस इश्यु पर इस माननीय सदन में डिस्कशन होती? आपको पता है कि कुछ देश सोलर पावर पर चल पड़े हैं जहां पर दो-दो या ढ़ाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। अब मंत्री जी कहेंगे कि हमें इसमें खरीददार नहीं मिल रहे थे। अगर खरीददार नहीं मिल रहे थे तो क्या यह बहुत ही ज़रूरी हो गया

28.08.2018/1215/SS-HK/2

कि इसको बेचना ही है। यह भी नहीं है कि आज की आपकी सरकार है यह आगे सदियों या पुश्तों तक चलेगी। आने वाले समय में बहुत सरकारें आयेंगी जब मार्किट स्टेबल होगी, समय अनुकूल होगा, तो उस वक्त की सरकारें इसे बेचने का काम करेंगी। आज अमेरिका अपने तेल के भण्डार को इस्तेमाल नहीं करता। आज स्वीडन ने अपना 30 परसैंट रिसोर्स रिजर्व रखा हुआ है कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप भी इसको पांच या दस साल के लिए रिजर्व रख देते कि खरीददार नहीं हैं या हमें ठीक रेट नहीं मिल रहा है। आपको ऐसी क्या पड़ी है कि आप कह रहे हैं कि इसे आज ही बेचना है? चाहे जो मर्जी हो मैंने आज ही बेचना है। मुख्य मंत्री जी पर दिल्ली से या किसी पावर लॉबी से या माफिया का ऐसा क्या दबाव आ गया कि आपने फ्री पावर जैसे संवेदनशील मसले पर हाथ डाल दिया? आपको मालूम है कि 2007-08 में फ्री पावर की बात 12 परसैंट से बढ़कर एक बार 18 परसैंट, फिर 23 परसैंट और लगभग 33 परसैंट तक चली गई थी। 33 परसैंट तक फ्री पावर की बात हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने की। फिर अगर आपने यह करना भी था तो जितने भी पहले टैंडर कर रखे थे उनको रद्द कर देते। फ्रैश टैंडर करते। अब राफेल हवाई जहाजों में क्या मुद्दा है? यही है कि आपने फ्रैश टैंडर नहीं किये। अगर आपने किसी को स्कीम देनी है तो आप पिछलों को कैसे फायदा दे सकते हैं? जितने भी पावर प्रोजैक्टस एलॉट कर रखे हैं, सरकारों के साथ समझौते हो रखे हैं, आप उसमें उनको कैसे फायदा दे सकते हैं? आप फ्रैश टैंडर करवाते,

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2018/1220/केएस/वाईके/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी----

फ्रैश निविदाएं इन्वाइट करते। टैंडरिंग प्रोसैस ठीक ढंग से होता । सदन को यह जानने का अधिकार है कि यह ब्रेन चाइल्ड है किसका? मंत्री जी, आपका तो हो नहीं सकता, इतना मैं जानता हूं। इसमें बहुत बड़े दिमाग ने काम किया है। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य

मंत्री महोदय, यह करप्शन से जुड़ा मसला है । आने वाले समय में इसकी परतें खुलती चली जाएंगी कि किसका दिमाग लगा? आप पंजाब से एरियर मांगते हैं। क्या एरियर मांगेंगे आप? आप अपने प्रदेश में तो ले नहीं रहे हैं आप पानी से रॉयल्टी मांगते हैं परन्तु आप क्या रॉयल्टी मांगेंगे? 1990 से पहले के प्रोजैक्ट्स में आप क्या हिस्सा मांगेंगे? आप शांता कुमार जी को, धूमल जी को क्या जवाब देंगें कि आप लोगों ने ये नीतियां बनाई थी और आप 40 साल तक लड़ते रहे लेकिन आज हमने आते ही इसमें पलीता लगा दिया और हम अब किसी से कुछ नहीं लेंगे। ऐसी नीति बनाने का क्या फायदा जिसमें आम आदमी को फायदा नहीं है, जिसका बोर्ड को, सरकार को फायदा नहीं है। एक्सचेकर को कुछ नहीं मिल रहा है। इससे अगर फायदा होगा तो सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होगा और 25 मैगावाट, 20 मैगावाट तक के प्रोजैक्ट्स को इस दायरे से निकालना, हिमाचल के पास है क्या? हिमाचल के पास टूरिज्म है, एन्वायरन्मैंट है। कल टूरिज्म की बात हो रही थी कि आप 26 इकाइयां बेचने जा रहे हैं। बेच दो। सेल आउट के लिए आप तैयार हो रहे हैं। (व्यवधान) मंत्री जी (महेन्द्र सिंह जी) आप बहुत पुराने मंत्री है। आप यहां पर ऊर्जा नीतियों के गवाह रहे हैं। आप यहां की लड़ाइयों के गवाह रहे हैं कि ऊर्जा की लड़ाइयां किस ढंग से लड़ी गई और आज आप इस बात पर हंस रहे हैं? एक दिन पूरा प्रदेश इस बात पर रोएगा कि आप लोग कर क्या गए हैं? एक दिन पूरा प्रदेश रोएगा कि आप लोगों ने किस ढंग से पूरे प्रदेश के हाथ काट दिए।आपने हिमाचल के रिसोर्सिज़ को सेल आउट कर दिया। पावर माफिया के साथ आपका समझौता हो गया। इससे अरबों में जो लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? बिजली मंहगी मिलेगी और बोर्ड को अलग से नुकसान होगा। आप लोगों को आगे सबसिडी देंगें, तब भी नुकसान होगा और आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा नीति में बदलाव करें। अगर आपको लगता था कि कोई खरीददार नहीं है तो आप इसको पैंड कर देते। अगर आपको लगता था कि आपके ऊपर कोई दवाब है, आप इसको पांच-दस साल के लिए पैंड कर देते कि जब स्थिति अनुकूल होगी तब करेंगें। इसमें पूंजीपतियों को इन्सैंटिव देने की बात कहां आ गई ? बड़ा क्लीयर है

28.08.2018/1220/केएस/ वाईके /2

कि इसमें कम्पनियों को फायदा होगा। उनको फायदे की पूरी बिसात आपने बिछा दी। पर्यावरण को नुकसान कर दिया। इतने बड़े फैसले को आपने गुपचुप तरीके से लागू कर

दिया। आप नोटिफिकेशन्ज़ कर रहे हैं। इस हाउस को आप विश्वास में भी नहीं लेना चाहते then for what this Hon'ble House is there? अगर आप ऊर्जा नीति पर बात कर रहे हैं तो आपने यहां पर चर्चा क्यों नहीं लाई? आप डिबेट करते । गलियारों में जो चर्चा है उसकी भी थोड़ी-बहुत जानकारी ले लिया करो कि क्या हो रहा है? इसमें बोर्ड को और सरकार को फायदा नहीं, लोगों को फायदा नहीं सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। माननीय मंत्री जी, हमारा आपसे अभी भी आग्रह है कि सरकार के झांसे में मत आओ। इन लोगों के झांसे में मत आओ। इस पॉलिसी को रिव्यू करवा दो और प्रदेश को लाइफ टर्म जो नुकसान होने जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप हाथ आगे बढ़ाओ। इसको रिव्यू करो। सरकारें आती-जाती रहेंगी लेकिन इस प्रदेश का हित सर्वोपरि है। उसके बारे में सोचें और इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखें। जब बाजार ठीक होगा, जो भी सरकार होगी, वह बेच लेगी लेकिन इसको इस ढंग से बेचना शुरू मत करो। प्रदेश सरकार के इसमें हित इन्वॉल्व है और पावर में बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिल रही है जो

श्रीमी अ0व0 द्वारा जारी---

28.8.2018/1225/av/yk/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री ---------- **क्रमागत**

आप कहें कि लोगों को नौकरियां देने के लिए हम कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, किसी में 15 आदमी तो किसी में 25 आदमी लगे हैं। आप इसके लिए कोई ऑडिट करवाते या डिबेट करवाते; आप कुछ तो करते। लेकिन आपने इस तरह से हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। आप ऊर्जा नीति में चेंज करके इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान करके जायेंगे जिसकी भरपाई आने वाले समय में सम्भव नहीं होगी। आपके तीन मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी, शांता कुमार जी और प्रेम कुमार धूमल जी; जिन्होंने इस बारे में लडाइयां लड़ीं। ये लोग चैंपियन थे, जिन्होंने रॉयल्टी और फ्री पावर की लड़ाई लड़ी उसमें आपने 6 महीने के अंदर ही बिना सोचे-समझे, अनाड़ीपन में बदलाव ला

दिया। आपने इस नीति में बदलाव लाकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और जब आप यह नीति लेकर आयेंगे तो और ज्यादा सवाल खड़े होंगे। बिजली बोर्ड के चंद ऑफिसर्ज को साथ लेकर आप इस तरह का बदलाव कर लेंगे तो समय आने पर उन ऑफिसर्ज से भी पूछा जायेगा कि आपने यह क्या किया। सरकार तो पांच साल बाद चली जाती है मगर उन लोगों से भी पूछा जाता है कि आपने हिमाचल के लिए अरबों-खरबों रुपये का नुकसान कैसे खड़ा कर दिया। हमारा यह सुझाव रहेगा कि ऊर्जा नीति में बदलाव लाने से पहले आप इस बारे में दोबारा से सोचें, इसको रिव्यू करें। आप पूंजीपतियों/पावर माफियाओं को फायदा पहुंचाने का अपना इरादा त्याग दें, इसी में आपका हित रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि सरकार को सद्बुद्धि दो। हिमाचल का इतना बड़ा केस जो कि 40-50 वर्षों से बिल्ड होता रहा उस पर आज इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। हिमाचल प्रदेश में आय का साधन केवल पावर है मगर इस पावर का इन्होंने अपनी पावर के साथ विश्वासाघात कर दिया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.8.2018/1225/av/yk/2

उपाध्यक्ष : इस विषय पर अभी दो लोगों ने और बोलना है अतः माननीय सदस्य, हर्षवर्धन जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात संक्षिप्त में कह कर समाप्त करें।

श्री हर्षवर्धन चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा नीति पर प्रदेश सरकार द्वारा जो संशोधन लाया गया है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पिछले महीने मंत्री मंडल की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया है। जिसमें इन्होंने कहा है कि 737 टोल प्रोजैक्ट्स जिनकी क्षमता 5500 मेगावाट है उसको राहत देने के लिए यह संशोधन किया गया है। यहां पर मुकेश जी ने बहुत सारी बातें कही हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। साथ में, इन्होंने यह भी कहा है कि 300 और

प्रोजैक्ट्स जिनको कोई नहीं ले रहा है तथा जिनकी क्षमता 2200 मेगावाट है वह प्रोजैक्ट कैसे चलें यह आपने अपने एम्स एण्ड ऑब्जैक्ट्स में किया है। अभी मुकेश जी पूछ रहे थे कि कितना लोस हुआ है, यह मैं बताऊंगा। हिन्दुस्तान में हाइडल पावर की 84000 मेगावाट की क्षमता है जिसमें से लगभग 22000 मेगावाट की केपेसिटी हिमाचल प्रदेश की अकेले की है। हिमाचल प्रदेश की इस 22000 मेगावाट की केपेसिटी में से लगभग 6300 मेगावाट की केपेसिटी हमने हार्नैस कर दी है। आपने जो 1037 प्रोजैक्ट्स का कहा है इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यह लगभग 7700 मेगावाट बिजली बनती है। अभी मुकेश जी ने पूछा कि लोस कितना होगा। टोटल केपेसिटी जिसको आप मुफ्त में दे रहे हैं यानि हमारी पूर्व सरकारों के सब मुख्य मंत्रियों की जो शुरू से 12 प्रतिशत की पॉलिसी रही है उसमें आपने संशोधन करके उसको फ्री ऑफ कोस्ट दे दिया। सिर्फ एक संस्था है जो किसी भी चीज को मुफ्त में देती है और वह भगवान है। यह पहली सरकार है जो पावर प्रोजैक्ट से 12 प्रतिशत की रॉयल्टी जिसको हिन्दुस्तान की सब सरकारें लेती है, आप उसको फ्री में बांटने जा रहे हैं।

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2018/1230/TCV/AG-1

श्री हर्षवर्धन चौहान.... जारी

उपाध्यक्ष महोदय, रेत, बज़री, मिनरल, पानी इत्यादि पर हर सरकार अपने रिसोर्सिज़ बढ़ाने के लिए थोड़ी या ज्यादा रॉयल्टी लेती है। अगर 5500 मेगावाट के ये 737 हाईडल प्रोजेक्ट जो 2, 5, 10 व 25 मेगावाट से नीचे के हैं, इन सभी को जोड़ लें तो हिमाचल प्रदेश का जो 12% फ्री शेयर है, वह 660 मेगावाट बनता है और कुल ऊर्जा 34,68,960 बनती है assuming a load factor of 60 per cent. यह प्रोजैक्टस, जिनको आप फ्री में बेच रहे हो, यदि उनकी कपैसिटी के मुताबिक 100 % न रखकर 60% ही रखेंगे तो भी हिमाचल प्रदेश को एक साल में 867 करोड़ रुपये का रैवेन्यू आएगा। आपने

जिनको 12 साल के लिए फ्री में दिया है, उनसे 12 साल में 10,404 करोड़ रुपये का रैवन्यू आएगा। आपकी सरकार 10,404 करोड़ रुपये का नुकसान आने वाले 12 सालों में पहुंचाएंगी। अभी तो आपके प्रोजेक्ट्स शुरू ही नहीं हुए होंगे। आने वाले 5-7 साल में आपके ये प्रोजेक्ट्स चलने शुरू होंगे और 12 सालों तक फ्री में रहेंगे। इस तरह से आने वाले 20 सालों में इन हाईडल प्रोजेक्ट्स से कोई बिजली नहीं मिलेगी। आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? आपके मुख्य मंत्री तो कहते हैं कि हम तो इस कुर्सी पर अभी 25 साल तक हैं। आपको ऐसी भी क्या जल्दी है कि 6 महीने, साल के अंदर ही आप अपने प्रोजेक्ट मुफ्त में बांट रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है। मैं अभी पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से ज़िक्र कर रहा था और मुझे याद है कि 1998 में हम में से बहुत थोड़े लोग श्री महेन्द्र सिहं जी, श्री राकेश पठानिया, श्री राम लाल जी, श्रीमती आशा कुमारी जी यहां हाउस में थे। वर्ष 1998 में जब सरकार का परिवर्तन हुआ और आपकी गठबंधन सरकार आई तो उस व़क्त की सरकार कहती थी कि पूर्व राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने प्रोजेक्ट्स में 25% इक्विटी रख दी है। 12% फ्री -शेयर पहले ही था लेकिन श्री वीरभद्र सिंह जी ने इक्विटी रखने के नये कंसैप्ट का प्रावधान किया। लेकिन आप लोग इसका विरोध करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब आप कैबिनेट में इक्विटी को बेचने का प्रपोज़ल ले गये। लेकिन वह नहीं हुआ। आज मुझे खुशी है, हम राजा वीरभद्र सिंह जी की दूरदृष्टि को बधाई देते हैं, आज नाथपा

28.08.2018/1230/TCV/AG-2

झाकड़ी पॉवर प्रोजेक्ट जिसका नाम सतलुज जल विद्युत प्रोजेक्ट है, उससे हज़ारों-करोड़ों रुपये की आय हिमाचल प्रदेश को हो रही है। आपकी सरकार ने कोलडैम और पार्वती प्रोजेक्ट का एम0ओ0यू0 साईन किया। पार्वती प्रोजेक्ट जो 2050 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, आपने उसमें सिर्फ 12% फ्री शेयर लिया आपने उसमें इक्विटी नहीं रखी । जो कंसैप्ट कांग्रेस सरकार, पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने चलाया था, उस कंसैप्ट को आपने आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद 800 मेगावाट के कोलडैम में भी आपने इक्विटी

नहीं रखी। मुझे याद है, उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा "where there is a will, there is a way" और नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट की रॉयल्टी का पैसा आया। रामपुर के प्रोजेक्ट में राजा वीरभद्र सिंह जी ने उस व़क्त वह इक्विटी 25% से बढ़ाकर 37% कर दी थी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी व राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की है।

श्रीमती एन0एस... द्वारा जारी ।

28-08-2018/1235/NS/AG/1

श्री हर्षवर्धन चौहान------जारी

आज हम सब जितने भी लोग हैं और मैं आपके मंत्रिमंडल के फैसले से हैरान हूं तथा अनिल शर्मा जी, मेरे भाई हैं, मैं इनको कल पूछ रहा था कि यह कैसे हो गया और क्या आपको इन्होंने पूछा भी कि नहीं? It is the collective responsibility of the entire Cabinet. आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, जिसमें आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की हाईडल पॉवर 22,000 मेगावाट है और इसमें से आपने एक तिहाई को मुफ्त में बेचने का प्रावधान कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। जैसे अभी माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आप यह मत समझो कि यह चैप्टर यहीं पर क्लोज़ हो जाएगा। अभी तो हमारे डिसप्यूट सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। हमारे बहुत सारे राज्यों से डिसप्यूट्स चले हुए हैं। आज हर राज्य को यह कहने के लिए मौका मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी 12% फ्री पॉवर को सरैंडर कर दिया है। 25 मेगावाट से कम प्रोजेक्टों में आपने 12% फ्री पॉवर को सरैंडर कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी, यह नेशनल लेवल पर चलेगी। हमारा भाखड़ा डैम वाला डिसप्यूट सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे पॉवर प्रोजेक्ट्स हैं, ये उन लोगों ने लिये हैं जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं और चाहे उनका जिस मर्ज़ी पार्टी से संबंध रहा हो। आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स चल ही नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने ये

प्रोजेक्ट्स लिये हैं उनकी मंशा इनको चलाने की नहीं है। उनकी मंशा तो इन प्रोजेक्टों को बेचने की है। लेकिन ये प्रोजेक्टस बिक नहीं रहे हैं। ये इसलिए नहीं बिक रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरे देश में अर्थव्यवस्था की नेगेटिव ग्रोथ है। हमारी अर्थव्यवस्था रूक गई है और रूकने की वज़ह से आज पॉवर की कीमत एक स्टेगनेशन पर आ गई है। आज पॉवर इंडस्ट्री इक्नॉमीकली वायेबल प्रोजेक्ट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आज नहीं है लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो इंडस्ट्री का नम्बर वन रॉ मैटीरियल पॉवर होता है। आने वाली जो हमारी रायल्टी है और हमारा आने वाला भविष्य यानी जेनरेशन को जो कमाई के रूप में देगा, उसको आप कृपा करके ने बेचें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से ऐसा निवेदन है।

28-08-2018/1235/NS/AG/2

आज यहां पर मुख्य मंत्री महोदय मौजूद नहीं हैं। अगर वे इस चर्चा को सुनते और जो आंकड़ें, बातें तथा राजनीतिक गलियारों में आज जो चर्चायें इस पॉवर प्रोजेक्ट के बारे में हो रही हैं, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। किसी भी चुनी हुई सरकार या बहुमत वाली सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, जैसा आपने यह फैसला लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको वाईंड-अप करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस पॉलिसी के बारे में जो निर्णय आपने कैबिनेट में लिया है, आप इसको प्रदेश के हित में रिव्यू करें। हमारे पास जो पूंजी, एफ0डी0 आदि पड़ी हुई हैं, वह हमें नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग घर में एफ0डी या पैसा संभाल कर रखते थे कि in times to come यह हमारी पूंजी है, इसको मत बेचो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुर्नविचार करें और इसको वापिस लें। आप इसको ठीक करें। आप इसको फ्री ऑफ कोस्ट क्यों कर रहे हैं? आप पहले तीन सालों में 3% कर दो, अगले तीन सालों में 6% कर दो और फर्दर तीन सालों में 12% कर दो। लेकिन आपने तो टोटल फ्री ऑफ कोस्ट कर दिया है। इसमें घौटाला है और दाल काली है। दाल काली ही नहीं बल्कि पूरी-की-पूरी काली है। इसलिए आप इस पर पुर्नविचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.08.2018/1240/RKS/DC-1

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सक्खु चर्चा में भाग लेंगे।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मुकेश अग्निहोत्री और श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने जो नियम-63 के अंतर्गत ऊर्जा नीति पर प्रस्ताव लाया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कृपया आप एक मिनट बैठ जाइए। नियम-63 के अंतर्गत जिनके नोटिस प्राप्त हुए हैं, उनके अलावा किसी को भी बोलने का प्रावधान नहीं है। हम इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, मैंने दो मिनट में सिर्फ दो ही प्वाईंट्स बोलने हैं और आप इसके लिए कृपया व्यवस्था कर दीजिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैंने क्षमा याचना के साथ आपको कहा है क्योंकि इसके बाद हमेशा के लिए यह प्रावधान हो जाएगा।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, आपके पास अधिकार है और आप यह व्यवस्था दे सकते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

28.08.2018/1240/RKS/DC-2

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, आपने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया, आपका धन्यवाद। वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऊर्जा नीति बनी। इससे पहले ऊर्जा नीति नहीं बनती थी। एम.ओ.यू. के तहत ही प्राजैक्ट आबंटित कर दिए जाते थे। जब वर्ष 2006 में पहली बार ऊर्जा नीति बनी तो उसमें यह नीतिगत फैसला लिया गया कि हिमाचल की धरोहर और जल का अधिक-से-अधिक उपयोग कैसे किया जा सके। एक

ऊर्जा नीति प्रदेश में लाई गई जिसके तहत प्रोजैक्ट आबंटित किए गए। इस ऊर्जा नीति में यह प्रावधान किया गया कि पहले 12 वर्षों में 12% बिजली हिमाचल प्रदेश को मुफ्त दी जाएगी। जब 12-30 वर्ष पूर्ण होंगे तो 18% और 30-40 वर्ष पूर्ण होने पर 30% बिजली हिमाचल प्रदेश को मुफ्त दी जाएगी तथा 40 वर्ष बाद पूरा प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आय बढ़ाने के लिए इस नीति में एक और प्रावधान किया गया। एक मैगावाट पर मिनिमम अप-फ्रंट प्रीमियम लिया जाएगा और 10 लाख अप-फ्रंट प्रीमियम का प्रावधान रखा गया। बाद मे यह प्रीमियम 20 लाख रुपये किया गया। अप-फ्रंट प्रीमियम के लिए ओपन बिडिंग की जाएगी। उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी और ऊर्जा मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। लोगों ने 10 लाख की जगह 55-60 लाख रुपये तक ओपन बिडिंग की। जो बिडर्ज आऐ थे उन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य तीन मिनट हो गए हैं। आप चर्चा मत कीजिए, अपना विषय रखिए।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, मैं अच्छी चीज़ सदन में ला रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप इसके लिए नोटिस दे दीजिए लेकिन अभी आप इसे समाप्त करें।

28.08.2018/1240/RKS/DC-3

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, उस समय 55 लाख रुपये की ओपन बिडिंग हुई। प्रोजैक्ट आए और प्रोजैक्ट्स अवार्ड करने के बाद सरकारी कोष में 200-200 करोड़ रुपये जमा हुए। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऊर्जा नीति में बदलाव क्यों लाया गया? क्योंकि जो पावर प्रोजैक्ट लगाने वाले उद्यमी हैं वे हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम प्रोजैक्ट तो अवार्ड कर देते हैं लेकिन जो क्लीयरैंसिज होती है, चाहे वह फोरैस्ट की क्लीयरैंस हो या अन्य विभागों से क्लीयरैंस की बात हो, उसमें एक-एक, दो-दो साल लग जाते हैं और प्रोजैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हो जाती है।

श्री बी0एस0 द्वारा ज

28.08.2018/1245/बी.एस/डी.सी./-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी...

यदि उसकी कन्स्ट्रक्शन कोस्ट 500 करोड़ की होगी तो वह दोगुनी हो जाती है। इस कारण प्रोजैक्टस नहीं आते। माननीय मंत्री जी मैं सिर्फ यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम-से-कम जो भी डवैल्पर यहां पर आए, उनको सारी कलियरेंस की सुविधा सरकार खुद प्रदान करे, यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा जो आपने कहा है कि 12% बिजली हम 12 वर्ष के लिए फ्री कर देंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। S.J.V.N.L के साथ समझौता हुआ है। मैं नेपाल की बात कर रहा हूं वहां पर S.J.V.N.L ने एक समझौता किया है, वहां उन्होंने 900 मैगावाट का एक ऐसा समझौता किया कि 30% मैगावाट फ्री बिजली प्रदान करने की बात कही है। आप हिमाचल प्रदेश में कुल 12% की बात कर रहे हैं। यदि आप डवेल्पर को फायदा देना चाहते हैं तो उनकी जितनी क्लीयरेंसिज़ हैं उसको क्लीयर कीजिए। यदि आप इस तरह ऊर्जा नीति में संशोधन करेंगे तो आने वाले समय में काफी घोटाले की संभावना बढ़ जाएगी।

28.08.2018/1245/बी.एस/डी.सी./-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 63 के अन्तर्गत आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और आदरणीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस माननीय सदन में उठाया गया है। ऊर्जा नीति पर कुछ मुद्दे यहां पर उठाए गए, उन पर मैं बाद में आऊंगा । हम जानते है विपक्ष का काम मुद्दे को हाईलाइट करना, Sensational करना है और इनकी मजबूरी भी हो सकती है। .....(व्यवधान)..... हर्ष जी कृपया बैठ जाइए .....(व्यवधान)..... कृपया एक मिनट बैठ जाइए। .....(व्यवधान)..... मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।

Shri Harshwardhan Chauhan: Sir, this is not right. We are also elected representatives. We can also think about the welfare of the State. ---(Interruption)---.

अध्यक्ष : कृपया पीछे से न बोलें।

बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : मैं पूर्व में भी सरकार में मंत्री रहा हूं उसको भी में डीफैड करूंगा। चिंता मत करिए, मैं पूर्व सरकार में मंत्री था और उस वक्त सरकार ने क्या कार्य किए उसका भी स्पष्टीकरण दे दूंगा। क्योंकि ऐसा न हो कि एक ही पक्ष रखा जाए, माननीय सदन में दोनों पक्ष आने चाहिए इसलिए मैं वस्तुस्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। जो सरकार ने पावर नीति लाई है उसके बारे में कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार है :-

The Government of Himachal Pradesh has carried out various amendments in its Hydro Power Policy from time to time, but certain amendments are still required to be carried out so that the provisions of the Policy may give boost to the stalled Hydro Power Projects in a dynamic market scenario especially in

view of fast changing market and technological interventions in Solar and Wind Power. Hence, the following amendments in Hydro Power Policy were made by the Government in the year, 2018 to boost the hydro sector in HP:-

i. Deferment of free power quantum for the critical period of initial 12 years for all the allotted projects except for the commissioned projects and free power royalty he entire agreement period for the projects to be allotted.

अभी तो आपको इसका उत्तर दे रहा हूं फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अन्दर क्या हुआ है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप पूर्व की सरकार में मंत्री रहे हैं।

बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : आदरणीय मुकेश जी आपको मालूम होगा कि मैं कैबिनेट के अंदर गलत को गलत ही बोलता था। आप यह मत कहना कि दाल में काला है, मैं इस बात को पूरा कलियर करूंगा। इस पर अभी मैं उत्तर दे रहा हूं।

Continued by Sh. HK in English…

28.08.2018/1250/DT/HK-1

Continued by MPP Minister in English….

i. Entire power from the projects having capacity upto 10 MW shall mandatorily be purchased by HPSEBL at the HPERC determined generic tariff. यह आप कह रहे हैं कि ज्यादा महंगी बिकेगी इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा।

ii. The tariff shall be determined by HPERC with respect to date of achieving CoD of project instead of the date of signing of Implementation Agreement (IA).

iii. Exemption of open access charges for all projects having capacity up to 25 MW.

iv. To re-define the milestones afresh where 100% equity transfer is permitted by the Government as per the prevailing policy by entering into revised agreement.

v. To allocate projects upto 10 MW for captive use of power for existing industries or for new industrial units within the State of Himachal Pradesh without competitive bidding.

It is intimated that since the Government has recently notified the amendments in the Hydro Power Policy, in May 2018, it shall not be appropriate to assess the outcome of the changes made at this stage. Moreover, some of the developers have shown positive response towards

28.08.2018/1250/DT/HK-2

the changes and ensure to speed up the implementation of the projects. Also the Government is making all its efforts to implement the changes / amendments made in the Hydro Power Policy, results of which will be visible in the coming time. However, the following will be possible outcome of the policy changes / amendments in near future:-

i. The projects shall become more financially viable as the free power liability has been deferred for the critical period of initial 12 years which shall fetch more opportunities for financing of the projects. Since the deferred quantum will be recoverable in the subsequent period of 28 years, the Government will get back equal amount. This relaxation will boost setting up of more projects in the State. (…interruption….)

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी अभी मंत्री जी बात कह रहे हैं कृपया आप बीच में मत बोलिये।

ससंदीय कार्य मंत्रीः आप सुनना ही नहीं चाहते है। This is very bad. आपको बता रहे हैं आप सुनना ही नहीं चाहते है। (...व्यवधान) आपने जो भाषण दिया है, आपके भाषण का जबाव दे रहे हैं। यह गलत बात है।(...व्यवधान) यह आप जानबूझकर करना चाहते हैं।

अध्यक्षः मुकेश जी, यह कोई तरीका नहीं है। I won't allow. ...(interruption)..... यह ठीक नहीं है। मुकेश जी, आप बैठिये ।I won't allow. Let the Minister reply. Reply is not complete. No, this is wrong. अभी मंत्री जी का रिप्लाई पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले आप स्पष्टीकरण नहीं ले सकते। मंत्री का रिप्लाई पूरा होने दीजिए। (...व्यवधान)

ससंदीय कार्य मंत्रीः अभी तो जबाव शुरू ही नहीं हुआ। ....(व्यवधान) अगर बोलने की हिम्मत है तो सुनने की भी हिम्मत रखो। (...व्यवधान) अभी तो जबाव ही शुरू नहीं हुआ है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

28.08.2018/1250/DT/HK-3

अध्यक्षः आप उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। उनकी बात पुरी होने पर ही आप प्रश्न कर सकते हैं। (...व्यवधान) कृपया आप बैठ जाइए। (....व्यवधान)

बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : आप बैठेंगे तभी तो मैं इसका उत्तर दे सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन.जी. द्वारा .... जारी

28/8/2018/1255/एच0के0/एन0जी0-1

उर्जा मन्त्री जारी…..

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

……व्यवधान…….

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुंजिपत्तियों के दवाब में बनी है। आप इसे रिव्यू कर रहे हो के नहीं। आपने सारा हिमाचल बेच दिया है।

……व्यवधान…….

उर्जा मन्त्रीः यह सब आपके समय में हुआ है। मैं सब बताऊंगा, आप सुन तो लीजिए।

श्री हर्ष वर्धन चौहानः आप लोगों ने 10 हजार करोड़ का घोटाला किया है।

(सत्ता पक्ष के कुछ **माननीय सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े** हुए)

……व्यवधान…….

(12.57 बजे अपराह्न **विपक्ष के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए** सदन से **वॉक आऊट कर गए)**

अध्यक्षः माननीय मन्त्री जी कृप्या आप बैठ जाईए। नियम 63 के अन्तर्गत चर्चा का उचित समय दिया गया जिन दो माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए थे उनको पुरा समय दिया गया। एक माननीय सदस्य को समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त समय भी दिया गया। कुल 48 मिनट में तीनो सदस्यों ने माननीय सदन में अपनी बात को रखा है। माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुनने से पहले ही विपक्ष द्वारा इस प्रकार का एक्शन अनुचित प्रतीत होता है। यह मेरा मत है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे।

28/8/2018/1255/एच0के0/एन0जी0-2

संसदीय कार्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल वाजिब कहा है कि नियम 63 के अन्तर्गत चर्चा के लिए लिमिटिड स्कोप होता है । उसके बावजूद तीन प्रमुख सदस्यों को बोलने का पुरा समय दिया गया । चर्चा के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने अपना जवाब देना प्रारम्भ ही किया था और विपक्ष के लोगों ने बिना जवाब को सुने ही शोर मचाना शुरू कर दिया । विपक्ष के लोग हिमाचल प्रदेश की आम जनता का और टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने में तुले हुए हैं और विपक्ष के लोग यह पहले से तय कर के आए थे । विपक्ष के लोगों में आपस की अन्दरूनी लडाई के कारण एक-दूसरे से अधिक प्वाईंट स्कोर करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है । इसलिए हर मुददे पर कभी एक व्यक्ति वॉक आऊट करता है तो कभी दूसरा व्यक्ति वॉक आऊट करता है । विपक्ष के लोगों ने माननीय मन्त्री जी का पुरा उत्तर सुना ही नहीं और विपक्ष की इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है । हिमाचल प्रदेश की विधानसभा एक-एक चर्चा के लिए, एक-एक प्रश्न के लिए लाखों रूपये खर्च करती है और

श्री आर0जी0 द्वारा जारी...

28/08/2018/1300/RG/YK/1
संसदीय कार्य मंत्री-----जारी

उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। पॉवर पालिसी के ऊपर आज चर्चा हो रही है और पॉवर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिमाचल प्रदेश एक ऊर्जा राज्य है, इसमें प्रदेश के बाहर से निवेश कैसे आए और किस प्रकार से हमारे यहां ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़े। इस बारे में सरकार जो निर्णय करती है, उसके अनुसार इन्होंने यहां चर्चा मांगी है और चर्चा का उत्तर हमारे माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। इसलिए इनका इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है और मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं।

28/08/2018/1300/RG/YK/2

अध्यक्ष : माननीय बहुउद्देश्यीय परयोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी कृपया उत्तर दें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो यह शुरूआत थी, पता नहीं विपक्ष के लोग क्यों उठकर चले गए? हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए मुझे अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहा है। मुझे कल पूछा गया कि क्या दबाव था कि जो यह पॉवर पालिसी आपने बदली? मैंने कहा कि मैं किसी दबाव में नहीं होता, पिछली सरकार में भी जब मैं मंत्री रहा, यदि उसमें गलत फैसले होते थे, तो मैं उस समय भी कहता था और अब भी हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं। मैं यहां वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं क्योंकि ये विपक्ष वाले जो चर्चा कर रहे हैं, जो इन्होंने 12 साल की बात की कि 12 साल को डेफर किया। मुझे इस बात का दुःख है कि ये आंकड़े सुनने से पहले ही चले गए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आंकड़े बताता हूं। हमारे 3010 मेगावाट के अलॉटेड प्रोजैक्ट्स हैं, जो पूर्व सरकार के माध्यम से अलॉट किए गए और चिनाब बेसिन में अगस्त, 2016 में इन्हीं के सरकार के आदेश हैं, हालांकि मैं भी उस समय की सरकार में मंत्री था, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष 2016 में लगभग 1,400 मेगावाट के प्रोजैक्ट्स थे, उनकी 12 साल की जो फ्री पॉवर थी, उसको डेफर किया। यह क्या हम पहली बार कर रहे हैं? ये जो उठकर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो हमारे 3010 मेगावाट के प्रोजैक्ट अलॉटेड थे, उनमें आपने 12 साल के लिए क्यों डेफर किया? पहले यह बताएं कि इन्होंने 1,400 मेगावाट के प्रोजैक्ट्स डेफर किए? इनकी नीति क्या थी और आज इन्हें प्रदेश की चिन्ता हो रही है? क्या उस समय प्रदेश की चिन्ता नहीं थी? इन्होंने उस समय क्यों डेफर किए और आज इनको 12 साल की चिन्ता हो रही है। तो इस प्रकार से बहुत से मुद्दे हैं, सरकार ने आगे इस बात को उजागर करने के लिए कोशिश की है। चिन्ता का विषय इसलिए है कि सभी कहते हैं कि हिमाचल में हाइडिल पॉवर पोटेन्शियल है। हम भी इस बात को मानते हैं और हिमाचल के हितों के लिए सभी मानते हैं कि हिमाचल में हाइडिल

पॉवर पोटेन्शियल है। परन्तु हाइडिल पॉवर पोटेन्शियल का हम किस तरीके से दोहन करें? इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे आदेश दिए कि सभी प्राइवेट पॉवर प्रोडयूसर्ज के साथ चर्चा करो और एक नया रास्ता निकाला जाए, एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस पर हम इस ऊर्जा नीति की पर बात करें। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ

28/08/2018/1300/RG/YK/3

बिन्दुओं पर बात कहूंगा। जैसा इन्होंने अपफ्रंट प्रीमियम की बात की। इन्होंने कहा अपफ्रंट प्रीमियम के बारे में, तो यहां जंगी-थोपन पॉवर प्रोजैक्ट के ऊपर बहुत चर्चा हुई। उसमें 20,00,000/-रुपये के अगेन्स्ट 36,13,000/-रुपये अपफ्रंट प्रीमियम भरा गया। मैं भी उसी कैबिनेट में था और उसी कैबिनेट में चर्चा हुई, 280 करोड़ रुपये सरकार के पास है। परन्तु रास्ते ढूंढते रहे। मैंने इसका विरोध किया, मैंने कैबिनेट में विरोध किया और कहा कि यह सरकार के पास पैसा है, इसलिए हम किसी भी तरह इसमें रिलायंस या और किसी से आगे बात नहीं करेंगे। इसलिए हमने इसका विरोध उस समय भी किया और आज भी हम करते हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि हमारा कम्पटीशन किसके साथ है? हमारा मुकाबला पॉवर प्रोडयूसर राज्य उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर के साथ है। यदि हमारा अपफ्रंट प्रीमियम दस लाख रुपये था, तो उसको आपकी सरकार ने कम किया। यदि उसीके आंकड़ों पर हम चर्चा करें, तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो प्रोजैक्ट्स स्वीकृत हुए, उनमें आपने पांच मेगावाट से ऊपर एक लाख रुपये अपफ्रंट प्रीमियम रखा। आपने बीस लाख रुपये से कम किया, क्या तब हिमाचल प्रदेश की चिन्ता इनको नहीं हुई? आपने इसको क्यों कम कर दिया? यह तो आपका है। इनको लगा कि लोग नहीं आ रहे हैं। इन्होंने 37 प्रोजैक्ट्स अलॉट किए, कोई आने वाला नहीं था। इसलिए इन्होंने अपफ्रंट प्रीमियम कम कर दिया।

एम.एस. द्वारा जारी

28/08/2018/1305/MS/YK/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी--------

मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड ने अपफ्रंट प्रीमियम 5 लाख रुपये 5 मेगावाट से 25 मेगावाट तक किया है जबकि हमने उससे भी कम किया। आपकी सरकार ने भी कम किया। उत्तराखण्ड में तो 5 से 25 मेगावाट तक 5 लाख रुपये अपफ्रंट प्रीमियम था लेकिन आपने 1 मेगावाट का 1 लाख रुपये अपफ्रंट प्रीमियम रखा। इसका मतलब 100 मेगावाट के ऊपर 1 करोड़ रुपये हुआ। तब आपको हिमाचल की चिन्ता नहीं हुई? आप मुद्दों के ऊपर बोलिए। अभी हर्षवर्धन चौहान जी बड़े आंकड़े बता रहे थे कि यदि 12 सालों तक हम फ्री पावर नहीं लेते हैं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यह बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रदेश की हालत क्या है? यदि हम प्रदेश की हालत की बात करें तो आज हमारा हाइडल सैक्टर क्यों पीछे गया? मैंने कहा कि हाइडल सैक्टर में 10 से 12 करोड़ रुपये पर-मेगावाट इसे स्थापित करने में लगते हैं जबकि सोलर पर-मेगावाट 4 से 5 करोड़ रुपये में लगता है। आज अगर हाइडल पॉलिसी को बदलने की बात है तो आज यह बात कम्पीटीशन के कारण है। यदि वर्ष 2008-09 की बात करें तो उस समय बिजली 7 रुपये 49 पैसे बिकती थी और बिजली बोर्ड के रेगुलेटरी कमीशन ने हमें 3 रुपये फिक्स किया था। उस वक्त इतनी महंगी बिजली बिकी और फिर धीरे-धीरे घटती चली गई। उसके बाद धीरे-धीरे वर्ष 2016-17 तक 3 रुपये 53 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे कीमत आ गई। यानी बिजली की डिमाण्ड जिस तरीके से देश के अंदर होनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। बिजली बिक ही नहीं रही है। सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का आता है कि आज लोग इस सैक्टर के अंदर आने को तैयार क्यों नहीं है? मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को कहा कि इसका किस तरीके से चैनेलाइजेशन किया जाए। हमने इस बारे में चर्चा की और हम पावर प्रोड्यूसर से भी मिले। उस बात को लेकर जब हमने उनसे बात की कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है तो जैसे मैंने चिनाब बेसिन का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि चिनाब बेसिन में जो अलॉटिड प्रोजैक्ट्स थे उसका 45 परसेंट जो अपफ्रंट प्रीमियम 12 सालों में आना था, वह भी राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने किया। क्या वे इस बात को भूल गए कि 45 परसेंट आप डैफर कर रहे हैं और आज आप हम पर प्रश्नचिह्न पैदा कर रहे हैं? इसलिए आज भी हमारे पास जैसे मैंने कहा, जंगी-थोपन का 280 करोड़ रुपया है।

28/08/2018/1305/MS/YK/2

आज हमारे पास लगभग 10 प्रोजैक्ट ऐसे हैं जो हाथ खड़े कर चुके हैं। 300 करोड़ रुपया अपफ्रंट प्रीमियम का हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन लोग प्रोजैक्ट्स छोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं लगा सकते हैं। फिर आप इस बिजली दोहन को कहते हैं कि 15 साल लटका दो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी पॉलिसी के ऊपर चलते तो हिमाचल के अंदर टैलीकॉम रेवोल्यूशन लेकर नहीं आती। इसलिए परिवर्तन लाना पड़ता है और दोहन भी समय पर होना चाहिए। एक बात हर्षवर्धन जी ने कही कि आज बिजली सस्ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 12 साल के बाद जब हम 5.17 परसेंट और उनसे लेंगे यानी जब हम 12 परसेंट से 18 परसेंट लेंगे तो 18 परसेंट के ऊपर 5.17 परसेंट और चार्ज करेंगे तो उस वक्त बिजली का रेट क्या होगा? क्या आपने इस बारे में इकॉनोमिस्ट से कोई वर्कआउट किया है कि उस वक्त हिमाचल को ज्यादा रेट मिल सकता है? आज यदि हाइडल के साथ थर्मल की बात करे तो इन 15 सालों में थर्मल किसी भी वक्त धीरे-धीरे कम हो सकता है। हमने आय के साधन को डैफर किया है उसको खत्म नहीं किया है। यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि हमने 12 साल की रॉयल्टी छोड़ दी। हमने वह रॉयल्टी छोड़ी नहीं है बल्कि डैफर की है। आप ऐसा कर सकते हैं परन्तु हम नहीं कर सकते। यहां पर सुखविन्द्र सिंह जी ने अपफ्रंट प्रीमियम की बात को उठाया लेकिन अखबारों में कहीं चर्चा नहीं आई। मुझे इस बात की खुशी है और मैंने इसका जिक्र कई बार अखबारों में भी किया कि पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, क्योंकि हमारे संबंधों का सभी को पता है और जब उनको गुस्सा आता है तो वे मुझे कई कुछ बोल देते हैं। परन्तु इन्होंने एक बार मेरा हाथ पकड़कर कहा कि जो काम हम नहीं कर सके, वह हिम्मत आपने की है। इसका मतलब वे दिल से इस बात को जानते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर हिमाचल के लिए कुछ किया जा रहा है और यही कारण है कि जो हमने प्रोजैक्ट की बात कही बल्कि मैं तो इसको कैलकुलेट करके आया था कि जब आपने अपफ्रंट प्रीमियम कम किया तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने प्रोजैक्ट आपके अलॉट हुए? आपको केवलमात्र 9 प्रोजैक्ट अलॉट हुए और 9 प्रोजैक्ट्स में आपके पास वे एग्रीमैंट इम्प्लीमैंट करने भी नहीं आए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा जारी---

28.08.2018/1310/जेके/एजी /1

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः-----जारी-----

इसका मतलब अपफ्रंट प्रीमियम 1 लाख 15 हजार जब ऐसे इन्होंने भर कर दिया तो मात्र 1,55,34,800/-रूपए अपफ्रंट प्रीमियम इन 9 प्रोजैक्ट्स में मिला है जबकि यदि 20 लाख होता तो 27 करोड़ 36 लाख रूपया मिलता। आप इस बात को भूल गए कि अपफ्रंट प्रीमियम आपकी सरकार ने कम किया था और यह सोच कर किया कि बिजली उत्पादक आएंगे और यहां पर बिजली का दोहन करेंगे। इस तरह के भ्रामक प्रचार करते हैं। जब आप फ्री पावर की बात करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास पावर प्रोड्यूसर्ज़ आते हैं। वे इस बात की चर्चा करते हैं कि आपका प्रदेश क्या औरों से भिन्न है? हम उनको क्या ज़वाब दें? यदि हम उत्तराखंड की बात करें, 2 मैगावाट की अब हम बात करते हैं, 2 परसेंट 12 साल के लिए, 12 परसेंट 18 साल के लिए और 18 परसेंट हम 10 साल के लिए करते हैं। जबकि हमारा जो मापदण्ड है, 2 से ऊपर की बात है परन्तु जहां पर 5 से 25 की बात आती है उसमें उन्होंने 15 साल तक फ्री किया हुआ है। 15 साल तक कुछ भी रॉयल्टी नहीं लेते हैं। एक तरफ उत्तराखंड है जहां 15 साल तक फ्री पावर है जबकि हम ले रहे हैं। पहली साल से हम उनका मीटर घुमाना शुरू कर देते हैं। जब वे हमारे पास आए और इस बात की चर्चा की, उन्होंने कहा कि यदि हमें 12 साल का समय दिया जाए क्योंकि हमने जितना लोन लिया होता है, फाइनैंशियल लाइबिलिटी हमारी नहीं बनती है इसलिए इस बात को देखा जाए। इस बात के लिए हमने प्रयास किया और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज लोग सस्ती बिजली क्यों लें? यदि बिजली बोर्ड को कोई सस्ती बिजली बेचता हो वह हमसे क्यों लेगा? हाइडल प्रोजैक्ट्स से क्यों लेगा? प्रश्न इस बात का है। मैं कुछ इशूज़ इस माननीय सदन के सामने लाना चाहता हूं लेकिन विपक्ष के लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि इन्होंने आज खबर बनानी थी कि पावर पॉलिसी के ऊपर हमने बहिष्कार किया। अरे, आप सुन तो लेते तब जा कर बहिष्कार करते परन्तु आपके मन

में इतना डर था और आपको पता था कि हमसे कहीं ऐसी बात न निकल जाए। यदि सोलर की हम बात करें, आज 4-5 करोड़ रुपये से प्रेति मैगावॉट बिजली सोलर से पैदा कर सकते हैं। मैं यहां पर बिजली बोर्ड की बात करना चाहता हूं और मुझे इस बात का दुख है

28.08.2018/1310/जेके/एजी /2

कि जब मुझे यह विभाग दिया गया तो मैं देख रहा था कि ऊहल स्टेज-III हमारा बिजली बोर्ड का प्रोजैक्ट जो कि 111 मैगावॉट का प्रोजैक्ट है और उसमें हमारे 15 साल लग गए। 15 सालों में 1500 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं। मैंने उनको कहा कि उसका कब उद्घाटन होगा तो 15 सालों में उसके पेन-स्ट्रोक के नट बोल्ट लूज़ हो गए। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इसमें कौन इन्वैस्टर आएगा जबकि हमारी स्टेट के अपने एक-एक मैगावाट के प्रोजैक्ट्स के लिए 15-15 करोड़ रूपया लग रहा है। इसलिए सबसे बड़ा इशू यह है कि हम प्राइवेट प्रोड्यूसर के माध्यम से ही इस प्रोजैक्ट के अन्दर, क्योंकि यहां पर कई बार इन्होंने कहा तो हम हाइड्रो पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रो पॉलिसी के ऊपर हम 12 परसेंट फ्री पावर 12 सालों के लिए प्लस 1 परसेंट और उसके बाद 18 प्लस 1 परसेंट और 30 सालों के लिए उसमें 30 परसेंट 10 सालों के लिए और लेते हैं परन्तु सोलर में जीरो परसेंट है। सोलर में हम नहीं लेते हैं। इस तरह से यदि आप कॉम्पीटिशन का कम्पैरिज़न करेंगे और कैट प्लान में तो हम 28 परसेंट लेते हैं, सोलर में क्या लेते हैं? यदि हम कहते हैं कि एल0ए0डी0एफ0 के ऊपर हम एक-डेढ़ परसेंट प्रोजैक्ट के ऊपर लेते हैं। यहां क्या लेते हैं, कुछ नहीं। आप यदि जी0एस0टी0 की बात करते हैं तो जी0एस0टी0 18 परसेंट में हम बिजली बेचते हैं और 18 परसेंट जी0एस0टी0 हाइडल के ऊपर देते हैं। सोलर के ऊपर 5 परसेंट है। अब आपकी हाइडल बिजली किस कीमत में होगी कभी यह सोचा है? हाइडल बिजली हम वहां किस कीमत में बेच सकते हैं, यही बहुत बड़ा इशू है। जहां तक हाइडल पॉलिसी के ऊपर लाभ लेने की बात है, इसको यहीं रोक दिया जाए या हमारे पास जो बहता सोना है उस बहते सोने का दोहन कर लिया जा

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

28.08.2018/1315/SS-AG/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री क्रमागतः

नोशनल लॉसिज़ की बात करते हैं कि इतने करोड़ लॉसिज़ हो जायेगा। मैंने कहा कि जब आपका अपफ्रंट प्रीमियम कम हुआ था तो कितना लॉस हुआ था क्या तब आपने कैलकुलेट किया था? तब तो आप उठकर चले गए थे। आपने क्यों अपफ्रंट प्रीमियम कम किया? जबकि जंगी थोपन में 36 लाख रुपया अपफ्रंट प्रीमियम हमारे को आया था। अपफ्रंट प्रीमियम आपने क्यों कम किया? आपको मालूम था कि आपके पास प्रोजैक्टस लगाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि हम नई सोच के साथ आगे आए। बिजली बेचने वाली संस्था क्यों महंगे रेट में बिजली लेगी? इसी कारण से ये सभी डिसीजन लिये गए। आप चर्चा करें। जिस मंच पर आना है आएं और चर्चा करें। चर्चा से क्यों भागते हैं? आपने जो मुद्दे उठाए, वे क्या मुद्दे थे? आपने किन मुद्दों पर बात की। 12 परसैंट के मुद्दे पर बात की। मैंने हर्षवर्धन चौहान की बात की। आज अगर ढाई या पौने तीन रुपये में बिजली बिकती है तो क्या 12 साल के बाद हो सकता है कि पांच या छः रुपये में बिके तो कितना पैसा स्टेट को आयेगा? हमने स्टेट के साथ कहां कम्प्रोमाइज किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भूल जाईये क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं है और न मैं काला होने देता हूं। उस वक्त प्रोजैक्टों की बात आती थी कि अपफ्रंट प्रीमियम में इन्हें दे दिया जाए। मैंने कहा कि कुछ नहीं है, सरकार का पैसा है और सरकार के पास ही रहेगा। मैं आज भी आपको हाउस के अंदर आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो पावर हाईडल पॉलिसी लाए हैं, वह सही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि वे ऐसे मुख्य मंत्री हैं जोकि हर विभाग को समझने की कोशिश करते हैं। हमने भी बात की। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि पैसा कहां से आयेगा, हम इसका जवाब देंगे। नोशनल लॉसिज़ कह सकते हैं कि यदि ये होता तो इतने करोड़ का होता। क्या प्रोजैक्ट लग गया? आपके टाइम में कितने प्रोजैक्टस लगे? आप हमें बताएं। मैंने आपको आंकड़े दिए और अगर आपने अपफ्रंट प्रीमियम कम किया तो आपके कितने प्रोजैक्टस लग गए? लोग फिर भी क्यों नहीं आ रहे हैं? आज हमने रास्ता खोला है और मैं इस बात को माननीय सदन में कह सकता हूं। हो सकता है कि हम इसमें

कामयाब न हों। हमें इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं, यह तो भविष्य पर निर्भर करता है लेकिन हमने एक रास्ता खोलने का प्रयास किया है। मिल बैठकर हिमाचल के हितों के लिए एक नया रास्ता खोलने की हमने बात की है।

28.08.2018/1315/SS-AG/2

एक बात इन्होंने और की कि 25 मैगावाट की फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं होगी। पता नहीं ये कहां से पढ़ कर आ जाते हैं? कहां से ऐसी सैनसेशनल खबर बनाकर ले आते हैं? जिससे पता लगे कि इंवायरनमैंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहा गया कि 25 मैगावाट के प्रोजैक्टस रूकेंगे। क्लीयरैंस नहीं मिलेगी, जिसे लेने की ज़रूरत है। अरे, मुकेश जी, आप मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे। मैं जानता हूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, आपको बधाई हो। परन्तु कम-से-कम जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, आप उसको लेकर आईये। तभी फायदा होगा। अगर आप गलत आंकड़ें देंगे तो वे गलत आंकड़ें जनता के बीच में जायेंगे। इसलिए आज भी हमारे पास हाईडल प्रोजैक्टस के लिए फॉरैस्ट इंवायरनमैंट क्लीयरैंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाईडल प्रोजैक्टस लगाने के लिए हमारे पास कई प्रोजैक्टस 8-8, 10-10 सालों से फॉरैस्ट इंवायरनमैंट क्लीयरैंस के लिए वैसे ही पड़े हुए हैं। आज इस क्षेत्र में लोग आना चाहते हैं परन्तु आज हमारी स्थिति विकट है। मैं हाउस के सामने इस बात को भी कहना चाहता हूं कि मैंने किन्नौर और दूसरे क्षेत्रों का दौरा किया, मैंने वहां के हाईडल प्रोजैक्टस के लोगों से बात की। आज हमारे पंचायत के लोग हाईडल प्रोजैक्टस के लिए एन0ओ0सी0 नहीं देते हैं। आज लूटने में लगे हैं। मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ प्रोजैक्टस लगे तो वे उस हालात में लगे जब पावर सैक्टर में बिजली की डिमांड थी। आज वह बात नहीं है। आज पंचायत कहती है कि हमें यह भी दे दो। बहुत-सी ऐसी पंचायतें हैं जो पैसा मांग कर एन0ओ0सी0 देंगी तो आज एन0ओ0सी0 के चक्कर में भी प्रदेश के अंदर हाईडल प्रोजैक्टस नहीं लग रहे। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। हम भी चाहते हैं कि हिमाचलियों को नौकरी मिले। परन्तु मैं देखना चाहता हूं कि हिमाचल के लोगों को नौकरी किस आधार पर मिलनी चाहिए। काम भी होना चाहिए, जो बाहर से प्रोजैक्टस लगाने आते हैं क्या वे इस वातावरण में सरवाइव कर सकते हैं? मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री बॉर्डर एरियाज़ में है। परन्तु पावर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां रोजगार मिल सकता है। इसमें आमदनी के साधन हैं।

लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड में पैसा है और एक परसैंट फ्री पावर भी लोगों को मिलती है। मैं विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि कौल डैम से लगभग 11 करोड़ रुपये की एक परसैंट फ्री पावर वहां के लोगों को मिलेगी। इस तरीके से इतने पैसे का प्रदेश के लोगों को फायदा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस चर्चा को उठाया गया,

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2018/1320/केएस/डीसी/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी---

मैं चाहता हूं कि यह चर्चा और अधिक होती और बहुत से मुद्दे सरकार के सामने आते। इन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए इसको क्यों नहीं लाया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने अप फ्रंट प्रीमिअम कम किया तो क्या आप सदन में आए थे? जब चुनाव में आपने 45 परसेंट अलॉटिड प्रोजैक्ट्स को 12 सालों के लिए डिफ़र कर दिया, तब क्या आप विधान सभा के अंदर आए थे? यदि आप हमें कहते हैं कि हमें चर्चा के लिए आना चाहिए तो हम चर्चा के लिए तैयार है । आदरणीय मुख्य मंत्री जी हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और उसके लिए आपके सुझाव आने चाहिए। केवल राजनीतिक रंग देने के लिए आप चर्चा में आए, यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार ने जो ऊर्जा नीति बनाई है, यह खासकर लोगों के रोज़गार के लिए हैं और उन लोगों के लिए है जो इसमें आना चाहते हैं। हमारा सफ़र यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। हम प्रयास करेंगें कि और प्रोजैक्ट्स लाने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। ये कहते हैं कि दोहन 15 साल के बाद करें । ठीक है, आप कहते हैं लेकिन 15 सालों के अंदर हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, कितना रेवन्यू ला सकते हैं ? अध्यक्ष जी, इनको इस बात की चिन्ता नहीं है। ये कहते हैं कि 15 साल छोड़ दो, 15 साल के बाद देखेंगें। क्या इस सोच के साथ यह सदन आगे चलना चाहता है, यह सरकार चलना चाहती है? अन्त में अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैंने सरकार का पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया है। विपक्ष के लोग आंकड़ों के

ऊपर जो भी बात रखेंगें, उसका मैं जवाब दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्षः इससे पहले कि दोपहर के भोजन के लिए हाउस अडजॉर्न किया जाए, मैं एक शुभ सूचना देना चाहूंगा कि आज हमारे उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी का जन्मदिन है। उनको हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जहां भोजन का कमरा है, ये वहां पर मिठाई जरूर खिलाएंगें।

अब इस सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

28.8.2018/1430/av/hk/1

विधान सभा की बैठक दोपहर के भोजन के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में 2.30 बजे (अपराह्न) पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्ष : नियम-130 के अंतर्गत श्री अनिरुद्ध सिंह जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसलिए ये लोग भी चर्चा में भाग ले सकेंगे।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम- 130 के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि "शिमला शहर की पेयजल समस्या पर यह सदन विचार करें।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि"शिमला शहर की पेयजल समस्या पर यह सदन विचार करे।"

इससे पूर्व कि अनिरुद्ध जी अपना विषय रखें, मेरा पक्ष और विपक्ष से आग्रह है कि आप दो-दो नाम इस पर बोलने के लिए हमें दे दें। नामों की संख्या अधिक होने के कारण विषय पूरा भी नहीं आता और मंत्री जी को पांच बजे से पहले इसका उत्तर भी देना है।

श्री अनिरुद्ध सिंह श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2018/1435/TCV/HK-1

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शिमला शहर में पानी की समस्या के बारे में विचार रखना चाहूंगा। शिमला शहर में पानी की समस्या आज की नहीं है। जब हम छोटे थे या स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी गर्मियों के दिनों में पानी टैंकर से बाल्टियों में लाते थे। हिन्दुस्तान में शिमला, डलहौजी, मंसूरी या शिलांग चाहे कोई भी हिल स्टेशन हो, वहां पानी की कमी रहती है। परन्तु इस बार हमने पानी की जो कमी देखी है, वह जीवन में कभी नहीं देखी। पानी कुछ कुदरती रूप से भी कम हुआ था लेकिन मिस-मैनेजमैंट की वज़ह से इतने क्राइसिज़ हुए हैं। इसको न केवल नेशनल न्यूज ने कवर किया बल्कि इंटर-नेशनल न्यूज चैनल, बी0बी0सी0 और सी0एन0बी0सी0 ने भी हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की इस न्यूज को कवर किया। शिमला शहर में पानी के लिए सभी सरकारों ने प्रयास किए हैं। परन्तु एक पुख्ता प्रयास नहीं किया गया। इसके बारे में शॉर्ट-टर्म सोचा गया, लांग-टर्म नहीं सोचा गया। पानी की स्टोरेज के लिए पहले एक रिज का टैंक हुआ करता था, लेकिन अब हर वार्ड में टैंक्स बनें हैं। हम लोग रोज़ पढ़ते हैं कि रिज धंस रहा है। क्योंकि जब वह बनाया गया था तो 80 साल उसकी लाइफ थी और आज उसको बने हुए 120-140 साल हो गये हैं। आज तक उसकी दरारों में सीमेंट डालकर रिपेयर की जाती रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहला काम रिज पर बने इस टैंक को नये सिरे से बनाने का काम होना चाहिए। आपके पास 'स्मार्ट सिटी' और 'अमृत' का पैसा है। उस पुराने टैंक को तोड़कर नये सिरे से बनाना चाहिए। सभी वार्डज़ में टैंक्स बने हैं, कुछेक रह गये होंगे, उनकी कपैसिटी बढ़ाने की जरूरत है। लोगों के पास पहले 500-1000 लीटर से बड़ी टैंकी नहीं हुआ करती थी क्योंकि हररोज पानी आता था। लेकिन आज दूसरे या चौथे दिन पानी आ रहा है। इसलिए लोगों ने अपनी स्टोरेज़ कपैसिटी बढ़ा ली है। आज हर घर में 4000 से 6000 लीटर पानी की स्टोरेज कपैसिटी रहती है। आजकल 3-3 घण्टे पानी आ रहा है, हर घर को 8-10 हजार लीटर पानी एक टाइम में आ रहा है। अगर हम इसको पहले से ही रेशनेलाईज करें कि हर घर को 2000 लीटर तक पानी

हररोज देना है तो लोग भी उसी हिसाब से पानी इस्तेमाल करेंगे। अभी 'स्मार्ट सिटी' और 'अमृत' में काफी पैसा आया है जिसकी सैंक्शन माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में हुई है। कोलडैम प्रोजेक्ट भी राजा साहिब के टाइम में आया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पानी की

28.08.2018/1435/TCV/HK-2

समस्या का हल करने के लिए सभी सरकारों को प्रयास करना चाहिए। ये समस्या पब्लिक की है, हम और आप तो समस्या सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए जल्दी-से-जल्दी पानी को लाया जाये। हमने नगर निगम एरिया में या उससे बाहर भी पानी के नये मीटर तो लगा दिए हैं। परन्तु मीटर लगाकर या पानी का रेट बढ़ाकर काम नहीं चलेगा, लोगों को सुविधा देने से काम चलेगा। नगर निगम, शिमला में माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, श्री विक्रमादित्य जी और मैं भी मेंबर हूं। नगर निगम के हाउस ने अप्रैल से मीटर रिडिंग-वाइज़ बिल्ज देने का फैसला तो कर लिया है। परन्तु जब पानी आया ही नहीं, उसका बिल देने का फैसला नहीं किया है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी।

28-08-2018/1440/NS/YK/1

श्री अनिरूद्ध सिंह -----जारी

यहां पर दो महीने पानी की बहुत किल्लत रही है। जितनी भी हमारी मशीनें हैं, चाहे गुम्मा अश्वनी या चेयड़ खड्ड से पानी आ रहा है और लगभग छः जगहों से शिमला के लिए पानी आता है और इनमें से पांच खड्डें मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही पड़ती हैं। अगर आप इन सबकी स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सबकी मशीनें पुरानी हैं। आपने कई जगहों पर नई मशीनें रिप्लेस कर दी हैं और नई मशीनें आई हैं, नये टैंक्स बने हैं तथा फिल्टर टैंक्स

और ज्यादा बनाये गये हैं। आपकी यह बात ठीक है। नई पाइपलाइन्ज़ भी बिछ रही हैं लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में पानी की कभी भी दिक्क्त न आये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा। मैं यहां पर पानी की कमी का कारण बताना चाहूंगा। यहां पर मुख्य सचिव जी भी बैठे हैं और आप सब इसको समझेंगे। यहां पर पानी की समस्या से सबसे ज्यादा टूरिज्म सैक्टर प्रभावित हुआ है। सरकार ने गैर जिम्मेदार तरीके से एक एडवाइज़री जारी की और यह एडवाइज़री अधिकारियों द्वारा टूरिज्म सैक्टर के लिए जारी की गई थी और इसमें कहा गया था कि आप शिमला में न आयें। इसकी वज़ह से टूरिज्म सैक्टर में 30% काम भी नहीं रह गया है। अगर आज कोई पर्यटक आ रहा है तो वे पहले यह पूछ कर आते हैं कि शिमला में पानी के क्या हाल हैं। इससे न केवल टूरिज्म सैक्टर बल्कि हर सैक्टर प्रभावित हुआ है। होटलों में लोगों ने अपने कर्मचारी कम कर दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दोबारा यह नहीं कहा कि अब शिमला में हालात ठीक हो गये हैं। अभी सड़कें खराब हुईं तो इसके लिए भी यह बोल दिया गया कि पर्यटकों को परवाणू में ही रोक दिया जाये। This gives the bad name to our city. इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सर, मैं यहां पर पानी से संबंधित ही बात कर रहा हूं। पानी की कमी क्यों है? होम-स्टे और बी0एन0बी0 (ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट) स्कीमें कोई सैंट्रल गवर्नमैंट की है और कोई स्टेट गवर्नमैंट की हैं। These are Schemes. जब हमारा कॉमन वैल्थ हुआ था तो उस समय ये स्कीमें आई थी। लेकिन इन स्कीमों के ऊपर कोई रूल नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कम-से-कम 1000 कमरा, जिसमें अधिकारियों (IAS and HAS) के कमरे भी शामिल हैं, वे अन-रजिस्टर्ड हैं। ये कमरे न तो बी0एन0बी0 और न ही होम स्टे में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन शिमला के अंदर चले हुए हैं।

28-08-2018/1440/NS/YK/2

होम स्टे तो शिमला से बाहर मर्ज़र एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल होता है और बी0एन0बी0 शहर के लिए एप्लीकेबल होता है। ये अभी ऐसे ही चल रहे हैं। पीछे पर्यटन विभाग ने छोटा शिमला में रेड मारी थी तो उनका बिजली और पानी के कनैक्शन काटे थे। अध्यक्ष महोदय, इसको चैक करने की बहुत जरूरत है। जहां रेजीडैंशियल एरियाज़ में 1000 कमरे छोटे से

शहर में चलेंगे तो पानी की दिक्कत नेचुरली ही आएगी और सीवरेज़ की समस्या भी आएगी। क्योंकि हमारी लाइन्ज़ पर्याप्त नहीं हैं। यहां पर एन0जी0टी0 ने ऑर्डर पास किया है कि यहां पर अढ़ाई मंजिल से ऊपर मकान नहीं बनेंगे। हमारे सरकारी वकील उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाये और लोड बियरिंगे केपेस्टिी पर इसको रिजैक्ट कर दिया गया कि शिमला अब इतना लोड सहन नहीं कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी क्यों आ रही है? यह भी लोड बियरिंग बढ़ाने के लिए आ रही है। पानी की लाइन्ज़ पानी बढ़ाने के लिए आ रही हैं। सरकारी वकील इस बात को एन0जी0टी0 को एक्सप्लेन नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय, ये सब मेरे प्वाईंट हैं। पानी के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जो अभी failure हुआ है that was utter failure of the Govt. इसके बाद भी पानी उतना ही था। हर साल जिलाधीश महोदय कॉर्पोरेशन के गर्मियां शुरू होने से पहले टैंकर के एडवांस टैंडर करते थे। लेकिन इस बार ये टैंडर ही नहीं हुए और ये टैंडर पानी की दिक्कत होने के बाद हुए हैं। आप चाहें तो इसकी डेट देख लीजिये। आप इसको मिस-मेनेज़मैंट बोल सकते हैं। बाद में कैसे पानी ठीक हुआ। जब लोगों ने धरना देना शुरू किया और जिस वार्ड में लोग धरना देते थे उस वार्ड में शाम को पानी आता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हर वार्ड वालों में कम्पीटीशन छिड़ गया कि जो धरना देगा, वहीं पर पानी आएगा। इससे हमारे राज्य/शहर की गरिमा पूरे देश में बहुत ही खराब हुई है और इसको सुधारने की जरूरत है। शिमला शहर को पथ के ऊपर दोबारा से उसी गरिमा से ऊपर लाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विभाग माननीय महेन्द्र सिंह जी के पास है और वे बहुत सक्षम व्यक्ति हैं तथा अगली बार ऐसी दिक्कत नहीं आयेगी, वे इसका इलाज़ करेंगे व पूरा प्रबन्ध भी करेंगे ताकि हमारे शिमला शहर का नाम ऊपर रहे। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.08.2018/1445/RKS/YK-1

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नियम-130 के अंतर्गत शिमला शहर की पेयजल समस्या के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। निश्चित तौर से यह समस्या पूरे प्रदेश के अंदर और खासतौर पर शिमला शहर में मई-जून के महीने में उत्पन्न हुई, this is completely unprecedented and has left very bad mark on the Government and tourism economy of the State. यह बहुत ही आइरोनिकल है। पिछले कल हम टूरिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। पानी की समस्या के कारण टूरिज्म इकॉनमी को प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन हम इसके बारे में विचार नहीं कर पाए। जहां एक ओर प्राकृतिक आपदा की समस्याएं हैं, चाहे इरैटिक रेन फॉल हो या इंटरमीडिएट डाउनपोर की समस्या हो। कभी-कभी बहुत पानी आ जाता है और कभी पानी की कमी हो जाती है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हैं जिनको हम दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन इससे हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते। हम यहां पर केवल सरकार की निंदा करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। We are trying to provide some important suggestions on how we can improve the water problem in the town. शिमला के लिए तीन मुख्य खड्डों, जिनमें नोटी खड्ड, गुम्मा, अश्वनी खड्ड और गिरि खड्ड, से पानी की आपूर्ति होती है। पहले यहां पर अश्वनी खड्ड से भी पानी आया करता था because of the jaundice problem, जो पीछे हुई उसके कारण वहां से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। इन सोर्सिज में जो अनसाइंटिफिक तरीके से डंपिंग और सिल्टिंग हो रही है उसकी वजह से भी हमारे सोर्सिज सूखने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुम्मा स्कीम 1921-22 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। इस स्कीम में जो पाइपें बिछाई गई हैं, वे उस समय की बिछी हुई हैं। कई जगह इन पाइपों को मोडिफाई जरूर किया है मगर अभी तक जो ब्रिटिश काल का सिस्टम है that has found to be more reliable because of it quality which was used at that point of time. Over the period of successive Governments the quality of pipes and the quality of machinery has been deteriorating जिसकी वजह से आज हमें यह समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जब यह

28.08.2018/1445/RKS/YK-2

संकट शिखर पर था, जो शिमला की इंस्टॉल्ड वाटर कैपेसिटी है that is 54 MLD जो शिमला को चाहिए। पीक सीजन में शिमला को केवल 9 एम.एल.डी. पानी ही मिला, which I think is unprecedented and it was totally uncalled for. This water crisis was only because of the mismanagement of the Shimla Municipal Corporation and the Government of Himachal Pradesh. जहां तक अंधाधुंध शोषण की बात है जैसा मैंने कहा कि I don't want to blame only the Government for this, there has been exploitation of the natural resources चाहे वह ट्यूबवैल्स की बात हो या हमारे किसान-बागवान जिन्होंने वहां पर खेती-बाड़ी करना और सब्जी उगानी शुरू कर दी है। पहले वहां पर दालों व गेहूं की फसल उगाई जाती थी। लेकिन अब वहां पर सब्जियां उगाई जा रही हैं जिसके कारण ज्यादा वाटर कंजम्पशन हो रहा है। उसको हमने कैसे सुलझाना है that is also very important. We cannot develop the people of Shimla Urban at the cost of the people of Shimla Rural. The balance and equilibrium has to be maintained between both of them and this is something which needs to be decided on priority bases . अध्यक्ष महोदय, पीक सीजन के समय शिमला शहर के अंदर कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों को रिकॉर्ड 12 दिन तक पीने-का-पानी नहीं मिला। यहां पर शिमला शहर के माननीय विधायक भी बैठे हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

28.08.2018/1450/बी.एस/ए.जी./-1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी...

शिमला के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि 12-12 दिन तक उनको पीने का पानी नहीं मिला। मैं अखबार में पढ़ कर हैरान रह गया कि कनलोग के एक बॉर्ड में सिवरेज का

मिला हुआ पानी उन लोगों को दिया जा रहा था। हमारी जो माननीय महापौर है। would say that it is completely inhuman जिस वक्त यह सारा घटनाक्रम शिमला में हो रहा था she was on international visit to China क्या उनकों इतनी समझ नहीं थी कि वह अपना अन्तर्राट्रीय कार्यक्रम को रद्द करके शिमला में आती और इस मामले का संज्ञान लेती। हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं There has not even a single statement from the Urban Development Minister on the issue. उनको कम से कम धर्मशाला से बैठ करके यहां के इशूज के बारे में तो कुछ कहना चाहिए था। जो हमारे नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव हैं on record 11 days he was in Delhi at a time when this unprecedented water crisis were there in the State and to top it all हमारे अधिकारी इसमें सलाह दे रहे हैं वे पर्यटकों को यह सलाह दे रहे हैं कि आप शिमला न आए। वे unsolicited advice दे रहे है। The Government should tame their officers and ask them that they should only give statements which are called for by the Government and the Chief Minister जो अधिकारी बिना मतलब की स्टेटमेंट देते हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक Substantial Analysis Report है इस में अपने मन से नही कह रहा हूं। This is a report that has been done and I would like to quote this report. It says that the operations are sub-optimal given the wear and tear of the aging assets, weak legacy system and practices which result in low service levels such as low per capita supply, unreliable supply and deterioration of water quality level हम लोगों को इसको देखने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने इस पर कड़ा

28.08.2018/1450/बी.एस/ए.जी./-2

संज्ञान लिया और काफी मिटिंगस इस बारे में कॉल की थी और नई पाइपलाइन डालने की कोशिश की है। But I think that was too little and too late जब हमें पता था कि इस तरह की समस्या शिमला शहर में आने वाली है then what stopped the Government

to have these precautionary measures well in advance when we have the reports of Meteorological Department with us. Why did the Government not take the precautionary measures and why did they force the people of Shimla to undergo such kind of problems which they went during these three months when this problem was at its peak? जहां तक शिमला शहर की बात करें यह एक पहाड़ी क्षेत्र में है यहां पर माननीय मंत्री महोदय, जो समस्या आती है वह यह है कि जिन पाइपों से पानी सप्लाई हो रहा है वे ऐवरेज 30 मीटर से ज्यादा लम्बाई की नहीं होती है। निश्चित तौर से जब रेजिडेंशल एरिया में कनेक्शन का भार पड़ता है, बहुत से लोग कनेक्शन मांगते हैं उसमें प्रेशर इशू क्रियेट होते हैं। frictional loses होते हैं and it also leads to pilferage. मेरा यह निवेदन रहेगा कि जो शहर के अंदर पानी की सप्लाई है उसमें हमने कैसे पाइपों को सही करना है इसे देखने की आवश्यकता है। एक रिनाऊंड एनवायरमैंटलिस्ट शिमला शहर के हैं श्री हरीश ठाकुर जो हमारे युनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं Shri Harish Thakur also spoken about this. He says that it reflects the sheer operational and strategic management failure of the Government in mending demand of town and suburbs. I would not only say that it is because of the current Government but it is because of the successive Governments जितनी इसमें प्राथमिकात मिलनी चाहिए थी I would like to given the Hon'ble former Chief Minister of Himachal Pradesh and the Hon'ble former Irrigation and Public Health Minister, Madam Vidya Stokes, the credit

28.08.2018/1450/बी.एस/ए.जी/-3

for initiating the Kol Dam Project for Shimla मेरा निवेदन सरकार के रहेगा कि They should take this on priority इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप न करें कीचड़ उझालने का काम न करें। इस प्रोजैक्ट को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए। पानी की किल्लत हमने शहर के अंदर देखी है उसे हम खत्म कर सकें।

श्री डी.टी. द्वारा जारी....

28.08.2018.1455/DT/AG-1

श्री विक्रमादित्य सिंह....जारी

अध्यक्ष महोदय,मैं दो मिनट और लूंगा। यहां पर टैंकरों की बात की जा रही थी। जब यह अनप्रिसिडेंटिड वाटर क्राइसिज शिमला के अन्दर हुआ तो शिमला के अन्दर बहुत ऐसे मोहल्ले हैं, and I was shocked to see that Hon'ble, the Acting Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Shri Sanjay Karol was forced to come out to various wards क्या यह ज्यूडिशियल एक्टिविजम है, क्या यह सरकार पुरी तरह से फेल हो चुकी है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को जगह-जगह वार्ड में जाना पड़ रहा है। पानी के टैकंर केवल V IP एरियाज़ में मुहैया करवाये जा रहे हैं। पिछले कल यूथ कांग्रेस की रैली में फटाफट 3 टैकंर पानी फैंकने के लिए आ गए गए। मगर जिन लोगों को पानी चाहिए था उनके लिए कोई टैकंर की सुविधा नही थी। यह इस तरह की राजनीति हम नही कर सकते हैं। We are educated people. We need to come on board. मंत्री महोदय इन ईश्यूज में हमें सैंस्टिविटी और कम्पैशन इन दो शब्दों को गंभीरतापूर्वक लेना होगा। सब को एक मंच पर आकर इन चीजों को देखना होगा। अन्त में , मैं अपनी बात पर्यटन को लेकर खत्म करूंगा। अभी माननीय अनिरूद्ध सिंह जी ने भी यह बात कही थी कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मगर लंदन की अख्बारों में और न्यूयोर्क टाइम में भी यह खबर आई that the former erstwhile capital of British India is facing tremendous water situation और जो ये advisory unsolicited/ uncalled for advisory जो ये सरकार के लोग दे रहे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टूरिस्ट आए या न आए। ये चीजें हम लोगों को देखनी है कि टूरिस्ट यहां पर आए, इकोनॉमी बढ़े और प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिले। माननीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि

शिमला शहर में पानी की समस्या को पूरा करने के लिए करे। कोई जोड़ तोड़ न करें। शिमला ग्रामीण की जो घरोग- घंडल स्कीम है वहां से मुझे बिना पूछे रातों रात पानी ले

28.08.2018.1455/DT/AG-2

लिया गया। 105 करोड़ रुपये की वह स्कीम राजा वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण के लिए लाई थी।

Speaker: Please wind-up

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, that was built within a stipulated period of three years जो 45 पंचायतों को पीने का पानी मुहैया करवा रही है। वहां से पानी टांका मारकर शिमला शहर को लाया जा रहा है। यह चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

28.08.2018.1455/DT/AG-3

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी ।

श्री राकेश पठानियाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के तहत,जो श्री अनिरूद्ध सिंह जी व श्री विक्रमादित्य सिंह जी शिमला शहर की पेयजल समस्या को लेकर यहां पर प्रस्ताव लाए हैं , मैं विक्रमादित्य सिंह जी को काम्पलीमैंट्स देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा सीख रहे हैं। कुछ सच्चाई भी बोली और कुछ राजनीति भी आपने मिक्स की है। लेकिन no Government wants any crises to be forced on the Government. कोई सरकार इस बात को नहीं चाहती उसके उपर ऐसा कोई एक नैचुरल समस्या आए। This was a natural calamity. It happened very suddenly. सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नही थी की इतने दिनों में पानी सूखने वाला है। सरकार सोई हुई नहीं थी। There was no such issue that the Government was

sleeping. We are all aware that what period of time we are going through of the global warming. All our sources got dried up. It happened so suddenly that the Government was caught on a wrong footing और वह इतनी जल्दी हुआ और यह संकट आता है तो सरकार को हर कुछ करना पड़ता है। आपने कहा की फलां आदमी फलां जगह रात को आया। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ चम्बा में था। उनकी उस समय शक्ल देखने वाली थी। वहां से वे बैठकर वीडियो कॉन्फ्रैंश के माध्यम से अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। मुख्य सचिव दिन- रात फील्ड में थे। The IPH Minister was in the field for 24 hours. 15 दिन तक यह शिमला छोड़ कर अपने विधान सभा क्षेत्र में नही गए। I agree that it was a major crisis. I also agree that the crisis was blown out of proportion जिस तरीके से इस क्राइसिज की खबरें लगी It may be London Times, it may be Washington Daily and it may be in any newspaper in Delhi. और मैं इस बात को भी मानता हुँ कि पर्यटन को भी इस बात से नुक्सान हुआ है। परंतु यह कहे कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है तो यह बिल्कुल गलत है। The Government was caught on a wrong footing.

श्री एन जी द्वारा जारी

28/8/2018/1500/डी0सी0/एन0जी0-1

श्री राकेश पठानिया जारी.....!

इतनी जल्दी सोर्स ड्र्राई हो जाएंगे और सोर्स इतने नीचे चले जाएंगे कि जहां पर 50 एम.एल.डी. पानी की जरूरत है वहां पर केवल 10-12 एम.एल.डी. की सप्लाई रह जाए तो naturally the crisis was to come. माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी उस समय आपके विधान सभा क्षेत्र, शिमला ग्रामीण की स्कीमों में से पानी के लिए कोई टांका लगाने की कोशिश नहीं की गई । It was part of crisis management और जब क्राईसिस मैनेजमैन्ट आई तो वह कितने दिन की थी, केवल 15 से 18 दिन की, इससे ज्यादा तो

क्राईसिस नहीं थी । We should all bear with the Government. आपने सच बोला की पूर्व की सरकार ने भी शिमला के पानी समस्या को अनदेखा किया है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । That was the good part you spoke because your father was also the Chief Minister but एक बात आपने पोलिटिकल टच देते हुए बोली है कि आपके क्षेत्र में पानी के केवल तीन टैंक आए और लोगों को पानी देने के बजाए केवल पानी का छिड़काव किया गया । आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और दिल्ली में आपने कई आन्दोलन किए और जब दिल्ली में आप पर पानी का छिडकाव किया जाता है तो वह पानी सिवरेज का पानी होता है और उसके बाद आपके कपड़ों में से तीन-तीन दिन तक दुर्गन्ध नहीं गई । हमारी सरकार ने तो आपको शुद्ध पानी मुहैया करवाया है और जो हमारी सरकार ने पानी का छिडकाव किया वो केवल लो एण्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किया । So you must compliment the Government और आपके ऊपर ऐसे पानी की बौछार की गई जिसे आप पी भी सकते थे । मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और आपकी बात में एक बात को जोड़ना भी चाहुंगा । यह बात ठीक है कि अख़बारों में ख़बरें लगी और जिसके कारण टूरिज्म में कमी आई। लेकिन ऐसा ड्रासटिक ड्रोप नहीं आया था । केवल 2-3 दिन के लिए समस्या रही परन्तु उसके बाद 4-5 दिन के अन्दर टूरिज्म का अराईवल नोर्मल हो गया था । मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी की सरकार को और माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी को, जिस तरीके से इन्होंने इस क्राईसिस को

28/8/2018/1500/डी0सी0/एन0जी0-2

टैकल किया यह एक बहुत ही सीरियस और श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार का पहला क्रिटिकल टैस्ट था, जिसे उन्होंने with a big brave heart और गम्भीरता से लिया और उसका सामना किया। इसे चैलेंज के रूप में लिया और इसे सफलतापूर्वक जीता । केवल 15 दिन में पानी की सप्लाई नोर्मल हुई और सारा सिस्टम लाईन पर आ गया । मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपने कहा और माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने कहा, यह एक बडी मेजर समस्या है । इसके लिए वर्ल्ड बैंक से 750 करोड़ का प्रौजैक्ट

अनुमोदित है और बहुत जल्द ही इसके ऊपर काम भी शुरू होने वाला है । मन्त्री जी इसका आश्वासन जरूर देंगे लेकिन मैं इतना जानता हूं की अगले साल ऐसी समस्या नहीं आने वाली और इसके लिए सरकार पुरी तरह से तैयार है। इस साल जिस तरह से रातों-रात टैंकर लगाए गए और सारा का सारा विभाग हरकत में आया, सारी सरकार हरकत में आई, सारे अधिकारी हरकत में आए । must compliment them that Shimla saw one of the major crisis but for very few days इतने कम समय में इस समस्या का समाधान किया गया और समाधान करके सरकार ने अपनी छाप छोड़ी है और यह भी कहा कि we have just taken the Government from the previous Government और जब शिमला में यह क्राईसिस आया था तो सरकार को सत्ता में आए केवल 5 महीने ही हुए थे । शिमला के पानी की समस्या के लिए आप वर्तमान सरकार को दोष दे रहे है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है । मैं आप सब की प्रशंसा करता हूं कि आपने इस विषय पर एक स्पोर्टिव मत माननीय सदन में रखा है । मैं माननीय मन्त्री जी से और सरकार से निवेदन करता हूं कि शिमला हमारी कैपिटल है और आपने खुद कहा है कि शिमला में पानी की स्कीम 1921-22 में अंग्रेजों के समय की बनी हुई है । तब वह स्कीम केवल 5 हजार लोगों के लिए बनाई गई थी और आज इस स्कीम का दोहन ढाई-पौने तीन लाख लोग के लिए हो रहा है। । agree with you. हमारे अधिकारियों को अंग्रेजो से सीखना चाहिए because those schemes are very efficient, जो 80-90 साल पुरानी स्कीमें है । Over all । congratulate the Government for behaving, acting and facing the situation very bravely.

28/8/2018/1500/डी0सी0/एन0जी0-3

शिमला के लोगों ने जो ये क्राईसिस फेस किया उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं । माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने अभी कहा है कि जहां धरने पर बैठते थे वहां पानी आ जाता था और फिर बोल रहे हैं कि 12-12 दिन पानी नहीं आ रहा था । क्या 12 दिन में उन्हें किसी ने सलाह नहीं दी थी धरने पर बैठने की ।। certainly agree that this was the

very serious problem and people of Shimla faced very bad days. मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिमला के लोगों के लिए ऐसे बुरे दिन फिर से न आए सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

28/8/2018/1500/डी0सी0/एन0जी0-4

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा शिमला के पेयजल समस्या पर विचार करने के लिए इस माननीय सदन में जो प्रस्ताव लाया गया है मैं भी उस चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को दो बातों तक सीमित रखना चाहता हूं।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

28/08/2018/1505/RG/DC/1
श्री राकेश सिंघा----जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि यह सिर्फ ऐकाडैमिक चर्चा न रहे। क्योंकि इस सदन में इस विषय पर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं और जहां तक मुझे याद है कि जो प्रोसीडिंग्ज़ विधान सभा की हैं, जिस समय श्री रविन्द्र सिंह जी, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री महोदय थे, उस समय कुछ ऐसे तथ्य इस विधान सभा में आए। मेरे ख्याल से यह वर्ष 2008 की बात है, उन तथ्यों पर चर्चा करने के बाद वर्ष 2016 में वे रिपीट हुए। अगर पीने-के-पानी की समस्या पर चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि दो बिन्दुओं के इर्द-गिर्द चर्चा होनी चाहिए और उन बिन्दुओं का हल निकालने का प्रयत्न होना चाहिए। एक sufficient drinking water और दूसरा है clean drinking water.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो गिरी पेयजल योजना का पानी शिमला शहर को आता है, श्री

विक्रमादित्य जी, मुझे करैक्ट करें क्योंकि उनका इस विषय को लेकर काफी अध्ययन है, तो वहां से लगभग 20 एम.एल.डी. पानी आता है और वर्ष 2008 में हमने इसको कमीशन किया। उसके पश्चात पहले दिन जब पानी चला, तो वह पानी ऑप्टीमम होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 एम.एल.डी. पानी आया और अधिकतर पानी 8 और 12 एम.एल.डी. तक आता रहा। क्या कारण था कि हम उसको 20 एम.एल.डी. नहीं कर सके। मुझे आप माफ करें, मैं किसी ओर इशारा नहीं करना चाहता। जिन ठेकेदारों ने भी इसको निर्मित किया, यह रिपोर्ट है, विजीलैंस की इन्क्वायरी है, इसमें एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें कुछ नहीं होगा। हां, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा होगी, तो शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका कारण क्या था कि पहले दिन पानी को पम्प किया और वह सारा गिरी नदी और जितना भी ठियोग का इलाका लगता है, पानी की सारी बौछारें वहां पर गईं। कारण क्या था कि जो स्पेसिफिक पाईप होना चाहिए था, राइजिंग मेन का होना चाहिए था, वह उसमें बहुत अधिक कम था, उसमें सिर्फ 5.4 और 5.9 एम.एम. की पाईप इस्तेमाल की गई। जबकि 7.9 एम.एम. की पाईप की जस्टीफिकेशन थी और इसमें रख-रखाव का खर्चा कितना हुआ? चालीस करोड़ रुपये से अधिक इसमें वर्ष 2016 से 2018 तक रख-रखाव पर खर्चा हुआ और प्रोजैक्ट को बनाने का खर्च मात्र 45 करोड़ रुपये था। ये आंकड़ें हैं और पूरा-का-पूरा फायदा जो ठेकेदार साहब चाहे जो भी थे, ए, बी या सी थे, मेरा उनके प्रति कुछ नहीं

28/08/2018/1505/RG/DC/2

है। लेकिन सख्ती से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो आज तक नहीं हुई। इसको ठीक करने के लिए कितना पैसा लगा, मात्र चार करोड़ रुपये में यह ठीक कर दिया गया। आज की तारीख में हम वहां से, जो पिछले कल वहां से पानी आया है, मेरे ख्याल 19. कुछ एम.एल.डी. पानी हम उस गिरी नदी से लाने में सक्षम हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रतिदिन का लॉस उन दिनों में आया था, वह 6,00,000/-रुपये प्रतिदिन का लॉस था, जो कि public money down the drain है। विधान सभा में इस पर चर्चाएं हुईं, लेकिन जो कार्रवाई करने की जरूरत थी, मंत्री महोदय, वह कार्रवाई नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम उस कार्रवाई को करें। यह मेरा एक विषय था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय यह है कि मैं इसी गिरी नदी के बारे में क्या कहना चाहता हूं। जितने भी हमारे Sewerage Treatment Plants (STP) हैं, आज एक भी काम नहीं करता। अभी कोटखाई में अस्पताल के नीचे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, उसका सारा सीवरेज गिरी नदी में और फिर लिफ्ट किया जाएगा। हम फिर शहर में कहेंगे कि स्वच्छ पानी दे रहे हैं, फिर पीलिया के मामले होंगे, ये आपको अक्यूज करेंगे, आप इनको अक्यूज करेंगे और इस प्रकार से एक-दूसरे को अक्यूज करते रहेंगे, लेकिन जो जान-माल का खतरा होता है, उस पर ग्रहण लग जाता है। मैं ऐसा समझता हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

28/08/2018/1510/MS/HK/1

श्री राकेश सिंघा जारी----------

इसलिए जो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का सारा गन्दा पानी गिरी नदी में जा रहा है उसको हम आज ही रोक लें। अभी उसका असर नज़र नहीं आएगा लेकिन जब सर्दियां आएंगी, तब उसका असर नज़र आएगा क्योंकि कन्सन्ट्रेशन पानी का कम हो जाता है और सीवरेज का उसी लैवल का रहता है क्योंकि पानी डायल्यूट नहीं हो पाता है और इसीलिए पीलिया का अटैक होता है।

अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं दूसरा विषय भी उठाना चाहता हूं और वह यह है कि अश्वनी खड्ड की जो समस्या है यह भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की वजह से ही है। इसकी रिपोर्ट वर्ष 2007 में आ गई है। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे ने अपनी रिपोर्ट दी है कि यह जो मलाणा का सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट है, जो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम है जहां से अश्वनी खड्ड का पानी चढ़ता है, उसका सारा सीवरेज नीचे अश्वनी खड्ड में जा रहा है और हम पीने-के-पानी के रूप में उसको शिमला की जनता को सप्लाई कर रहे हैं। It is shocking. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एकेडेमिक चर्चा न रहे। यह रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के बाद अन्य रिपोर्ट्स भी आई हैं। पंजाब युनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने एक रिसर्च की है और वह लड़की हिमाचल से संबंध रखती है। अगर उसका नाम सही है तो वह स्मृति है जोकि कोटखाई की रहने वाली है। इसकी यह पी0एच0डी0 की रिसर्च है।

उस रिसर्च में यह पाया गया है कि यह पानी पीने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य अनिरूद्ध सिंह जी ने रखा है, जिसमें विक्रमादित्य जी ने ऐड किया है और राकेश पठानिया जी ने अपने विचार रखे हैं, इसको हम सीरियसली लें। यह प्रश्न सिर्फ शिमला का नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में रहने वाले लोग और जो सैलानी यहां आते हैं अगर हम उनको पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं तो ऐसी आजादी को लानत है जहां 71 साल बाद भी हम इस बात पर सोच-विचार कर रहे हैं कि पीने-का-पानी स्वच्छ और उसकी क्वांटिटी किस तरीके से अदा कर सकते हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि इन दो बिन्दुओं के इर्द-गिर्द भी जो अश्वनी खड्ड के मसले को लेकर एफ0आई0आर0 लॉज है, उसमें भी मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है। इसी तरह

28/08/2018/1510/MS/HK/2

से गिरी खड्ड के मसले को लेकर जो विजीलैंस इन्क्वायरी होनी है उसमें राइजिंग मेन की जो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी उसमें करोड़ों रुपये का मुनाफा ठेकेदार डकार कर चले गए हैं।मैं समझता हूं कि यह कार्य भी इस सदन को करना चाहिए और जो कानून है उसे अपना काम करना चाहिए। हमें किसी को शील्ड करने की कोई जरूरत नहीं है चाहे वह व्यक्ति किसी भी विचारधारा का हो। लेकिन पीने-के-पानी को लेकर, मैं समझता हूं कि यह क्रीमिनल ऐक्ट है और किसी को इस बात के लिए बख्शा नहीं जा सकता है। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न कहता हुआ आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका इस सदन में दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे मंत्री महोदय हैं वे कुछ प्रश्नों को लेकर बहुत डाइनामिक हैं और वे इस प्रश्न को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे तथा इन चीजों को सख्ती से डील करते हुए पानी-का-पानी और दूध-का-दूध करके देंगे ताकि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली जनता जो शहर से नाता रखती है उसको स्वच्छ पीने-का-पानी मिले। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका पुनः बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

28/08/2018/1510/MS/HK/3

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री राकेश कुमार जी भाग लेंगे।

श्री राकेश कुमारःअध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अनिरूद्ध सिंह जी ने शिमला शहर की पेयजल की समस्या को लेकर इस सदन में जो प्रस्ताव लाया है, उस पर यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने राजधानी शिमला की पेयजल समस्या के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की है। राजधानी में देश के कोने-कोने से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

28.08.2018/1515/**जेके**/**एचके**/1

श्री राकेश कुमारः------**जारी**-------

इस बार गर्मियों में जो पीने के पानी की समस्या यहां राजधानी में हुई, उसके बारे में हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की और कहा कि बहुत गम्भीर समस्या है और इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी होना चाहिए। साथ में यह भी कहा कि इसमें हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, यह भी कहते गए और साथ में यह भी कहते गए कि सरकार की ये-ये नाकामयाबियां रही हैं। सरकार ने यह गलत किया, अधिकारियों ने यह गलत किया जिसके कारण पीने के पानी की समस्या इस राजधानी में आई। लेकिन मुझे लगता है जिस दिन यह पीने के पानी की समस्या आई उस समय प्रदेश की सरकार को बने हुए अभी पांच महीने ही हुए थे। यह समस्या मात्र पांच महीने में उत्पन्न नहीं हुई। पूर्व की पांच वर्ष की सरकार में यह चिन्ता नहीं की गई। शिमला में आए दिन जिस प्रकार से कन्स्ट्रक्शन हो रही है, अनिरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार से होम स्टे के बारे में कहा, किस कारण पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, विभिन्न बातों को ले कर यहां पर चर्चा की गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय पीने के पानी की समस्या को लेकर किस प्रकार के प्रयास किए गए, इस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए था। लगातार तीन वर्षों से कम

बारिश हुई, बर्फबारी कम हुई और हम सभी जानते हैं कि उस कारण से भी यह पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हुई। पूर्व सरकार में उस समय की माननीय मंत्री जी चाहती थीं कि चांशल से पीने के पानी को शिमला लाया जाए लेकिन उस समय के मुख्य मंत्री जी चाहते थे कि शिमला के लिए कोल डैम से पानी लाया जाए। इसी बात को लेकर मामला उलझता रहा और वह योजना पूरी नहीं हो सकी। उस योजना को वर्ल्ड बैंक से मंजूर नहीं करवाया गया। उसके कारण वर्तमान में यह समस्या शिमला में आई और उसके लिए जो दोषी है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में किस प्रकार से प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने, आई0पी0एच0 मंत्री जी ने, प्रदेश के सभी आई0पी0एच0 के अधिकारियों/कर्मचारियों और यहां तक कि प्रदेश के सबसे बड़े आला अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ने खुद इन सारी बातों को लेकर मॉनिटरिंग की।

28.08.2018/1515/जेके/एचके/2

यहां पर चर्चा की गई कि शिमला की मेयर विदेश में थी लेकिन साथ में यह भी चर्चा होनी चाहिए थी कि शिमला के हमारे लोकल विधायक व शिक्षा मंत्री, आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी की धर्मपत्नी पी0जी0आई0 में एडमिट थी। उसके बावजूद ये यहां शिमला में पीने के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए रात-दिन प्रयास करते रहे। मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने जो प्रयास किए और एक हफ्ते के लिए जो यह समस्या शिमला में आई, उससे निपटने के लिए हर रोज मुख्य मंत्री जी शिमला में सुबह, दोपहर और शाम को बैठक कर अधिकारियों से सारी रिपोर्ट लेते थे। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि विभाग का मंत्री घर-घर जा कर और वॉर्ड में जा कर लोगों को पूछ-पूछ कर कि कहां-कहां, क्या-क्या समस्या आ रही थी, इन्होंने उस समस्या का पता किया और उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया। मेरा भी मानना है कि यह गम्भीर समस्या है। शिमला हमारी राजधानी है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा मान्यवर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने इस समस्या के तुरन्त बाद शिमला के लिए लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम चाबा-सतलुज-गुम्मा के लिए 80 करोड़ रूपया मंजूर किया। उसके टेंडर भी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि दो-चार दिन में वे टेंडर खुलने वाले हैं। इसके साथ-साथ जो बड़े दिनों से जिक्र कर रहे थे कि कोल डैम से पानी उठाया जाए, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय आई0पी0एच0 मंत्री जी को कि आपने इस पर भी तुरन्त काम किया

और लगभग 930 करोड़ रूपए की लागत से कोल डैम से पानी शिमला के लिए लाया जाएगा और आने वाले समय में शिमला में पीने के पानी की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी सरकार ने इस विकट परिस्थिति में काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिल कर, जब भी ऐसी कोई विकट परिस्थिति प्रदेश में उत्पन्न होती है तो राजनीति करने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मिल कर उस समस्या का समाधान करने में लगें तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश आगे जाएगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

28.08.2018/1520/SS-YK/1

श्री राकेश कुमार क्रमागतः

जिस प्रकार से कहा गया कि समाचार पत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई। लेकिन किन कारणों से हुई, उसके पीछे भी हमको जाना चाहिए। यह समस्या मात्र पांच महीने में उत्पन्न नहीं हुई है। पिछले पांच वर्षों में उस समय भी सरकार थी। उस समय भी मुख्य मंत्री और मंत्री थे तो उस समय इस समस्या का समाधान करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। लेकिन मैं आज हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस छोटे से कार्यकाल में जो शिमला राजधानी में समस्या उत्पन्न हुई है उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा है। एक बड़ी योजना के तहत कौल डैम से शिमला के लिए पानी आयेगा। 930 करोड़ रुपये की लागत से हमारी राजधानी के लिए योजना बनेगी। आने वाले समय में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं कि इस समस्या के बाद विभाग ने किस प्रकार से काम किया। हम सब लोग जानते हैं कि 13 अगस्त को जो बारिश हुई उस बारिश के कारण पीने के पानी की बड़ी-बड़ी योजनाएं खराब हो गईं। उन्हें दुरूस्त करने में एक हफ्ता लगा और कहीं दस दिन लगे। लेकिन शिमला में इतनी भारी बारिश के बावजूद कहा गया कि 100 वर्षों पहले इतनी भारी बारिश हुई थी। उस बारिश के बावजूद भी एक दिन के अंदर शिमला शहर की पीने के पानी की सप्लाई 24 घंटे के अंदर-अंदर बहाल की गई। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और विभाग के अधिकारियों को

बधाई देता हूं। मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग सार्थक चर्चा करें। समस्याएं अनेकों हैं उन समस्याओं को लेकर विपक्ष के सहयोगी भी अपनी भूमिका निभाएं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सब लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा निवेदन रहेगा कि जहां हम नेगेटिव बातों को लेकर चर्चा करते हैं, वहां सरकार का जो अच्छा पक्ष है उसको भी रखने का प्रयास करें। इतना निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.08.2018/1520/SS-YK/2

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी जी, चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा प्रस्तुत जो नियम-130 का प्रस्ताव है, इसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य, दोनों युवा साथी और एक पुराने साथी, श्री राकेश पठानिया जी की बातों को मैं गौर से सुन रही थी। वैसे इस चर्चा में भाग लेने का मेरा इरादा नहीं था परन्तु क्योंकि आपने (श्री राकेश पठानिया) भाग लिया इसलिए मैंने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भाग लेने का आपका भी इरादा नहीं था और मेरा भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह चिन्ता का विषय रहा और माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी बड़ा अच्छा बोलते हैं। डायनामिक हैं। अपनी ही बातों को खुद कंट्राडिक्ट करते हैं। इन्होंने पहले कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए परन्तु आपने खाली राजनीतिक भाषण दिया। श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री विक्रमादित्य सिंह व श्री राकेश सिंघा जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए और कोई राजनीति नहीं की। यह राजनीति का विषय भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिमला में पली-बढ़ी हुई हूं। मेरा शिमला शहर में ननिहाल है। शिमला में वॉटर की शॉर्टेज रहती है, यह कोई नई बात नहीं है। मगर इस बार जिस तरह से शॉर्टेज की हैंडलिंग हुई उसकी चर्चा करना जरूरी था। सरकारें रही हैं। आपकी भी रही हैं और हमारी भी रही हैं। आप तो एक मुख्य मंत्री को पानी वाला मुख्य मंत्री कहकर बुलाया करते थे, आजकल आप लोग उनकी चर्चा नहीं करते हो। जिन मूल्यों के लिए वे खड़े होते थे,

उसके खिलाफ आप सुबह अपनी पावर पॉलिसी बता रहे थे। आपकी सोच में बदलाव आ गया है। आप उनको पानी वाले मुख्य मंत्री कहा करते थे। राकेश जी ऐसी बात नहीं है यहां सरकारें हमारी भी रही हैं और आपकी भी रही हैं। भारद्वाज साहब पहली बार विधायक नहीं बने हैं। ये विधायक भी रहे हैं, बी0जे0पी0 के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और शिमला के पानी के लिए सभी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि यह बेहतर हो। जिस कौल डैम स्कीम की आप चर्चा कर रहे हैं, आपने अपने भाषण की शुरूआत में कहा कि कौल डैम से राजा वीरभद्र सिंह जी स्कीम बनाना चाहते थे और हमारी मंत्री महोदया को कुछ लोग एडवाइज़ कर रहे थे कि पानी चांशल से लाया जाए। प्रश्न यह नहीं था कि पानी चांशल से लाया

28.08.2018/1520/SS-YK/3

जाए या कौल डैम से लाया जाए, प्रश्न यह था कि शिमला को पानी मिलना चाहिए। टेक्निकली कौल डैम वाली स्कीम बेहतर पाई गई। इस स्कीम का श्रेय आपको नहीं जाता है। इसका श्रेय राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है और कांग्रेस की सरकारों को श्रेय जाता है। आप उसको आगे ले गए हैं, ये तो हमको आपसे उम्मीद है ही।

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2018/1525/केएस/वाईके/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी---

महेन्द्र सिंह जी, बहुत कम्पीटैंट मिनिस्टर हैं। ये हमारे पुराने साथी हैं। आज आपके साथी हैं, कल क्या पता? हमारे दरवाजे तो इनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे साथी भी रहे हैं। इसी तरह से उस तरफ हमारे और भी साथी हैं लेकिन अगर मैं नाम लूंगी तो बात दूर तलक जाएगी। एक तो आप ही के साथ बैठे हैं, ये तो हमारे केबिनैट मंत्री थे।

अध्यक्ष जी, चिंता का विषय यह है कि जो नेशनल और इंटर नेशनल लैवल पर शिमला की बदनामी हुई है, आप भी मानेंगें कि यह चिंता का विषय है। What was the need to issue

an advisory and what was the need to tell people that don't come to Shimla? I don't think there was any need to do this. यह पहली बार हुआ कि शिमला का समर फैस्टिवल कैंसल हुआ। इससे बदनामी हुई। इन्टर नेशनल न्यूज़ पेपर जिसका यहां पर ज़िक्र किया गया और उसको वांशिगटन डेली बोल रहे थे लेकिन वह वाशिंगटन पोस्ट है । इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्ज़ और लंदन टाइम्ज़ में यह खबर छपी है कि ब्रिटिश टाइम की राजधानी जो कि समर कैपिटल थी, वहां इस तरह के क्राइसिज़ हुए। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की हमारी जो कैपिटल है, we call it the "Queen of Hills" इसकी बदनामी होगी तो हम सब की बदनामी है। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं कहती हूं it is matter of concern कि अश्वनी खड्ड में, जिस तरह से आदरणीय सिंघा जी ने कहा, चाहे अश्वनी खड्ड हो या कोई और हो, वहां पर सिस्टम फेल क्यों हुए? वहां पर राइज़िंग मेन में अगर किसी ठेकेदार ने सही काम नहीं किया और उसके खिलाफ एफ.आई.आर. है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह सब का कन्सर्न है। ठेकेदार कोई भी हो सकता है। I don't even know who he is. ठेकेदार कोई भी हो सकता है मगर लापरवाही बरती गई है तो वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, किसी भी व्यक्ति से सम्बन्ध रखता हो, action should be taken on him. कल को कोल डैम से स्कीम बननी है जो कि बहुत बड़ी स्कीम है। अगर ठेकेदारों को यह महसूस हो कि हमारे ऊपर कोई ऐक्शन ही नहीं होगा how they will be bothered? वह लिफ्ट की स्कीम है

28.08.2018/1525/केएस/वाईके/2

और आपको पता है कि लिफ्ट की स्कीम को हमेशा मेंटेंन करना बहुत मुश्किल होता है। पम्प की प्रॉब्लम आती है, पम्प ऑप्रेटर्ज़ की प्रॉब्लम आती है, इलैक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, आपके बिल टाइम पर पे नहीं होते। हमारे सदस्यों की इस बात की चिंता है कि जो हुआ है, सक्सैसिव गवर्नमैंट्स ने कोशिश की है और यह कोशिश का ही नतीजा है कि कोल डैम परियोजना आज टेबल पर आई है। उसको वर्ल्ड बैंक से मंजूरी मिली है। उसके लिए धनराशि स्वीकृत हुई है और वह बनने जा रही है। वह भविष्य की बात है लेकिन अभी आप

कह रहे हैं कि हफ्ते में वह समस्या खत्म हो गई। आप आज का न्यूज़ पेपर देखिए, आपकी मेयर आज भी पानी की समस्या के बारे में मीटिंग कर रही है । हर जगह पर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शिमला के कुछ एरियाज़ में रीस्टोर हुआ है और कुछ एरियाज़ अभी भी अफैक्टिड हैं। आज के न्यूज़ पेपर में आपकी मेयर की पानी की समस्या का समाधान ढूंढते हुए बहुत बढ़िया फोटो छपी है। समाधान ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन वह चाइना नहीं जाती तो अच्छा होता। भारद्वाज साहब का तो हम धन्यवाद करते हैं। ये हमेशा शिमला के बारे में चिंता करते हैं। मुझे मालूम है कि इनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी ये अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है । हमारा विरोध तो इस बात पर है कि किन ऑफिसर्ज़ ने यह एडवाइज़ दी कि एडवाइज़री इशू की जाए कि शिमला में लोग न आए। शिमला में पानी की समस्या थी, उसका समाधान करने की बजाय शिमला को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? अश्वनी खड्ड का एक विडियो वायरल हुआ और मुझे विश्वास है कि वह आप सभी ने भी देखा होगा। अश्वनी खड्ड में दुनिया भर का कूड़ा-कचरा जा रहा है। एन.जी.टी. ने उसका सुओमोटो संज्ञान लिया है। यह नौबत वहां कैसे आई? यह कूड़ा-कचरा कहां से जा रहा है? यह प्रबन्धन कौन नहीं कर रहा है? क्या कारण हैं? पांच महीने सरकार को आए हुए हो और उसकी वजह से यह हो जाए, ऐसा नहीं है लेकिन यह भी ठीक है कि इसका जो सही से नेशनल और इन्टर नेशनल लैवल पर दृष्टिकोण जाना चाहिए था, वह नहीं गया। शिमला को सरकार द्वारा बदनाम किया गया। मैं यह नहीं कहती कि मुख्य मंत्री चिंतित नहीं थे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.8.2018/1530/av/ag/1

श्रीमती आशा कुमारी -------- क्रमागत

राकेश पठानिया जी ने ठीक कहा, मुख्य मंत्री जी चम्बा में थे जब शिमला में यह सब हो रहा था और इनको इसलिए भी याद होगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी तथा राकेश पठानिया जी

वहां पानी में नौका विहार कर रहे थे। यह कोई मुद्दा नहीं है कि मुख्य मंत्री जी चिन्तित नहीं थे और यह भी कोई मुद्दा नहीं है कि महेन्द्र सिंह जी गये, इन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया। मगर मुद्दा यह है कि क्या कारण था कि चीफ जस्टिस गलियों में घूम रहे थे। Why? मुकेश अग्निहोत्री जी ने पहले भी यह बात रेज़ की है कि why is the High Court directing the Government? क्या कारण है कि जिलाधीश (शिमला) कनैक्शन्ज काट रहे थे। क्या यह काम जिलाधीश का होता है। (---व्यवधान---) कनैक्शन किस-किस का काटा, मैं इस पर बोलना नहीं चाहती। वे भी वर्तमान में इस माननीय सदन के सदस्य हैं। हमारे मित्र हैं और हमारी पार्टी से ही समर्थन लेकर गये हैं और अब आपके साथ हैं। कहीं अगर वे अभी भी हमारे साथ होते तो आप लोगों ने यहां पर बवंडर खड़ा कर देना था। (---घंटी---) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। I am just winding up. क्या कारण है कि जिलाधीश को कनैक्शन काटने के लिए जाना पड़ा। अनिरुद्ध जी ने ठीक कहा, यह चाहे शिमला हो या कोई दूसरा शहर; जहां-जहां पर over the capacity जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट्स, होटल्स, बैड एण्ड ब्रेक फास्ट, गैस्ट हाउसिज चल रहे हैं उसके अलावा अनरजिस्टर्ड कितने चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं? क्या कारण है कि जब क्राइसिस आयेगी तो जिलाधीश जाकर पानी काटेगा। हम इन चीजों को खुद क्यों नहीं देख रहे हैं? Why we are not taking action? कोई मेरा दोस्त होगा और कोई आपका दोस्त होगा। Why are we interfering in this? तथा उसका नतीजा यह हो रहा है कि शिमला शहर अब इस बोझ को और सहन नहीं कर पायेगा। आपको कोल डैम की स्कीम बनाने में भी समय लगेगा, आपको गुम्मा से पानी लिफ्ट करने में भी समय लगेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगले वर्ष के लिए कुछ तैयारियां पहले से कर लीजिएगा। उसके लिए जो टैंकर्स इत्यादि पहले से बुक होने हैं उसको टाइम से कीजिएगा। ये स्कीमें बनेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

28.8.2018/1530/av/ag/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से जो पानी के कनैक्शन की बात आई है, मैं उस बारे में इस मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं।

किसी अधिकारी ने जो कनैक्शन काटा है वह मेरे नाम से नहीं था। मैंने उसके तीसरे दिन प्रैस कान्फ्रैंस की थी और कहा था कि यदि यह कनैक्शन मेरे नाम से होगा या यह कनैक्शन गैर कानूनी होगा तो मैं अभी विधायक पद से रिजाईन कर दूंगा और जीवन में कभी चुनाव नहीं लडूंगा। मुझे हैरानी इस बात की है कि एक अखबार वाले ने तो यहां तक लिखा कि चौपाल का विधायक पानी की चोरी करते पकड़ा गया। मेरे नाम से कोई कनैक्शन नहीं है और न ही मैंने उसके लिए अप्लाई किया है। जो कनैक्शन लगा था वह लीगल कनैक्शन था और जिसने अप्लाई किया था उसके नाम से लगा हुआ था। वह कनैक्शन जिस ऑफिसर ने काटा था उसके तीसरे दिन उसी ऑफिसर ने वह कनैक्शन जोड़ दिया। मैं यह नहीं कहता कि किसी पक्ष या विपक्ष ने यह मुद्दा उछाला लेकिन कुछ चंद लोग गलत तरीके से ऐसी बात को आगे ले जाते हैं। मैं इस मान्य सदन को अभी भी अवगत करवाना चाहता हूं कि वह लीगल कनैक्शन था, उसको कमीश्नर ने सैंक्शन किया था इसलिए वह कनैक्शन लगा था। तीसरे दिन उसी कनैक्शन से उनको पानी दिया गया। मैं मान्य सदन को इसलिए अवगत करवाना चाहता हूं कि यह कनैक्शन मेरे नाम से नहीं था, न मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और न ही मेरा इससे कोई लेना-देना था। धन्यवाद,सर।

28.8.2018/1530/av/ag/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में पेयजल समस्या पर विचार हेतु श्री अनिरुद्ध सिंह जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर मुझे आपने चर्चा के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।जहां तक शिमला शहर की पेयजल समस्या का मामला है तो पिछले 20 वर्षों से मैं भी शिमला शहर में रह रहा हूं।

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2018/1535/TCV/HK-1

श्री जीत राम कटवाल .... जारी

यहां पर पानी की समस्या हर वर्ष किसी-न-किसी रूप में देखने को मिलती है। यह बात भी सही है कि हवा और पानी हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है और किसी भी व्यक्ति को इन दोनों चीजों के बिना गुजारा करना न केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत होता है। शिमला शहर के बारे में जो कंसर्न माननीय सदस्य ने जताया, शिमला एक कॉस्मोपोलिटन शहर है। प्रदेश के 12 जिलों, विदेशों और भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों से व्यक्ति यहां पहुंचते हैं। उनके अनुभव अच्छे हों, उनका यहां का प्रवास अच्छा हो, जिस कार्य/सरकारी कार्य या किसी अन्य कार्य से वे यहां आये हैं, यह हिमाचल प्रदेश के लोगों का कर्त्तव्य ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी अवधारणा भी होनी चाहिए कि वे यहां से खुश होकर जायें। पिछले दिनों यहां पानी की जो प्रोब्लम थी, वह सच में ही चिन्ताजनक थी। सरकार को आये मात्र दो महीने हुए थे, जब 15 फरवरी और 15 मार्च के आसपास पानी की समस्या या सूखे की परिस्थितियां सामने आने लगी। इसका कारण चाहे कोई भी हो, हमें इससे एकजुट होकर निपटना और सहनशीलता से अपना वक्तव्य रखना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको कॉस्मोपोलिटन शहर मानते हैं, प्रदेश के हर नागरिक का इस शहर में इंट्रस्ट है तो यह सभी का कर्त्तव्य भी है। गुण-अवगुण गिनाने आसान है। परन्तु परिस्थितियों को सभी के सहयोग से निपटाने का प्रयास हो तो बहुत अच्छे तरीके से हम

किसी भी परिस्थिति में उसको आगे ले जाने या निपटाने में सशक्त और समर्थ होते हैं। माननीय अनुरूद्ध जी ने बताया कि यहां पानी की कमी होती है और टी.वी. चैनलों में बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं आई। अखबारों में बहुत कुछ हुआ। इसलिए इसके लिए लांगटर्म-शॉर्टटर्म प्रयास होने चाहिए। इनकी सोच बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। मेरा भी यह मानना है कि जो हुआ, बात गई। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय की सारे व्यक्ति दाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एफिशिएंट हैं, कुछ-न-कुछ कर दिखाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के संदर्भ में जो टिप्पणी आती है, उनकी

28.08.2018/1535/TCV/HK-2

स्पष्टवादिता और अच्छे काम के बारे में पक्ष- विपक्ष के सभी सदस्य उनकी सराहना करते हैं। इसलिए हमें राजनैतिक कारणों से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। ये भी बात सही है कि शिमला शहर की जो वॉटर सप्लाई स्कीम है, वह अंग्रेजो ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 20000 व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई थी और इसकी कपैसिटी भारतीय मानकों के अनुसार 60000 व्यक्तियों तक सक्षम आंकी गई थी। आज अढ़ाई-तीन लाख व्यक्ति प्रतिदिन यहां आते हैं और यहां शिमला में निवास/प्रवास करते हैं। पानी की आवश्यकता और अनुभव यहां से लेकर जाते हैं। शिमला अंतरराष्ट्रीय स्तर का हिल स्टेशन है। शिमला को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसको हमें हलके में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करने चाहिए। यहां पर चर्चा में आया कि शिमला शहर के लिए 930 करोड़ रुपये की पानी की स्कीम बनाई गई है। वर्ष 2014 में 673 करोड़ की बनाई गई थी और अब रिवाइज करके 930 करोड़ की हो गई है।

श्रीमती एन0ए0 .... द्वारा जारी ।

28-08-2018/1540/NS/DC/1

श्री जीत राम कटवाल -----जारी

जहां तक मेरे पास सूचना है, उसके अनुसार जनवरी, 2019 तक 250-300 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त आने वाली है। पानी की सप्लाई के लिए पानी का प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छे प्रयास किये हैं। मैं इसलिए अवगत हूं क्योंकि ये मेरे एक एस.ई. को बिलासपुर से उठा करके शिमला ले आये थे और यह आम सहमति से निर्णय था। मैं इनके पीछे पड़ा कि इनको न ले जायें। लेकिन इन्होंने कहा कि इनकी वहां पर आवश्यकता है और ये अच्छा काम करते हैं। यह तो अच्छी बात है कि वे किसी न किसी हिस्से में सेवा देंगे। परन्तु हमारी जो व्यावहारिक परिस्थितियां हैं कि किसी ने टुल्लू पम्प लगा करके पानी की चोरी की है। इसके ऊपर आई0पी0सी0 की धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। परन्तु ऐसा करने से समस्या हल नहीं होती है। इसके लिए हमें एजुकेट होने की आवश्यकता है। पानी का जो प्रबंधन है, मान लो पाइपें पुरानी हैं, कोई छोटी और मोटी पाइपें हैं तथा किस डाया की पाइपें लगनी हैं, ये भी कमियां रहती हैं। मेरा यह मानना है कि आने वाली नई स्कीम में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सापेक्ष अनुभव व नीयती के साथ अगर हम काम करेंगे तो माननीय मंत्री महोदय को इस स्कीम का क्रेडिट भी मिलेगा। आने वाले 4-5 वर्षों में एक अच्छी वाटर सप्लाई स्कीम से शिमला को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को एडवांस में शुभकामनायें देता हूं। मैं मानता हूं कि पिछले अनुभव से और आलोचना से या जो भी अच्छे सुझाव यहां पर आते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये अच्छा काम करेंगे। अगर हम रेग्युलर वॉटर सप्लाई देते हैं तो हम अपने नागरिकों के आभार के पात्र तो हैं ही इससे हमारे भीतर एक सन्तुष्टि की भावना भी होगी।

यहां पर लोंग रन स्कीम की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की 930 करोड़ रुपये की स्कीम जो रिवाईज़ड रेट में है, आज इसकी चर्चा यहां पर हो रही है। वर्ष 2014 में इसकी प्रस्तावना हुई थी और वर्ष 2017 में इसके नये एस्टिमेट भेजे गये थे। वर्तमान सरकार ने इसकी पहली किस्त को लाने का जो प्रयास किया, इसके लिए मैं सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अच्छा काम करें।

28-08-2018/1540/NS/DC/2

अध्यक्ष महोदय, अप्रैल-मई के महीने में पानी की गंभीरतम समस्या प्रदेश भर में थी। इसके कई कारण हैं। माननीय विक्रमादित्य जी ने कहा कि सब्जियां उगाना या पानी का एक्सैस यूज़ करना या दोहन ज्यादा करना आदि से भी यह समस्या पैदा होती है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि गांव में भी इस प्रकार की समस्यायें आती हैं। गांव में लोगों ने मनरेगा के तहत 10,000 लीटर केपेस्टिी के टैंक बना रखे हैं और पानी की सीधी सप्लाई इस टैंक में दे रखी है। भंडारण की जो ऐसी प्रवृत्ति हम लोगों में है कि चार दिन पानी नहीं आएगा तो हमारा बंदोवस्त होना चाहिए और पड़ोसी का चाहे जो मर्ज़ी हो। इस भावना के लिए हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा भी मानना है। इस सदन में चार खड्डों की भी बात हुई है। चांश्ल का अनुभव भी यहां रखा गया है। रिसपैक्टिव गवर्नमैंट्स ने इसके बारे में कोशिश की है। (घंटी) अब वर्तमान सरकार इस पर अच्छा काम करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध रहेगा कि इस ईश्यू पर हम एकजुट हो करके सार्थक सुझाव के साथ आगे आयें और आने वाला समय में शिमला की वॉटर सप्लाई स्कीम टूरिज्म से जुड़े। क्योंकि यह हमारा एक ऐतिहासिक डेस्टिनेशन है, इसको ज्यादा सुन्दर, साफ और समर्थ बनाने के लिए काम करें। मेरा ऐसा मानना है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृप्या वाईंड-अप करें।

श्री जीत राम कटवालः सर, मैं वाईंड-अप कर रहा हूं। ज्यादा न कहते हुए जो कोल डैम की स्कीम है और एडवाइज़री पर जो चर्चा हुई है, मैं इसे अनुभव मान कर ही आगे बढ़ना चाहूंगा। लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.08.2018/1545/RKS/DC-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी।।।

मेरा सुझाव है कि आने वाली स्कीम में हम प्रत्येक हिमाचली के इंटरस्ट से काम करें। इस स्कीम में हजार करोड़ रुपये के लगभग खर्चा होने की संभावना है और हमें इसे भले तरीके

से लागू करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो इसके हल के लिए काम किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। भविष्य में इस स्कीम को लागू करने के लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द।

28.08.2018/1545/RKS/DC-2

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी इसमें अपनी बात कहेंगे।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। शिमला पेयजल आपूर्ति के बारे में माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह और श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने नियम-130 के अंतर्गत चर्चा लाई है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और स्वयं को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं। इस सदन में इस क्षेत्र को रिप्रेजैंट करने वाले मुख्य रूप से तीन ही लोग हैं। यह अलग बात है कि मेरे दोनों ओर राजा व राणा है और मैं बीच में हूं।

श्रीमती आशा कुमारीः भारद्धाज जी, बिना पंडित के काम नहीं चलता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी यह सब आप से सीख लें कि उनके बिना काम नहीं चलेगा।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर पहले गांव था। अंग्रेजों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और अपनी आवश्यकताओं के लिए बिजली व पानी की आपूर्ति भी की। उस समय भी शिमला के इर्द-गिर्द पानी नहीं था इसलिए पानी की सप्लाई गुम्मा से लानी पड़ी। लीकेज की वजह से सबसे पहले सन् 1977 में क्रैगनैनो-शिमला तक की पाइप लाइन को ठीक किया गया। शिमला से बाहर का एरिया, जब यह पंजाब का एरिया था और जहां से कुसुम्पटी शुरू होता है, वहां एक 'शेर' वाला नलका होता था। उस नलके से पानी लेने के लिए कुसुम्पटी के लोगों को नगर-निगम से 10 पैसे की पर्ची मिलती थी। बैंगी में पानी उठाकर घर-घर ले जाने वाले लोग होते थे। जैसे-जैसे पानी की आवश्यकता होती थी या लोगों के पास पैसा होता था उस हिसाब से वे 2, 3 या 4 कंटर पानी के लेते थे। लेकिन पंजाब के एरिया में कोई नलका नहीं था। बाद में बाजार में एक नलका लगा, दूसरा लगा।

अब यह नगर-निगम का एरिया बन गया है और सारे कुसुम्पटी में पानी के नलके लगे हुए हैं। शिमला में जितना भी पानी है वह सारा सरफेस वाटर है। यहां पर जमीन से निकलने वाला पानी नहीं है। चाहे वह गुम्मा, गिरि, चुरट, चैड़ या अश्वनी खड्ड की स्कीम्ज हों, ये सारी स्कीम्ज सरफेस वाटर से आती है। इन सभी स्कीम्ज का पानी इक्ट्ठा करके 54 एम.एल.डी. बनता है। लेकिन लीकेज वगैरह होने के कारण शिमला को कभी भी 45 एम.एल.डी. से ज्यादा पानी नहीं मिला। इसलिए मांग और आपूर्ति के कारण शहर में पानी का संकट रहता है। आज यहां 51 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता है लेकिन जब पीक सीजन में भी 42-45 एम.एल.डी. पानी मिलेगा तो कहीं-न-कहीं प्रॉब्लम रहेगी। इस बात

28.08.2018/1545/RKS/DC-3

का जिक्र माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी भी कर रही थी कि आजकल भी पानी की समस्या चल रही है। 80 के दशक में भी शिमला में इस प्रकार की प्रॉब्लम हुई थी, जैसे इस बार हुई है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

28.08.2018/1550/बी.एस/डी.सी./-1

शिक्षा मंत्री .....जारी

वर्ष 1989-90 में भी इस तरह की दिक्कत आई थी और ऐसे ही पहली बार 10-15 दिन तक पानी की समस्या हुई है। असल में शिमला में जो वर्षा का एवरेज रहता है वह 1400 मिली लीटर का रहता है। यह रिकार्ड है कि वर्ष 1917-18 में बरसात में शिमला में कोई बारिश नहीं हुई और सर्दियों में बर्फ नहीं गिरी । शिमला के पूरे-के-पूरे कैचमैंट एरिया के इर्द-गिर्द बिल्कुल बर्फ नहीं गिरी जिसका नतीजा यह हुआ कि स्त्रोतों में पानी कम हो गया। जब स्त्रोत में पानी कम हो जाएगा तो उसका असर सीधा सप्लाई पर पड़ेगा। डैम यहां पर नहीं है । यहां तक सीधा पानी पंप से उठाकर पहुंचाया जाता है और शिमला की वाटर स्पलाई को दे दिया जाता है। इस कारण जब गर्मी का मौसम आया तो उस समय स्त्रोतों में पानी कम हो

गया । यह सही है कि उसके लिए तैयारियों पहले हो जानी चाहिए थीं। मैं इस बारे में नगर निगम को आगाह भी कर दिया था। क्योंकि गुम्मा का जो केचमैंट एरिया है वहां पर अंग्रेजों के समय का एक एग्रीमैंट हुआ है कि जब शिमला के अन्दर पानी की कमी होगी तो वे अपना सिंचाई का काम बंद कर देंगे। उसके बदले में उनको सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी परंतु कई वर्षों से इस तरह की कोई आवश्यकता पानी की नहीं पड़ी या किसी को पता ही नहीं है कि इस तरह का एग्रीमैंट हुआ है इसलिए उस पर काम नहीं किया गया। जब पानी सूख गया और स्रोत में पानी नहीं रहा तो शिमला शहर को पानी नही मिला। विकास एक सतत प्रक्रिया है, शिलान्यास हम करते हैं और उद्घाटन आप करते हैं यदि आप शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन हम करते हैं । ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार द्वारा बनाई जा रही स्कीम दो-तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी। आदरणीय शांता कुमार जी ने 1990 में मुख्य मंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम रिज से चल कर अश्वनी खड्ड से जो पानी की स्कीम शिमला के लिए बन रही थी उसके लिए किया था। वह पानी की स्कीम उस समय तैयार होने वाली स्टेज पर थी । उसको उसी वक्त पैसा देकर लगभग 8 महीने में उस स्कीम को पूरा किया था। उस स्कीम से शिमला को 10 एम.एल.डी. पानी मिलना शुरू हुआ। इस स्कीम से लगभग-लगभग शिमला में पानी की आवश्यकता को पूरा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद शिमला शहर में पानी की खपत अधिक होनी

28.08.2018/1550/बी.एस/डी.सी./-2

शुरू हो गई । शिमला के चारों ओर मकान बन गए । नगर निगम द्वारा शहर के साथ लगते एरियाज कभी ले लिए जाते थे और कभी हटा दिए जाते थे। अब वह सारा एरिया शिमला नगर निगम का हिस्सा बन गया है। उसके लिए कोई स्कीम चित्रित नहीं की गई थी कि ये-ये एरियाज आएंगे और वहां रहने वाली जनता भी शिमला शहर में शामिल होगी और उन्हें पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे । फिर उसके बाद गिरी नदी से पानी की स्कीम बनी । गिरी

नदी से 20 एम.एल.डी. पानी आना था लेकिन यहां आदरणीय सिंघा जी ने ठीक कहा कि वह 20 एम.एल.डी. के लिए बनी थी, उसमें 14 एम.एल.डी. से ज्यादा पानी नहीं आया। शुरू में हमें भी आई.पी.एच. के द्वारा यही कहा गया कि इसमें इतना ही पानी प्रदान किया जाएगा, जब पीक होगा या पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी तो इस बारे में बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें कभी 19 एम.एल.डी. पानी आ जाता था कभी 20 एम.एल.डी. तक आ जाता था। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें 12-14 एम.एल.डी. से ज्यादा इसमें पानी नहीं आया। शायद उस समय उतनी आवश्यकता भी नहीं रही होगी और न ही इस तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। इसके साथ-साथ यहां पर लोगों को पीलिया हुआ। अश्वनी खड्ड में पानी खराब हो गया, मैला हो गया और साथ में उसमें पीलिया का वायरस आ गए। उसका कारण यह था कि अश्वनी खड्ड में पानी का ट्रीटमेंट प्लांट से केवल 4 किलोमीटर दूरी पर सिवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट लगा दिया गया था।

श्री डी.टी. द्वारा जारी ....

28.08.2018/1555/डी.टी./एच.के./-1

शिक्षा मंत्री .....जारी

कभी भी चलते पानी के करीब 25 किलोमीटर से नजदीक सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए। वरना वहां जितना भी सिवरेज होगा वह पानी में मिल जाएगा और पानी उससे खराब हो जाएगा। जब शिमला में पीलिया फैला तो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हो गए तब अश्वनी खड्ड के पानी की स्कीम को बंद किया गया। वह पानी तो शहर के लिए कम हो गया उसके बदले कोटी-बरांडी से 2 एम.एल.डी. कभी 3 एम.एल.डी. पानी आने लगा और उसे शिमला शहर के लिए देने लगे। जब इतना पानी कम हो गया और जैसा आप सभी जानते हैं कि शिमला शहर में पानी की खपत बहुत ज्यादा है। उसके कारण यहां पानी की कमी हुई। यह ठीक है कि घडल की योजना के बारे में जो माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य जी ने बताया है वह बहुत जल्दी में बनाई गई है।

वह माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र था लेकिन उसी चुनाव क्षेत्र का कुछ हिस्सा शिमला नगर निगम में आया है। टुटू के दो बार्ड उसमें शिमला नगर निगम में शामिल हैं। बालूगंज के दो बार्ड हैं वे दोनों ही शिमला ग्रामीण के हैं वे शिमला नगर निगम में हैं। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी से हमने इसी सदन में चर्चा की थी, मैने उनसे निवेदन किया था और उसके बाद मैं उनसे मिला भी था। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि गंढल का पानी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां से पानी स्पेयर किया जा सकता है। कम-से-कम आपके जो चार बार्ड हैं उनको यदि वह पानी मिल जाए तो शिमला को पानी मिल जाएगा। उस वक्त वे सहमत हो गए थे। जब यहां पर पीलिया पर चर्चा हुई थी उसके तुरंत बाद बैठक हुई थी, मैं और माननीय सदस्य श्री अनुरूद्ध सिंह जी बैठक में मौजूद थे। उस वक्त मैंने एक और बात कही थी कि शिमला में पानी की दिक्कत इस लिए आती है कि यहां पर पानी की सप्लाई आई.पी.एच. विभाग देता है और पानी जो शहर के लिए बांटा जाता है वह नगर निगम द्वारा बांटा जाता है और बिजली बोर्ड इसके लिए बिजली देता है। जब आई.पी.एच. से पानी नहीं आता है तो वह कहते हैं कि बिजली नही

28.08.2018/1555/डी.टी./एच.के./-2

आई । इसलिए पानी की पंपिंग नही हुई या वे कह देते थे कि सप्लाई तो हम पूरी दे रहे हैं परंतु पानी का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो रहा है। नगर निगम कह देता था कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा है। इसलिए तीनों विभागों का झगड़ा रहता था। इस बारे में उस वक्त मीटिंग हुई थी । श्रीमती अनुराधा जी उस समय आई.पी.एच. विभाग की सचिव थी। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, मैं, माननीय अनिरूद्ध जी तथा श्री संजय चौहान जी मेयर थे हम सब बैठक में हाजिर थे। फिर तय हुआ कि शिमला के लिए एक अलग से सर्कल दिया जाएगा। वे शिमला के लिए सप्लाई भी देंगे और पानी का बंटवारा भी करेंगे। उसके बाद इसके लिए यहां अलग से सर्कल स्थापित किया गया । हम बहुत समय से यह सुनते आ रहे

थे और माननीय वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि मैं शिमला के लिए चंद्र नाहन से पानी लाऊंगा। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में कहा कि आप बहुत बार यह कह रहे हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि ये रोहड़ू का पानी शिमला को पिलाना चाहता है। लेकिन उसमें हमारा जो खर्चा था ज्यादा था और सारे रास्ते में उसमें ढांक है और वन का क्षेत्र है इसलिए वहां से पानी लाना संभव नहीं था। पब्बर का वह कैचमैंट एरिया है इसलिए पब्बर पर जो प्रोजैक्ट लगे हैं उसमें वह पानी आ नहीं सकता । इस कारण से आदरणीय धूमल जी की दूसरी बार की सरकार थी । माननीय सदस्य आशा कुमारी जी यहां नहीं बैठे हैं अन्य माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उस वक्त श्री अरविन्द मैहता जी वित्त सचिव थे। उन्होंने मेरे को विशेष रूप से बुला करके कहा था कि भारत सरकार ने जो कोल डैम की स्कीम है उसको वल्ड बैंक को भेज दिया है। ये एग्जैक्ट शब्द उनके थे । यह लगातार प्रक्रिया है उसके बाद पांच साल चलते रहे उस वक्त की सिंचाई मंत्री आदरणीय विद्या स्टोक्स जी थी उनको ध्यान पुराना ही रहा होगा तो वे चन्द्र नाहन से ही पानी लाने की बात करती रही और

श्री एन.जी. द्वारा जारी .....

28/8/2018/1600/वाई0के0/एन0जी0-1

शिक्षा मन्त्री जारी.....!

और स्कीम कोल डैम की बन रही थी, लेकिन पांच साल में वो स्कीम नहीं बनी । मैं धन्यवाद करूंगा अपने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री और मुख्य सचिव महोदय का, जिन्होंने प्रयत्न करके उस स्कीम का स्ट्रक्चर भी बना दिया और वर्ल्ड बैंक ने भी उस स्कीम को फन्डिंग करने की मंजूरी दे दी है । इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में शिमला को जो 65 एम.एल.डी पानी की आवश्यक्ता है, वह पूरी हो जाएगी । इन क्राईसिज के ऊपर विचार करने की आवश्कता है। माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि शिमला ग्रामीण की स्कीम से हम एक ईंच पानी शिमला को नहीं देंगे । वह विधानसभा

क्षेत्र भी तो आपका है, उसके आपके भी चार वार्ड हैं। आपके दादा जी और आपके पिता जी तो शिमला के लोगों के लिए पानी के पिआऊ लगाया करते थे और आप कह रहे है कि हम शिमला को एक ईंच भी पानी नहीं देंगे । आई.पी.एच. विभाग ने उस समय कहा कि हम 10 लाख लीटर पानी स्पेयर कर के शिमला को दे सकते है । हमने कहा कि आप केवल टुटू को ही पानी दो क्योंकि जब यह स्कीम बनी थी तो टुटु इसका पार्ट नहीं था । आज शिमला नगर निगम के तहत टुटू में भी पानी के कनैक्शन्ज हैं और आईपीएच के कनैक्शन्ज भी टुटू में हैं। इसी प्रकार शिमला नगर निगम से बाहर का जो ऐरिया है उसके लिए भी हम सब प्रैशर डालते हैं कि इन्हें भी कनैक्शन दे दो जब पानी पीक पर होता है और जब पानी नहीं होता है तो सबको समस्या हो जाती है । मैं इस बात को मानता हूं कि इस बार शिमला में पानी का क्राईसिस आया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी का, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहुंगा क्योंकि मैं अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण यहां पर वक्त नहीं दे पाया और माननीय मुख्यमन्त्री जी ने अपने घर पर बैठ कर इस समस्या की पूरी मोनेटरिंग की और समस्या के समाधान के लिए हाई लेवल मिटिंग बुलाई । माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश स्वयं नगर निगम के दफतर जा कर के पूरी की पूरी स्कीम बना कर आए ।

28/8/2018/1600/वाई0के0/एन0जी0-2

उपरले स्तर पर पूरी मोनिटरिंग हुई ताकि किसी को पानी से वंचित न रहना पड़े । थोड़ी बहुत गड़बड़ इसलिए हुई कि जब प्रशासन ने जोनिंग सिस्टम किया तो जहां पानी पिछले 3-4 दिन नहीं आया तो जोनिंग सिस्टम में उनकी बारी तीसरे दिन हो गई । इस कारण उस क्षेत्र के लोगों को लगा कि हमको तो पानी मिल ही नहीं रहा है, आज तक नहीं मिला तो हमें तीसरे दिन भी नहीं मिलेगा । इस लिए कुछ लोगों ने इस समस्या का राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिश की और जनबूझ कर के प्रोब्लम क्रियेट किया । मैं सहमत हूं, हमारे मित्रों ने जो कहा है कि सारी दुनिया और देश में शिमला का नाम पानी न होने की वजह से बदनाम हुआ । लेकिन यह बहुत अल्पकाल के लिए था क्योंकि सरकार इतनी संवेदनशील है कि राजधानी शिमला में पानी के क्राईसिस को सैटल करने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री,

माननीय कैबिनेट मन्त्री, मुख्य सचिव और उपायुक्त शिमला, सभी लोग इसके समाधान के लिए पुरजोर के साथ लगे हुए थे । सरकार ने शिमला में पानी की समस्या को समाधान करने के लिए सभी अधिकारियों को काम में लगाया था ताकि पानी की क्राईसिज न हो। जैसे लडाई/युद्ध के समय देश को सभी लोगों की जरूरत होती है और लोगों को कहा जाता है की वर्दी पहनो और लड़ाई में जाना पड़ सकता है । यहां पर भी उसी प्रकार के क्राईसिज हो गए थे। पानी ना मिलना बहुत गम्भीर बात होती है और उसके लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। इसके चलते शिमला का समर फैस्टीवल पोस्टपोन हो गया है, वो दोबारा हो जाएगा। लेकिन पानी ज्यादा जरूरी था उसके लिए प्राथमिकता पर काम किया गया। उसके लिए मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमन्त्री जी को, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई देनी चाहिए । मैं कमेंट नही करना चाहता लेकिन इस प्रकार के काम बहुत सारी चीजें में हो रहे हैं । ये सब काम तब हीं हो रहे हैं जब पिलिया हुआ था तब भी मैंने यही कहा था । उससे पहले जब विधायकों की गाडियां रोकी गई थी, उनकी गाडियों को मैट्रोपोल के पास खड़ा नहीं करने दिया गया और एक गाड़ी का चालान हो गया था तो माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर के मुख्य सचिव, डीजीपी सबको बुलाकर के कहा था कि क्यों चालान किया गया। तब भी मैने इसी माननीय सदन में कहा था कि संविधान में सबके अपने-अपने दायरे हैं और

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

28/08/2018/1605/RG/YK/1

शिक्षा मंत्री-----जारी

उनके अंदर ही हमें काम करना चाहिए। जो कार्यपालिका का दायरा है उसको अपना काम करना चाहिए। यदि वह अपना काम नहीं करती है, तो जो न्यायपालिका को करना चाहिए, उस समय उसका न्यायपालिका संज्ञान ले। विधायिका के काम में यदि दखलन्दाजी करेंगे, तो इससे संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसके बाद संज्ञान लिया। जब तीनों ज़ोन बन चुके थे, काम लग चुका था और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारे अधिकारी काम में लगे हुए थे, उसके बाद पी.आई.एल. फाईल हुई। फिर पी.आई.एल.

दायर करने का भी एक सिस्टम है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पी.आई.एल. फाईल करते हैं और फिर उसके आधार पर काम होना शुरू हो गया। हालांकि पहले मैं उस साइड को था तो बोल सकता था लेकिन आज मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि हम भी अपने दायरे को पार करेंगे, तो निश्चित रूप से संवैधानिक अव्यवस्थाएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए संविधान के दायरे में रहकर हमको काम करना चाहिए कि ऐसे संकट भी हो सकते हैं और उसमें जहां थोड़े लैप्सेस रहे हैं, जिसको मैं मान रहा हूं। किसके रहे हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। उसमें बहुत सारे विभाग हैं, निगम है, सब हैं। किसमें कमी रही, क्या अच्छा रहा, यह अलग बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय दिन-रात काम किया। उस समय मेरी पत्नी पी.जी.आई. में थी और मेरा बेटा आई.जी.एम.सी. में भर्ती था, तो वे आई.जी.एम.सी. देखने आए थे और मुझे उन्होंने मना किया। लेकिन जिस मीटिंग में यह सब तय हुआ था, उसमें मैं भी हाज़िर था। हालांकि उन्होंने मुझे मना भी किया था कि आप मत आइए। उन्होंने सारा काम अपने ऊपर ले लिया और हाइऐस्ट लेवल पर काम किया। मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत प्रशंसा होनी चाहिए और भविष्य के लिए जो यह हमारी 65 एम.एल.डी. की विश्व बैंक की स्कीम है, यह पूरी हो जाए। क्योंकि जो चन्द्रनाहन से हमारे यहां पानी लाने की बात है, उसमें रेकरिंग ऐक्सपैंन्डीचर नहीं होगा। लेकिन शुरूआती ऐक्सपैन्डीचर बहुत ज्यादा है और वन क्षेत्र उसमें बहुत अधिक शामिल है। इसलिए वह नहीं आ पाएगा। कोल डैम से पहले स्कीम नहीं बन सकती थी, सतलुज में सिल्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कोल डैम के होने से सिल्ट नीचे बैठ जाती है। इसलिए उसका रेकरिंग ऐक्सपेंडीचर कम हो जाएगा। यदि वह स्कीम बनेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा।

28/08/2018/1605/RG/YK/2

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक वह स्कीम बनेगी, उससे पहले जिसका इस बार भी इस्तेमाल किया, चाबा से गोमा में पानी डाला गया और वह भी टैंकर्ज में लाकर डाला गया। सांईं फॉउन्डेशन के टैंकर्ज फ्री ऑफ कॉस्ट इस सारे संकट के समय में दिए गए, जिन्होंने यह काम किया। अब वहीं से पानी गुमा के सोर्स में आए और वहां से हमारी नॉर्मल सप्लाई में आ जाए, इससे शिमला का भला होगा। शिमला में बहुत ऐक्सपेंशन हो रही है। लेकिन एक बात का मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम हिमाचल प्रदेश के

पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन बाहर जाए, यह हम सबकी इच्छा है। लेकिन उसके कारण शिमला, धर्मशाला, मनाली और कसौली या डलहौजी, उनको समाप्त करने या उनको अण्डरमाइन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आज भी आप संसार में जाएंगे, तो शिमला, डलहौजी या कसौली के नाम से हिमाचल जाना जाता है। इसलिए हम शिमला के पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस प्रकार की ऐडवाइसेज गई हैं, तो मैं समझता हूं कि वे उचित नहीं थीं। लेकिन किस कारण से वे गई हैं? क्योंकि कई बार संकट में इस प्रकार के निर्णय हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि शिमला में पर्यटक आए अन्यथा शिमला का बिजनेस समाप्त होता जा रहा है। अगर पर्यटन नहीं रहेगा, तो शिमला में जो पहले ऊपर के लोग आकर राशन-पानी या सब चीजें लेते थे, वे अब सीधे परवाणु से लाते हैं। क्योंकि शिमला में सब्जी मण्डी चढ़ने के लिए हैड लोड बहुत अधिक पड़ता है, अनाज मण्डी जाने के लिए हैड लोड बहुत पड़ता है। इसलिए वे यहां नहीं आते। पर्यटक आएगा, तो काम चलेगा और अगर शिमला में पर्यटक आएगा, तो सारे हिमाचल प्रदेश में वह जाएगा। इसके लिए यदि हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। उसमें बहुत सारे लोगों ने संयम भी बरता है। इसमें अनिरूद्ध सिंह जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उनके 12 वार्ड इसमें पड़ते हैं, विक्रमादित्य जी के चार वार्ड इसमें पड़ते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में इन्होंने भी कोशिश की। हमारे जितने भी पार्षद थे, सबने अपने-अपने वार्ड में व्यवस्था बनाने के लिए और पानी की सप्लाई प्रॉपर देने के लिए कोशिश की। जहां पानी नहीं पहुंच सकता था, टैंकर से सप्लाई हो जाए, इसके लिए काम किया है। मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से विक्रमादित्य जी और अनिरूद्ध जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा को यहां लाया ताकि हम सब आगे आने वाले भविष्य में इससे

28/08/2018/1605/RG/YK/3

सबक लेकर ठीक प्रकार से काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय

28/08/2018/1610/MS/AG/1

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण देना है।

अध्यक्षः पहले माननीय मंत्री जी को चर्चा का उत्तर देने दीजिए फिर आप स्पष्टीकरण दे देना।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्षः ठीक है।

Shri Vikramaditya Singh: Sir, I just want to straight the record. माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि मैंने किसी वॉर्ड में पानी देने के लिए ऑब्जैक्ट किया है। हमारा व्यू डॉग्मेटिक नहीं है बल्कि प्रेग्मेटिक है और मैंने कभी यह नहीं कहा कि किसी क्षेत्र को पानी न दिया जाए। मैंने केवल इतना निवेदन किया था कि जो स्टॉप-गैप अरेंजमैंट है यह परमानैंट नहीं हो जाना चाहिए। अगर हमने कोई जुगाड़ किया है या टांका लगाया है तो that should only be for one particular instance but that cannot be the norm. यही मेरा कहना है। मैंने सिर्फ इस चीज को ऑब्जैक्ट किया था। अगर कभी पानी की क्राइसिज होती है और कहीं भी पानी दिया जाता है तो इसमें हमारा कोई ऑब्जैक्शन नहीं है।

28/08/2018/1610/MS/AG/2

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री नियम-130 के अंतर्गत हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस सदन के तीन माननीय सदस्यों आदरणीय श्री अनिरूद्ध सिंह जी, आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी और आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने नियम-130 के अंतर्गत "शिमला शहर की पेयजल समस्या पर यह सदन विचार करे" बारे प्रस्ताव दिया था। आदरणीय अनिरूद्ध सिंह जी ने बहुत ही पॉजिटिव इसमें कहा है कि यह समस्या किसी दल या पार्टी की नहीं है बल्कि यह समस्या पूरे शिमला शहर की है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अनेकों सुझाव भी

दिए हैं। जिनमें रिज़ के टैंक को नये सिरे से बनाने का सुझाव दिया है। इसी तरह से टैंकों की क्षमता बढ़ाने की बात कही है और पानी के वितरण के बारे में भी इन्होंने कहा है कि इसकी प्रौपर तरीके से रेशनेलाइजेशन की जाए और मीटर के लिए भी इन्होंने कहा है। हमारे युवा विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने भी इस पर काफी चर्चा की है और पर्यटन के बारे में भी चिन्ता जाहिर की है। इन्होंने एक स्कीम का भी जिक्र किया है। विक्रमादित्य जी, आपका बहुत लम्बा भविष्य है। जब हम भी पहली बार विधायक चुनकर आए थे तो उस वक्त हम भी बिना सोचे कई बार ऐसा कह देते थे। आपने एक बात कही कि मुझे बिना पूछे घरोग-घण्डल स्कीम से कैसे पानी लिया गया? मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई स्कीम बनती है तो वह सरकार की स्कीम होती है। वह स्कीम किसी मंत्री या विधायक की नहीं होती है बल्कि वह आम जनता की होती है। जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उस स्थिति में किसी-न-किसी प्रकार से उसका समाधान करने के लिए किसी की भी सहायता ली जा सकती है। उस पानी को उस स्कीम से कोई परमानैंट नहीं जोड़ा गया है। मेरा आपको यह सुझाव रहेगा।

इसी तरह से मेरे भाई राकेश सिंघा जी ने बहुत पुरानी यादें ताज़ा करवाई। निश्चित तौर से जहां से पानी लिफ्ट होता है, मैं स्वयं वहां गया था और मैंने वहां एक बात जरूर पूछी कि ये जो पाइपों के ढेर लगे हैं ये क्यों लगे हैं? इसके अलावा जहां से राइजिंग मेन की पाइपें बिछी हैं वहां पर भी मैं देख रहा था कि जो नई पाइपें हैं वे जोड़ी गई हैं और पुरानी पाइपें भी उस पहाड़ पर कई जगह देखने को मिली हैं। निश्चित तौर पर आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार जहां गलत होगा, वहां गलत को गलत कहेंगे और जहां ठीक

28/08/2018/1610/MS/AG/3

होगा, वहां ठीक को कभी गलत नहीं कहेंगे यानी ठीक को ठीक ही कहेंगे। जो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की बात कही है जिसमें ठियोग वाले ट्रीटमैंट प्लांट की भी बात कही है और इसके अलावा नीचे जो मलाणा का सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट है उसकी भी बात कही गई है तो इस पर भी हम संज्ञान लेंगे।

आदरणीय राकेश जम्वाल जी ने कहा कि यह जो शिमला में पीने-के-पानी की समस्या है यह कोई एक दिन, एक महीने या चार महीने में पैदा नहीं हुई है

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

28.08.2018/1615/जेके/एचके/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः----जारी-----

इसके लिए जो-जो वर्तमान सरकार कर पाई है, उसके लिए आपने जो कहा उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी बहन आशा कुमारी जी ने एक बात कही कि अधिकारियों ने कोई ऐसी एडवाइज़री जारी की, विशेषकर जो हमारे टूरिज्म डिवैल्पमैंट के अधिकारी हैं, अर्बन डिवैल्पमैंट के अधिकारी हैं, किसी भी अधिकारी ने कोई ऐसी एडवाइज़री जारी नहीं की। जब यह समस्या उठी तो उस वक्त बहुत अखबारों में, इलैक्ट्रोनिक मीडिया में ये चीजें बढ़ती चली गई। अनेक चैनल थे, अपनी मर्जी से दिखाते चले गए । उसमें यहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये निर्दोष हैं क्योंकि इन्होंने किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने चीफ सेक्रेटरी जी का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनकी पूरी टीम का, चाहे उसमें आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट है, चाहे उसमें हमारे म्युनिसिपल कार्पोरेशन के लोग हैं या दूसरे विभागों के लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सबने ही एक टीम के रूप में काम किया। बल्कि मैं आपके ध्यान लाना चाहता हूं कि मैं खुद यहां पर था और कई रातें तो हमारी ऐसी निकली कि हम सारी-सारी रात सोये तक नहीं। हम इस पानी की प्रक्रिया को सुधारने के लिए रात को भी दौड़ते रहे। इसी प्रकार से बहुत से अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने 24 घण्टे अपनी सर्विसिज़ दी। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में काफी ज्यादा कहा क्योंकि इनका चुनाव क्षेत्र भी है और इनके चुनाव क्षेत्र के साथ-साथ अनिरूद्ध सिंह जी का भी चुनाव क्षेत्र है और विक्रमादित्य सिंह जी का भी चुनाव क्षेत्र साथ में पड़ता है। तीनों ही विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के जो

हमारे यहां से चुने हुए आदरणीय विधायक व आदरणीय मंत्री जी हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस बार का जो ये सूखा पड़ा, मैं ऐसा समझता हूं कि वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और बादल फटे लेकिन 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 ये तीन साल ऐसे निकले कि इन तीन वर्षों में जिस अनुपात में पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ पड़ती थी, वह

28.08.2018/1615/जेके/एचके/2

हमें देखने को नहीं मिली। जिस प्रकार से बरसात में बारिश होती थी उस बारिश के अनुपात में इतनी कमी आ गई और विशेषकर जो 2017-18 का वर्ष है, इस वर्ष में तो ऐसा लगा कि बारिश ही नहीं हुई। किसी नाले में हमने पानी नहीं देखा, किसी झरने में हमने पानी नहीं देखा। यह जो सारी समस्याएं खड़ी हुई ये केवलमात्र शिमला शहर में ही नहीं हुई। पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा। जब पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने मुझे आदेश किए कि आप पूरे प्रदेश में जा कर जिला स्तर पर बैठकें करो और उन बैठकों में आप सुनिश्चित करो। ठाकुर राम लाल जी यहां पर बैठे हैं, हमने सबसे पहले बिलासपुर में बैठक की थी ।क्योंकि बिलासपुर ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर जिस पर का हो-हल्ला होना था, उससे हम बच गए। हमने पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में जा कर बैठकें की। उन बैठकों में हमने ऐसा भी नहीं किया कि हमने सत्ता पक्ष व विपक्ष को देखा । मेरे ऑफिस से और मैंने खुद भी कोशिश की है, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी इस बात के ग्वाह है क्योंकि हमने जिस दिन ऊना में बैठक की तो मैंने खुद इनको आमंत्रित किया कि आप आइए क्योंकि यह बैठक कोई राजनीतिक लक्ष्यों को ले कर नहीं है। यह बैठक इसलिए है कि जो आने वाला समय है, ऐसा लग रहा है कि उसमें बड़ी गम्भीर समस्या हमारे प्रदेश के सामने खड़ी होने

वाली है। वह गम्भीर समस्या कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए ही खड़ी नहीं होगी बल्कि वह हमारे पूरे प्रदेश के लिए होगी इसलिए हम इसका किसी न किसी प्रकार से समाधान करें।

श्री0एस0एस0 द्वारा जारी-----

28.08.2018/1620/SS-DC/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

जहां तक शिमला शहर की वाटर सप्लाई का प्रश्न है वह तीन खड्डों से आता है। हमारी गुम्मा की खड्ड से पानी आता है। हमारी गिरी की खड्ड से पानी आता है और हमारी अश्वनी की खड्ड से पानी आता था। लेकिन अब हमने अश्वनी की खड्ड से पानी उठाना बंद कर दिया क्योंकि 2015-16 में जो यहा शिमला शहर में पीलिया फैला, उसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन उस समय गुम्मा और गिरी नदी से पानी आता था। इससे पहले 2013 से लेकर 2017 तक विश्व बैंक की एक परियोजना थी, जिसका यहां ज़िक्र हुआ है, उस परियोजना का एक कंसैप्ट नोट, जब आदरणीय धूमल जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उनके समय में भारत सरकार को भेजा गया था। एक प्रक्रिया है। उनके समय में भेजा गया, आपकी सरकार आई, आपने उसे फोलो अप किया। जब फोलो अप किया गया तो उसके बीच में मैंने ऐसा महसूस किया है कि आई0पी0एच0 विभाग की मंत्री और मुख्य मंत्री के मध्य जो सहमति बननी चाहिए, उसके बनने में दिक्कत आई है। --(व्यवधान)-- जो उस वक्त आई0पी0एच0 मिनिस्टर थीं, वे चाह रही थीं कि शिमला के लिए चांशल का पानी लाया जाए और प्रदेश के उस वक्त के मुख्य मंत्री, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी चाह रहे थे कि कौल डैम से पानी लाया जाए। मुझे लगता है कि उसी वजह से इधर-उधर फाइलें घूमती रहीं, दौड़ती रहीं और जो निर्णय आपको 2013 और 2014 में करना चाहिए था, उस निर्णय को करते-करते काफी देर हो गई। विश्व बैंक इंतजार करता रहा कि डे ऑफ दी गवर्नमैंट आए, बात करे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें मैंने यह महसूस किया कि उस प्रक्रिया को बढ़ाने में कुछ कमी रही है। निश्चित तौर पर आपने फैसला लिया कि अब पानी चांशल के बजाय कौल डैम से

लेंगे। जैसे आदरणीय भारद्वाज जी ने कहा कि एक बहुत लम्बी ग्रैविटी में लाइन आनी थी, उसमें अनेकों पेड़ जाने थे, उसमें वन टाइम इंवैस्टमैंट बहुत थी लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हो सकते थे। लेकिन उसमें भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूंगा कि उसमें जो कमी रही है उसका खामियाजा हम सबको 2017-2018 में भुगतना पड़ा। 2017-18 में बर्फबारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई और एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय मई और जून के महीने में यहां आए थे तो उस वक्त मेरी डयूटी उनके साथ लगी थी। एक दिन वहां का स्टाफ कहने लगा कि यहां नहाने के लिए पानी नहीं है। अब हम उस

28.08.2018/1620/SS-DC/2

तरफ बंधे हुए थे तो हमें भी किसी ने ऐसा आगाह नहीं किया कि ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। मैं इस हाउस में आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी दिल्ली वापिस लौटे, उसके अगले ही दिन प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने चीफ सैक्रेटरी महोदय सहित उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन करने के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो पीने के पानी की समस्या शिमला शहर में पैदा हुई है उसकी मोनिटरिंग वे स्वयं करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि जब मुख्य मंत्री जी आगे आ जाएं कि मैंने खुद इसकी मोनिटरिंग करनी है तो क्या काम नहीं हो सकता। मैं बल्कि घर चला गया था। मेरे को माननीय मुख्य मंत्री जी का फोन गया कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि छः - सात दिन तो राष्ट्रपति के साथ रहा हूं और एक-दो दिन अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र में लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र को छोड़कर तुरन्त शिमला आ जाओ। उन्होंने मेरी डयूटी भी लगाई और डयूटी लगाने के साथ-साथ पूरे शिमला शहर को तीन जोनों में बांट दिया। मेरे शिमला आने से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे महत्वपूर्ण कदम उठा लिये थे। जब शिमला को तीन जोनों में बांटा तो

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2018/1625/केएस/डीसी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी---

तीन जोन में बांटने के साथ-साथ उस वक्त हमने महसूस किया कि क्या कारण है कि हमारे यहां पानी कम आ रहा है? मैंने सोचा कि हम यहां इन टैंकों की तरफ घूमते रहेंगे तो टैंको से तो पानी निकलने वाला नहीं है। अगर सोर्स से पानी नहीं उठेगा तो टैंक से कहां पानी सप्लाई होगा ? अपनी टीम के साथ, अधिकारियों के साथ हम गुम्मा गए। हम उस खड्ड में, उसका जो कैचमैंट था, उसमें ऊपर तक चले गए। हमने काफी एरिया देखा। उसको देखने से यह पाया गया कि लगभग 12-14 कूहलें वहां ऐसी चली हुई हैं जो अंग्रेजों के समय से चल रही थी और जिनका जिक्र आदरणीय भारद्वाज जी ने भी किया कि वे कूहलें उस वक्त की थीं। वे कूहलें राजस्व रिकॉर्ड में लगी हुई थी और जब ऐसी आफ़त आती थी तो उनका पानी बंद किया जाता था लेकिन इसके लिए वहां के किसानों को फसल की मुआवजा राशि रखी गई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से पहले जितनी बार उन कूहलों को बन्द किया गया, वहां के किसानों को उनकी जो फसलें हैं, विशेषकर वहां पर सब्जी का बहुत बड़ा कारोबार है, उस वक्त से पहले उनको सभी ने आश्वासन ही दिया कि आपको इसका मुआवज़ा दिया जाएगा लेकिन किसी ने उनको मुआवज़ा नहीं दिया। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा, इन्होंने उन किसानों की सारी की सारी मुआवजा राशि दी । मैं उन किसानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, 12 कूहलों के अलावा वहां पर सैंकड़ों ऐसी एच.बी.डी. पाइप से अपने टुल्लू पम्प उस खड्ड से लगाए हुए थे और मैंने जब वहां एक किसान से बात की तो उसने कहा कि ये मेरे खेत हैं। मेरी दो बेटियां युनिवर्सिटी में पढ़ती है और चार लाख रुपया एक साल का उनका खर्चा है जिसको मैं इन खेतों से निकालता हूं। आप देख रहे हैं कि इन खेतों में सब्जी है या नहीं है? मैंने कहा कि बहुत सब्जी है। तो वह कहने लगा कि हम क्या करें? हमने उनके साथ बैठकर अपने अधिकारियों को भी साथ बैठाकर उनके साथ जो नैगोशिएशन की, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 15 घण्टे हम पानी खड्ड में छोड़ेंगें उस पानी को आप शिमला के लिए

उठा लें और 9 घण्टे हम अपने खेतों में पानी लगाएंगें। हमने कहा कि हमें मंजूर है। उस फैसले को करने के उपरांत जो हमारी पानी की कमी थी, उसमें काफी सुधार हुआ। इसके अलावा एक राइज़िंग मेन जिसकी यहां पर चर्चा की गई, विक्रमादित्य जी ने भी कहा, भारद्वाज जी

28.08.2018/1625/केएस/डीसी/2

भी कह रहे थे कि एक बहुत पुरानी राइज़िग मेन है और उसके आगे जो एक ग्रेविटी मेन है, क्रैगनैनो से ले कर ढली और ढली से आई.जी.एम.सी. तक वह अंडर ग्राउंड थी। पता नहीं चलता था कि उसमें कहां-कहां से पानी लीक हो रहा है। मैं आई.पी.एच. विभाग के अपने इंजीनियर्ज़ को, अपने अधिकारियों को बधाई दूंगा, इन्होंने रात-दिन उसकी रैकी की और उसके बाद जहां-जहां लीकेज़ थी, लीकेज़ कोई थोड़ी नहीं थी। अध्यक्ष जी, हमने महसूस किया कि जो पानी नीचे से ऊपर उठता था, क्रेगनेनो को उठता था और वहां से आगे जो ग्रेविटी से पानी आता था लगभग

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.8.2018/1630/av/hk/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री-------- क्रमागत

6-7 एम0एल0डी0 पानी उस लीकेज में चला जाता था। आपके समय में उस ग्रेविटी मेन में नई लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और हमने उस काम को आगे बढ़ाया। अब हमारा काम लगभग 85 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और जो 15 प्रतिशत शेष रहता है उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम गिरि कैचमैंट में गये, वहां हमने यह देखा कि सैंज से लेकर के हमारे पम्प हाउस तक कम-से-कम हजार-पन्द्रह सौ पाइपें थीं जो कि उस खड्ड में डाली गई थी। वहां से टुल्लू पम्प लगाकर सारे किसान अपने-अपने खेतों को पानी देते थे। हमने वहां उनके साथ बैठक की जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है शिमला शहर में पीने के

पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे लोग भी शिमला में है और हम आपको वायदा करते हैं कि हम अपनी इन पाइपों को हटायेंगे। हम ज्यादा-से-ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारी सब्जी के लिए आवश्यक पानी चलता रहे और शिमला शहर के लिए भी पानी मिलता रहे, ऐसा करने से पानी की बढ़ोतरी हो गई। हमने गिरि पम्प हाउस कम्पलैक्स में इमिडियेटली बोर वैल की मशीन मंगवाई। हमने वहां पर एक-दो बोर वैल लगाकर कोशिश की कि कहीं अंडरवाटर उपलब्ध हो जाए। हम यह सोच रहे थे कि अगर हमें 3, 4 या 5 एल0पी0एस0 पानी उपलब्ध होता है तो ठीक है मगर वहां पर हमें 1 से 2 एल0पी0एस0 पानी मिला, हमने उसका भी सदुपयोग कर लिया। वहां पर सर्कुलेशन के बाद जो पानी बाहर निकलता था हमने उसको भी पकड़ा तथा उस पानी को दोबारा सर्कुलेशन में डाल दिया। हमने यह कहा कि जो पानी वैस्ट बह रहा है उसको दोबारा वाटर ट्रीटमैंट प्लांट में डालो ताकि शिमला शहरवासियों को पीने का पानी मिले। इन प्रयासों के साथ-साथ आदरणीय मुख्य मंत्री जी के मार्ग दर्शन में हमने यहां पर टैंकर्स की व्यवस्था की, आदरणीय अनिरुद्ध जी कह रहे थे कि टैंकर्स के लिए आपको टाइमली टैंडर करने चाहिए थे। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हर वर्ष इसी प्रकार से प्रक्रिया होती थी। हमने एक बार कह दिया था कि जितने टैंकर लगा सकते हैं, उतने लगा दो। मैं साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऑफर दी

28.8.2018/1630/av/hk/2

और कहा कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे तथा बिना पैसे के टैंकर लगायेंगे। साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन वालों ने तीस बड़े-बड़े, 18-18 हजार लीटर केपेसिटी के टैंकर लगाये। उन्होंने टैंकर लगाने के साथ-साथ कोल डैम से उनको भरने का काम भी खुद किया। इस धरती पर ऐसे लोग भी है जो मानवता की सेवा करने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने वहां पर अपना सिस्टम इनस्टाल किया, श्री राज कुमार वर्मा जी इस फाउंडेशन के अग्रणी व्यक्ति है। वे खुद वहां पर रात-दिन बैठे और वहां से रॉ वाटर उठाकर के गुम्मा वाटर ट्रीटमैंट प्लांट में डालते रहे जिस कारण से हमारी यहां पेयजल समस्या में कुछ कमी आई। इसके अतिरिक्त

जो टैंकर्स हमने लगाये थे कुछ उससे दूर हुई तथा किसानों द्वारा हमारी बात मानने से भी काफी हद तक पानी की समस्या दूर हुई। यहां के टैंक चैक करने से कुछ नहीं मिलना था बल्कि वहां काम करने से हमारी यहां की पेयजल समस्या दूर हुई है। मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह एक कठिन काम था और तीन जोन्स का काम था। उसमें ठीक है और हम स्वीकार करते हैं कि कुछ कमियां रही होंगी। मगर जो काम करेगा गलती उसी से होगी और जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती कहां से होगी। उस समय तीन जोन्स में काम किया गया। कई बार एक जगह की सप्लाई टूट गई तो उसको फिर चार दिन के बाद सप्लाई मिली। हम इस बात को मानते हैं कि चार दिन के बाद सप्लाई मिली लेकिन इस बात के लिए मैं मुख्य मंत्री जी और अपने अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम घर-घर गये। हमने अपने अधिकारियों की टीमें बना दीं। जिस जोन का पानी छोड़ा गया उसके अलग-अलग हिस्से कर दिए कि आप इस हिस्से में जाकर के घर-घर में यह पूछेंगे कि पानी आया या नहीं आया। इस तरह से घर-घर जाने से यह फायदा हुआ कि (---व्यवधान---) आदरणीय अग्निहोत्री जी-----

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2018/1635/TCV/HK-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी

(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप ये बताएं कि आपकी शहरी विकास मंत्री क्या कर रही थी, आपकी नगर निगम क्या कर रही थी? मेयर को आपने चायना क्यों भेज दिया था? --- (व्यवधान)--- आपकी शहरी विकास मंत्री कहां गई है? ---(व्यवधान)---

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आप सुनिए, आप सुनिए तो सही। आप विपक्ष के नेता है। आदरणीय अग्निहोत्री जी ये सरकार का छाता है और सरकार के छाते में सभी आते हैं।

सरकार के जितने भी बोर्ड, कारपोरेशन्ज़ व विभाग है, वे सभी गवर्नमैंट के दायरे में आते हैं। ये मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः कृपया शोर न मचाएं। माननीय मंत्री जी आप अपना उत्तर दें।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः इस दौरान जब हम घर-घर जा रहे थे तो हमें ऐसी अनेकों अनियमितताएं देखने को मिली ---(व्यवधान)--- ठाकुर जी (श्री राम लाल ठाकुर) अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस हो कि हम नहीं गये या हमारे अधिकारियों ने काम नहीं किया तो आप हमें पूछें। ---(व्यवधान)--- आप कानों से सुनिए मुंह से ज्यादा न बोलिए। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः जब हम घर-घर जा रहे थे तो अनेकों अनियमितताएं हमारे सामने आई और अनेकों कनैक्शन्ज़ हमें काटने पड़े जिनमें से कुछ कनैक्शन तो ऐसे थे कि 2-2 इंच की पाइपों के कनैक्शन दिए हुए थे। क्या वे कनैक्शन्ज़ हमारे आने पर लगे? कुछ कनैक्शन्ज़ तो ऐसे थे जो सड़क से 6-6 फुट नीचे से लिए

28.08.2018/1635/TCV/HK-2

हुए थे। वे भी किसी के समय लगे होंगे। मैं यह नहीं कहता कि ये आपके समय में लगे होंगे। ये न मुझे पता है और न आपको पता है। ---(व्यवधान)--- इन परिस्थितियों को देखते हुए जिन निर्णयों को आप नहीं ले सकें, हम उन निर्णयों को ले रहे हैं। पहला निर्णय है कि मध्यकालीन, दीर्घ और दीर्घकालीन उपाय हमने प्रस्तावित किए हैं। चाबा हाईडल प्रोजेक्ट से पानी उठाकर हम गुम्मा तक लाएंगे। उसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने स्टेट हैड से 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। अगर आप ये काम पहले कर देते जो अब हमें करने पड़ रहे हैं तो ये समस्याएं न आती ।

दूसरा, हम अगली गर्मी से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं।

श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा जारी ।

28-08-2018/1640/NS/YK/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री -----जारी

दूसरा, जो विश्व बैंक की परियोजना है, यह हमारी बहुत बड़ी परियोजना है और इसमें दिक्कत आई थी। इसमें जिस प्रकार का फॉलो-अप लेना चाहिए था, वह नहीं लिया गया था। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं । उन्होंने विश्व बैंक के अधिकारियों को स्वयं बुलाया और कहा कि शिमला शहर के पीने के पानी की विदेशी अनुदान की जो योजना हमने आपको दी है, आप उस पर तुरंत पहली किस्त जारी कीजिए। ...(व्यवधान).... हम कहां इन्कार कर रहे हैं कि नहीं पहुंची। लेकिन यह परियोजना पहुंचने पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने संज्ञान लिया, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले। हिमाचल प्रदेश सरकार के अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट को इसकी पहली किस्त दिसम्बर से पहले जारी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हम इस काम को समयबद्ध सीमा में करेंगे। इस काम को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ।

आज इस प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इनसे निपटने के लिए पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'जलवायु परिवर्तन' को ले करके एक स्टेटमैंट पड़ी है। ...(व्यवधान)....अग्निहोत्री जी, हम आपकी पीठ किस बात के लिए थपथपायें कि आपने विश्व बैंक परियोजना को लटकाया या आपने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, इस बात के लिए पीठ थपथपायें। ...(व्यवधान)....

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप बोलिए। ...(व्यवधान)....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः छः महीने की माफी हम मांगते हैं। आप (विपक्ष) पांच साल की माफी मांगो।

शिक्षा मंत्रीः आपने (विपक्ष) शिमला की जनता को सारा सीवरेज़ वाला पानी पिलाया, यह आपके समय में हुआ है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप शिमला के तीन बार से विधायक हैं तो यह सीवरेज़ वाला पानी आपने पिलाया होगा।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप वाईंड-अप करें।

28-08-2018/1640/NS/YK/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आज यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई आरोप या प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह हमारा सामूहिक दायित्व है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। यह इस तरफ या उस तरफ का नहीं है। यह हमारा सामूहिक दायित्व बनता है और यह एक सांझा प्रयास है। इस सांझे प्रयास में जहां हमें आपकी मदद लेनी है तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना और आग्रह करेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। हम माननीय अनिरूद्ध सिंह जी, माननीय विक्रमादित्य सिंह जी और नेता विपक्ष से चाहेंगे कि आप सकारात्मक सोच को ले करके हमारे साथ चलें।

अध्यक्षः जिन्होंने इस प्रस्ताव को मूव किया है, वे दोनों यहां से चले गये हैं। माननीय अनिरूद्ध जी तो पहले ही चले गये थे, अब दूसरे माननीय सदस्य भी चले गये हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः इसलिए अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की सरकार के प्रयास और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास और इनके मार्गदर्शन में पूरी टीम एकजुट हो करके काम कर रही है। अधिकारियों की टीम काम पर लगी हुई है। मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि हम एक स्कीम अगले वर्ष गर्मी से पहले तैयार करेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्कीम को भी टाइम बाउंड करेंगे और समय रहते हुए शिमला जो हमारी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। शिमला हमारे प्रदेश की राजधानी है और शिमला के कारण हमारी पहचान न केवल देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। मेरे मित्रों ने जो सुझाव दिये हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। ...(व्यवधान)....

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

28.08.2018/1645/RKS/YK-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री... जारी

अग्निहोत्री जी मेरे मित्र हैं, इन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनको मुंह की खानी पड़नी थी। इस कारण इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमलाः171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः28 अगस्त, 2018 **सचिव।**